

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

कार्यालय

मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

(मैनुअल संख्या-05)

खण्ड-2

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

कार्यालय

मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

(मैनुअल संख्या-05)

खण्ड-2

मैनुअल संख्या	मैनुअल का नाम	पृष्ठ संख्या
05	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	01 से 176

अनुक्रमणिका

क्रम सं०	शासनादेश संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	2408/राजस्व/2001 दिनांक 28 सितम्बर, 2001	उत्तरांचल में मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय का गठन	4 से 6
2	1162/30(2)/2005 दिनांक 07 मई, 2005	सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी नियमों का अनुपालन।	7 से 8
3	1243/30(2)/2005 दिनांक 12 मई, 2005	अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण	9 से 10
4	1887/30(2)/2005 दिनांक 05 जुलाई, 2005	अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण	11 से 14
5	122/18(1)/2006 दिनांक 09 जून, 2006	उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में नियमित संग्रह अमीन, संग्रह चपरासी एवं सहायक वासिल वाकी नवीस के पदों का सृजन करने के सम्बन्ध में।	15 से 18
6	5453/2-संग्रह-57बी/88 दिनांक 23 मई, 1998	संग्रह अमीनों का वसूली हेतु वार्षिक मानक निर्धारण।	19
7	590/कार्मिक-2/ 2003-55 (26)/2002 दि० 13 मई 2003	उत्तरांचल सरकारी ड्राइवर सेवा नियमावली 2003	20 से 33
8		कमिशन आफिसर मिनिस्ट्रीयल सिर्विस रूल्स, 1980	34 से 43
9		उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय मिनिस्ट्रीयल सिर्विस रूल्स, 1980	44 से 58
10		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975	59 से 65
11	अधिसूचना संख्या- 3426/आई०बी०-1422-बी-53 दिनांक 09 मई, 1958	लेखपाल सेवा नियमावली, 1958	66 से 75
12	अधिसूचना संख्या- 84/2/(2)एफ/65 दिनांक 25.04.1965	सदर कानूगो सेवा नियमावली, 1968	76 से 79
13		अधीनस्थ कार्यालय मिनिस्ट्रीयल स्टाफ रूल्स, 1985	80 से 87
14		सर्विस कमिशन रेगुलेशन, 1954	88 से 95
15	संख्या-9403/1-ख-1099-ख-54 दिनांक 30 अगस्त, 1954	राजस्व लिपिक(रजिस्ट्रार कानूनगो और सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो) सेवा नियमावली, 1958	96 से 100
16		Promotion by selection in consultation with public service commission (Procedure) Rules, 1970	101 से 108

17		तहसीलदार सेवा नियमावली, 1966	109 से 113
18		नायब तहसीलदार सेवा नियमावली, 1944	114 से 127
19		कलेक्शन अमीन सेवा नियमावली, 1974	128 से 136
20		Revenue, consolidation (Higher) service Rules, 1992	137 से 142
21		अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (सुपरवाइजर कानूनगो) सेवा नियमावली, 1977	143 से 155
22	84-1(2)/65-राजस्व-698 दिनांक 19 मार्च, 1983	अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (पेशकार) सेवा नियमावली, 1983	156 से 167
23		Consolidation Department Ministerial and Drawing Staff Service Rules, 1980	168 से 176

उत्तरांचल शासन
भूमि संसाधन शाखा (राजस्व विभाग)
संख्या-2408/राजस्व/2001
दहरादून: दिनांक 26 सितम्बर, 2001

कार्यालय जाग

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन 2000) की धारा-87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय लोकनलिक प्रभाव से पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत राजस्व पारंपद के अधीन पर उत्तरांचल में मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय 11 मंजूर एवं स्वयं के अधीन निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदा एवं व्यवसायों की संख्या स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	पतनमान
1	मुख्य राजस्व आयुक्त	1	रु० 22,400-24,500 / -
2	मुख्य राजस्व आयुक्त के स्टाफ अधिनियम	1	रु० 6,500-10,500 / -
3	व्यक्तिगत सहायक	1	रु० 5,500-9,000 / -
4	आशुलिपिक-सह डाटा इंटी आपरेटर	1	रु० 4,000-6,000 / -
5	डाइवर	1	रु० 3050-4590 / -
6	चपरासी	2	रु० 2550-3,250 / -
7	प्रशक्कर	1	रु० 5,500-9,000 / -
8	अहलमद	2	रु० 4,500-7,000 / -
9	न्यायालय चपरासी	1	रु० 2550-3,250 / -
10	अपर राजस्व आयुक्त	1	रु० 14,300-18,300 / -
11	आशुलिपिक-सह डाटा इंटी आपरेटर	1	रु० 4,000-6,000 / -
12	डाइवर	1	रु० 3050-4590 / -
13	चपरासी	1	रु० 2550-3,250 / -
14	अधीक्षक	1	रु० 6,500-10,500 / -
15	प्रवर वर्ग सहायक सह डाटा इंटी आपरेटर	4	रु० 55,00-9000 / -
16	अवर वर्ग सहायक सह डाटा इंटी आपरेटर	2	4,500-7,000 / -

17	कार्यालय सहायक (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)	2	2,550-3,250 / -
18	वित्तीय अधिकारी	1	रु० 8,000-13,500 / -
19	लखादार सह डाटा इंट्री ऑपरेटर	2	रु० 5,000-8,000 / -
20	सहायक लखादार सह डाटा इंट्री ऑपरेटर	1	रु० 4,000-6,000 / -
21	कॅशियर सह डाटा इंट्री ऑपरेटर	1	रु० 4,000-6,000 / -
22	कार्यालय सहायक (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)	2	रु० 2,550-3,250 / -
23	डाटा इंट्री ऑपरेटर	2	रु० 5,000 / - (निर्धारित दिन)

2- मुख्य रूप से निम्न का निर्देश हुआ है कि मुख्य शक्तियों आयुक्त शक्तों विभाग, न्यायिक विभाग, मु-अधिमहण विभाग, वन्दावरत विभाग के विभागाध्यक्षों से योग्य और उनके द्वारा निम्न कार्य सम्पन्न किए जाएंगे :-

- 1- एसिसमेंन्ट एण्ड कलैक्शन आफ लेण्ड रयन्स।
- 2- मन्टीनन्स आफ लेण्ड रिकार्ड्स।
- 3- सर्वे, सिटिलमन्ट एण्ड रिकार्ड ऑपरेशन।
- 4- एवाल्यूशन आफ जमीनदारी एण्ड रिलीफ ऑन लेण्ड डायरेक्ट्स।
- 5- कन्सालिडेशन आफ डायरेक्ट्स रजिस्ट्रेशन एण्ड डायरेक्टर फॉर कन्सालिडेशन।
- 6- रवेन्यू ज्युडिसरी।
- 7- लजिसलेशन कलैक्टड बिद एग्रीकल्चरल डायरेक्ट्स।
- 8- रिलीफ ऑन एग्रीकल्चर ऑफ नचुरल कल्वाइमेटोज।
- 9- लोनस फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (नकली)।
- 10- लार्ज लेण्ड डायरेक्ट्स टक्स।
- 11- कालोनाईजेशन।
- 12- कोप एण्ड सीजन रिपोर्ट एण्ड रनफॉल स्टेटिस्ट्स।
- 13- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स एण्ड दियर रिबीजन।
- 14- एक्वीजिशन ऑफ लेण्ड।
- 15- सर्वोडिनेट रवेन्यू सर्विस।
- 16- एडमिनिस्ट्रेशन आफ गवर्नमन्ट डस्टट्स।
- 17- एडमिनिस्ट्रेशन आफ गवर्नमन्ट डस्टट्स गान्स एक्ट
- 18- भूदान एण्ड ग्रामदान
- 19- अन्य कार्य जो समय-समय पर शासन द्वारा अधिसूचित अथवा आदेशित किए जाए।

- 3 - मुख्य राजस्व आयुक्त/अपर राजस्व आयुक्त का मुख्यालय देहरादून में होगा और सर्किट कोर्ट के रूप में उनके द्वारा न्यायिक कार्य पौड़ी एवं नैनीताल में किया जाएगा।
- 4- कम्प्यूटर चलान के लिए दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो जब तक कर्मचारियों को कम्प्यूटर पर प्रशिक्षित किया जाता है तब तक के लिए दो डाटा इंट्री ऑपरेटर संयत बतन रु0 5,000/- प्रतिमाह पर अधिकतम छः माह तक की अवधि के लिए रख जायेंगे।
- 5- इस संबंध में हान वाला व्यय वर्तमान विनोय वर्ष 2001-02 के आय व्यय के अनुदान संख्या-7 जल्हा शीर्षक-2052-099- मुख्य राजस्व आयुक्त के नाम उन्हा जायगा।

एस0क0दास
प्रमुख सचिव
राजस्व विभाग
उत्तरांचल शासन

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित वर सुधनाथ एवं आगराक प्रयोगाही वरु पांपन :-

- 1- मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
- 3- मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4- मुख्य राजस्व आयुक्त/अपर राजस्व आयुक्त उत्तरांचल देहरादून।
- 5- प्रमुख सचिव वन एवं सामा विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
- 6- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- समस्त सचिव, अपर सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
- 8- सचिव श्री राज्यपाल, उत्तरांचल देहरादून।
- 9- मुख्य निजरा आयुक्त एवं स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल नई दिल्ली।
- 10- आयुक्त, पूर्णगलन उत्तरांचल शासन लखनऊ।
- 11- महालखावर, उत्तरांचल सारन हिल्स इलाहबाद।
- 12- आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मंडल, पौड़ी/नैनीताल।
- 13- रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल।
- 14- रजिस्ट्रार, राजस्व परिषद, उ0प्र0 इलाहबाद।
- 15- निदेशक, सूचना एवं लाक संपर्क विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
- 16- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 17- निजी सचिव, मा0 विन एवं राजस्व मंत्री जी, उत्तरांचल।
- 18- कोषाधिकारी, देहरादून।
- 19- भूमि संसाधन शाखा (राजस्व विभाग) उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।

(सोहन लाल)
अपर सचिव
राजस्व विभाग
उत्तरांचल शासन

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिवगण,
उत्तरांचल शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 07 मई, ;

विषय-सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी नियमों का
से अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों से अनेक ऐसे प्रकरण शासन के आगे लाये जा रहे हैं जिनमें सरकारी सेवक लम्बी-लम्बी अवधि के लिए कार्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं। कुछ प्रकरणों में कर्मचारी अवकाश की पूरी अवधि के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं देते हैं और कुछ प्रकरणों में कर्मचारी अनेक वर्षों के लिए बिना अवकाश के गायब हो जाते हैं और वापस आने पर उनके विभाग द्वारा उन्हें सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के लिए लिया जाता है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि अनुपस्थिति की अवधि को नियमों के अन्तर्गत शिथिल करते हुए अस्वीकृत कर विनियमित कर दिया जाए। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग 2-4 के मूल नियम 18 के अनुसार 0 से अधिक की अनुपस्थिति पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के उपबन्ध लागू होते हैं, परन्तु अति मामलों में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी कार्यवाही न करके अनुपस्थिति की अवधि को विनियमित करने के प्रस्ताव जाते हैं। कार्य के प्रति उत्तरदायी होना प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व है। बिना सूचना के अनुपस्थित होना तथा अवधि तक अवकाश पर चले जाना जहां एक ओर कर्तव्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है, वहीं दूसरी ओर शासन कार्य प्रभावित होता है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं—

- (1) किसी कर्मचारी के बिना प्रार्थना-पत्र दिये अनुपस्थित हो जाने पर, उसे एक सप्ताह के अन्दर इसका नोटिस, उत्तर देने हेतु 15 दिन की अवधि निर्धारित करते हुए, जारी की जाए कि बिना प्रार्थना दिये अनुपस्थिति की अवधि में, उसे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति मानते हुए क्यों न उसको अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए तथा क्यों न उस अवधि का वेतन न दिया जाय। नोटिस प्राप्त बाद यदि सम्बन्धित सेवक द्वारा 15 दिन के अन्दर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध समयान्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये।
- (2) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 18 की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन जाए तथा बिना अवकाश के 05 वर्ष से अधिक अवधि की अनुपस्थिति के बाद अनिवार्य रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय और सम्बन्धित सरकारी सेवक को नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व उ के बिना सेवा में पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति न दी जाए।

2-कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्च
प्रमुख सचिव।

संक्रांकन संख्या 1162/XXX (2)/2005, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र लोहनी,
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 12 मई,

विषय-अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा इस बात पर सदैव बल दिया जाता रहा है कि कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों के निस्तारण में विलम्ब न किया जाय। शीघ्रता से निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों को निपटाया जाय। परन्तु यह में आया है कि ऐसे मामले बहुत लम्बे समय तक अनिर्णीत रहते हैं जिसके कारण कर्मचारी लम्बे अर्से तक निलम्ब रहते हैं और उनको शासन द्वारा बिना काम किये, जीवन निर्वाह भत्ते की अदायगी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

2-अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण एवं अनुश्रवण करने के लिए प्रत्येक विभाग एक रजिस्टर तैयार किया जायेगा जिसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार प्रविष्टियाँ की जायेंगी। इस रजिस्टर में प्रविष्टियाँ की जायें तथा 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर, तथा 31 दिसम्बर को विचाराधीन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उच्च अधिकारी को रजिस्टर में अंकित प्रविष्टियों से अवगत कराया जायेगा। समस्त अधिकारियों से यह अपेक्षा की है कि वे इस प्रकार का रजिस्टर अवश्य रखेंगे और विचाराधीन कार्यवाहियों से अपने अगले ज्येष्ठ अधिकारी के द्वारा उपरोक्तानुसार अवगत कराते रहेंगे।

3-वरिष्ठ अधिकारी अपने दौरों के समय इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उक्त रजिस्टर ठीक प्रकार चला जा रहे हैं या नहीं। उच्च अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि अपने दौरों के समय ऐसी कुछ कार्यवाहियों की जांच करें कि निर्धारित प्रक्रिया तथा समय-सारिणी का ठीक-ठाक पालन हो रहा है या नहीं।

4-शासन द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के समय से निस्तारण हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है। के लिये समय-सारिणी नीचे दी जा रही है :-

- (1) अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में औपचारिक निर्णय की तिथि से 15 दिन के आरोप-पत्र जारी कर दिया जाये तथा उसे अपचारी कार्मिक को तामील कर दिया जाय;
- (2) आरोप-पत्र में अपचारी कर्मचारी से अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन से एक महीने के अन्दर करने को कहा जायेगा। किसी भी दशा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के लिये एक महीने से का समय नहीं दिया जायेगा;
- (3) अपचारी कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर जांच पूरी कर ली जाये जिसमें की परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा भी सम्मिलित हैं;
- (4) जांच अधिकारी की रिपोर्ट जहां वह स्वयं दण्डन अधिकारी नहीं है, शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत की साधारणतया यह रिपोर्ट जांच समाप्त होने के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दी जाये;

(5) जहाँ दण्डन अधिकारी जांच अधिकारी से भिन्न है, दण्डन अधिकारी जांच आख्या की प्रति आरोपित कार्मिक को प्रेषित करते हुए उसे यह निर्देशित किया जाये कि यदि जांच आख्या के सन्दर्भ में वह कोई अभिकथन देना चाहता है तो अपना प्रत्यावेदन 15 दिन से एक माह के भीतर प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी आरोप के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा आरोपित कर्मचारी को दोष सिद्ध न पाया हो परन्तु दण्डन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि आरोपित कार्मिक पर सिद्ध हो रहा है तो ऐसा मत स्थिर करने के कारणों सहित जांच आख्या की प्रति आरोपित कार्मिक को उपलब्ध करायेंगे;

(6) दण्डन अधिकारी अंतिम आदेश जारी करने से पूर्व जहाँ—

(क) लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है वहाँ जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के 6 सप्ताह के अन्दर लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाये। परामर्श प्राप्त होने के बाद 15 दिन के अन्दर अन्तिम आदेश जारी किये जायें,

(ख) लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अन्तिम आदेश जारी किया जाये।

5—मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक मामले में इस समय—सारिणी की जांच अधिकारी एवं दण्डन अधिकारी द्वारा दृढ़ता के साथ पालन किया जाये। यदि किसी मामले में इस समय—सारिणी का पालन सम्भव नहीं है तो उन कारणों को जांच अधिकारी द्वारा लेखबद्ध करना चाहिए। यदि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलम्ब होता है तो जांच अधिकारी एवं दण्डन अधिकारी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते हैं।

6—अतः आपसे अनुरोध है कि आप अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध समस्त अधिकारियों की जानकारी में उपरोक्त आदेश ला दें और यह निर्देश दे दें कि इनका कड़ाई से पालन किया जाये तथा निर्धारित रूप में रजिस्टर भी रखा जाये।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

संख्या 1243(1)/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 05 जुलाई,

विषय-अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण शीघ्र सुनिश्चित किया जाय। परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि सामान्यतया अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ व उसे पूरा करने में तत्परता नहीं बरती जाती है। बहुत से मामलों में वर्षों पुरानी घटनाओं/आरोपों के उ पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया जाता है। कई मामलों में अनुशासनिक कार प्रारम्भ करने के बाद लम्बे समय तक जांच कार्यवाही पूरी नहीं हो पाती है। विलम्ब से जांच करने में इस की सम्भावना रहती है कि सम्बन्धित आरोपों को सिद्ध कर सकने वाले साक्ष्य ही मिट जायें और दोषी सर सेवक दण्ड पाने से बच जायें। यदि जांच करने का निर्णय ही देर में लिया जाय, तो इस बीच सरकारी को वेतन वृद्धि, स्थायीकरण, पदोन्नति जैसे लाभ मिल चुके होने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही का कोई नहीं रह जाता है। जहां अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ होने के बाद लम्बे समय तक चलती है, वहां आ सरकारी सेवक के पदोन्नति आदि के मामले लम्बे समय तक लम्बित रखने पड़ते हैं, जिससे उनमें कुण्टा उ होती है और कैडर मैनेजमेन्ट में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः आवश्यक है कि अनुशासनिक कार्यवाही से की जाय और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार उसे पूरा कर लिया जाय।

2-यह भी देखने में आया है कि बहुत से मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय उ जल्दबाजी में या आवेश में आकर ले लिया जाता है और निर्धारित समय-सीमा में आरोप-पत्र तैयार नहीं हो पाता इस बात की छानबीन होती रहती है कि जो आरोप हैं उनमें किन नियमों/आदेशों की अवहेलना/उल्लंघन निर तथा उसे सिद्ध करने के लिए आरोप-पत्र में किन-किन साक्ष्यों का उल्लेख/समावेश किया जा सकता है। कुछ म में अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेते समय इस बिन्दु पर विचार नहीं किया जाता है कि संज्ञान में आये हुए यदि सिद्ध हो जायेंगे तो उनकी गम्भीरता को देखते हुए मात्र कोई लघु शास्ति देना ही तो पर्याप्त नहीं होगा अन्ततः सभी आरोप सिद्ध होने के बावजूद परिनिन्दा प्रविष्टि जैसा लघु शास्ति दिये जाने का निर्णय होता है, नियमानुसार लघु शास्ति देने के लिए आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होता है। स विभाग से जो जांच रिपोर्ट प्राप्त होती है, उसमें कई मामलों में लघु शास्ति दिये जाने की संस्तुति की जाती है, भी अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। ऐसे मामलों में जहां लघु शास्ति दिया जाना है, वहां अनुशास कार्यवाही प्रारम्भ करने से अत्यधिक समय नष्ट होता है और सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को कठिनाई का र करना पड़ता है। दूसरी ओर जो शास्ति समय के अन्तर्गत दी जा सकती है, उसमें विभागीय कार्यवाही कर उस श को वर्षों बाद देने से शास्ति लगभग प्रभावहीन हो जाती है और लघु शास्ति के पीछे जो सुधारात्मक दृष्टिकोण होता है, वह भी पूरा नहीं हो पाता है।

3-उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण शीघ्र सुनिश्चित करने तथा अनुशासनिक कार्यवाही की समय-सारिणी को अधिक प्रभावकारी और व्यवहारिक बना उद्देश्य से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

- (1) प्रत्येक दशा में, यथासम्भव, निलम्बन आरोप-पत्र बनाने के बाद ही किया जाय और जब भी किसी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेवक (कर्मचारी/अधिकारी) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाय तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा आरोप-पत्र तैयार कर अवश्य प्रेषित किया जाय।
- (2) नियंत्रक अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि अपचारी सरकारी सेवक को प्रशासकीय कार्यों में इस सीमा तक न लगाये रखें कि उसे यह कहने का मौका मिले कि वह अपने प्रशासकीय/शासकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण समय से उत्तर नहीं दे सका। यदि जांच पूर्व नियुक्ति के स्थान से सम्बन्धित है तो अपचारी सरकारी सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाय, जहां उसे अभिलेख आदि देखने हों।
- (3) निलम्बन एवं अनुशासनिक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजने से पूर्व आरोप-पत्र के साथ अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का उल्लेख स्पष्ट रूप से कर दिया जाय और अभिलेखीय साक्ष्यों की प्रतियां भी संलग्न कर भेजी जायें।
- (4) किसी सरकारी सेवक के निलम्बन का प्रस्ताव/रिपोर्ट भेजने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करने चाहिये कि वे उन आरोपों से सम्बन्धित सभी अभिलेख अपने पास रखें, जिनके आधार पर उन्होंने निलम्बन का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया है, ताकि जांच अधिकारी व अपचारी सरकारी सेवक को समय से वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जा सकें। यदि वे अभिलेख किसी अन्य मामले में वांछित हों, तो साक्ष्यों के लिये ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियां बनाकर प्रस्ताव करने वाले अधिकारी द्वारा अपने पास रख ली जायें।
- (5) समस्त कार्यालयों/अधिष्ठानों की मासिक समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों में विभागीय कार्यवाहियों की समीक्षा भी की जाय। यह समीक्षा जिला स्तर, मण्डल स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर तथा शासन स्तर पर की जाय।

6. सामान्यतः बहुत पुरानी घटनाओं, जब तक कि उनमें कोई गम्भीर दुराचरण या शासन को आर्थिक क्षति का मामला निहित न हो, के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही/जांच प्रारम्भ न की जाये।

अध्यक्ष पुराने घटनाओं के सम्बन्ध में जांच कार्यवाही

7. किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप संज्ञान में आने पर, शास्ति देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि क्या आरोपों के सिद्ध होने पर भी मात्र लघु शास्ति दिया जाना ही पर्याप्त होगा? यदि हां तो आरोप-पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिये जाने के बजाय, यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण लेकर, निम्नलिखित क्रिया अपनाई जाय :-

लघु शास्ति देने की प्रक्रिया

- (क) यदि परिनिन्दा प्रविष्टि या वृद्धि का औचित्य पाया जाय तो शास्ति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आरोपों व उन्हें सिद्ध करने वाले साक्ष्यों आदि का उल्लेख करते हुए सीधे ही दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश जारी कर दिया जाय;
- (ख) यदि उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य लघु शास्ति (डिसमिसल, रिमूवल, प्रत्यावर्तन, जो वृहत् दण्ड है, को छोड़कर) देने का औचित्य हो, तो अधिकतम तीन सप्ताह का समय देते हुए आरोपित सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण मांगा जाय तथा स्पष्टीकरण प्राप्त होने या स्पष्टीकरण देने की अवधि बीतने के दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश पारित कर दिया जाय।
8. (1) जहां नियुक्ति प्राधिकारी का आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए यह विचार हो कि यदि आरोप सिद्ध हो जायेंगे तो वृहद् शास्ति देने का औचित्य होगा, तो दो सप्ताह के भीतर आरोप-पत्र जारी कर दिये जायें।
- (2) प्रत्येक दशा में यथा सम्भव, निलम्बन आरोप-पत्र बनाने के बाद ही किया जाय और जब भी किसी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेवक (कर्मचारी/अधिकारी) के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही प्रस्तावित की जाय, तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा आरोप-पत्र तैयार कर अवश्य प्रेषित किया जाय।
- (3) आरोप-पत्र में आरोपित सरकारी सेवक से एक माह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय तथा अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में स्पष्टीकरण के लिए

दीर्घ शास्ति देने की प्रक्रिया

अनधिक एक माह का और समय दिये जाने पर विचार कर लिया जाय परन्तु इ हेतु किसी भी दशा में दो माह से अधिक समय न दिया जाय। उक्त अवधि स्पष्टीकरण दे सकने के लिए उसे पर्याप्त अवसर देने के उद्देश्य से सभी संग्रामिलेख आदि आरोप-पत्र के साथ ही संलग्न कर उपलब्ध करा दिये जायें। किसी भी यदि किसी अन्य अभिलेख को देखने की अनुमति देना आवश्यक हो तो उक्त तत्काल अवलोकित करा दिया जाय और यदि वे उसकी तैनाती से भिन्न स्थान पर उपलब्ध हो तो उसके लिए उसे दो सप्ताह के लिए उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाय, जहां अभिलेख उपलब्ध हो।

- (4) आरोपी सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद अधिकतम तीन माह के भीतर जांच अधिकारी द्वारा जांच की कार्यवाही, जिसमें गवाहों का परीक्षण प्रतिपरीक्षा भी शामिल है, पूरी कर ली जाय। इस अवधि में जांच पूरी करने के उद्देश्य से सुनिश्चित किया जाय कि जांच से सम्बन्धित स्थान पर तैनात अधिकारी को सामान्यतया जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। जहां यह सम्भव न हो वहां उक्त स्थान से निकटतम स्थान पर तैनात अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। जांच अधिकारी वैयक्तिक नाम के बजाय केवल पदनाम से नियुक्त किया जाय ताकि उनके स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति आदि के अवसर पर नये जांच अधिकारी को नियुक्ति की आवश्यकता न हो।
- (5) यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वयं जांच सम्पन्न न की गयी हो तो :-
 - (क) जांच अधिकारी द्वारा जांच समाप्त होने के दो सप्ताह के भीतर अपनी जांच आख्या नियुक्ति प्राधिकारी अनुशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाय।
 - (ख) जहां सेवा से पदच्युत, सेवा से हटाना किसी निम्नतर पद या श्रेणी या सम वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना या संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि रोकना में से कोई दीर्घ शास्ति प्रस्तावित हो तो जांच आख्या रिपोर्ट की प्रतिलिपि एवं उस पर अनुशासनिक अधिकारी अभिलिखित निष्कर्षों की प्रति आरोपित सरकारी सेवक को उपलब्ध कराते हुए आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाय कि वे इस पर अपना प्रत्यावेदन, यदि देना चाहें, दो सप्ताह के भीतर अनुशासनिक अधिकारी को उपलब्ध करा दें।
- (6) आरोपित सरकारी सेवक का अभ्यावेदन प्राप्त होने या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्धारित अवधि बीतने, जैसी भी स्थिति हो, के पश्चात् अगले दो सप्ताह के भीतर अनुशासनिक अधिकारी द्वारा समुचित शास्ति आदेश जारी कर दिया जाये। यदि उक्त सरकारी सेवक की नियुक्ति उस अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी हो जो उक्त दण्ड देते समय सम्बन्धित पद के नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च स्तर के हों, तो वह शास्ति के आदेश उस अधिकारी द्वारा ही जारी किये जायें जिसने उस सेवक को वास्तव में तत्समय नियुक्ति प्रदान की थी।
- (7) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार जांच आख्या एवं उस पर अनुशासनिक अधिकारी अभिलिखित निष्कर्षों की प्रति दिये जाने के अलावा कोई अन्य शो-काज नोटिफिकेशन दिये जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान के 42वें संशोधन के परिणामस्वरूप अब सेकेण्ड अपारच्युनिटी दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है।
- (8) जहां कोई शास्ति दिये जाने के लिए लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक हो वहां शास्ति आदेश पारित करने के पूर्व लोक सेवा आयोग को संदर्भ किया जाय और उनसे अधिकतम 06 सप्ताह के भीतर परामर्श प्राप्त किया जाये तथा परामर्श प्राप्त होने के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश पारित कर दिया जाये।

9. प्रत्येक विभाग में उपरोक्त समय-सारिणी को कड़ाई से लागू करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये जो अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेगा कि अनुशासनिक कार्यवाही

लिए निर्धारित समय-सारिणी का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। समय-सारिणी का पालन न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह सचिव स्तर पर आख्या प्रस्तुत की जायेगी और जिन प्रकरणों में विलम्ब दृष्टिगोचर हो, उसकी आख्या मुख्य सचिव स्तर पर भेजी जायेगी। प्रत्येक अनुशासनिक कार्यवाही का अनुश्रवण किया जायेगा जो कार्यवाहियाँ समय पर नहीं हो पायेंगी उनकी सूचना विभागाध्यक्ष, विभागों के सचिव व मुख्य सचिव स्तर पर उपलब्ध कराई जायेगी ताकि अनुश्रवण किया जा सके। सभी सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले मासिक बैठकों में भी अनुशासनिक कार्यवाही के निस्तारण में होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाये और एक अभियान चलाकर सभी लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णयों से, अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध समस्त अधिकारियों को कृपया अवगत करा दें और यह निर्देश दे दें कि संदर्भित समय सारिणी/उपरोक्त निर्णयों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

संख्या 1887 (1)/XXX(2)/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ (पौड़ी/नैनीताल) उत्तरांचल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र लोहनी,
संयुक्त सचिव।

संख्या: 122/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक 09 जून, 2006

विषय:—उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में नियमित संग्रह अमीन, संग्रह चपरासी एवं सहायक वासिल बाकी नवीस के पदों का सृजन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल मिसलेनियस रिट याचिका संख्या-9557 ऑफ 1997 उमराव सिंह रावत एवं अन्य बनाम जिलाधिकारी, नैनीताल एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 16-7-1997 को पारित करते हुये राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था कि सीजनल अमीनों एवं चपरासियों के पदों के सृजन पर जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा की गई संस्तुति पर विचार करें और तब तक याचीगणों को नियमित अमीन की भाँति वेतन आदि का भुगतान करने एवं उनकी सेवायें बिना कृत्रिम व्यवधान दिये जारी रखी जायें।

2— नियमित संग्रह कर्मचारियों यथा— संग्रह अमीन, संग्रह चपरासी, सहायक वासिल बाकी नवीस के नियमित पदों का सृजन मुख्य देयों की मांग के सापेक्ष किया जाता है। विविध देयों की वसूली के लिये सीजनल संग्रह कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति जनपद में इन देयों की मांग के अनुरूप तीन माह के लिये वर्ष में दो बार मण्डलायुक्तों द्वारा दी जाती है। इन देयों की वसूली के विरुद्ध बाकीदार से 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि वसूली व्यय के रूप में प्राप्त की जाती है। इसमें से वसूली प्रमाण पत्र के सापेक्ष प्राप्त धनराशि सम्बन्धित संस्था को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दी जाती है एवं वसूली व्यय में प्राप्त 10 प्रतिशत धनराशि राजकोष में जमा हो जाती है। इन देयों में मुख्य रूप से बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विद्युत निगमों, जलसंस्थान आदि की अवशेष वसूली की धनराशियाँ होती हैं, जिन्हें नियमानुसार भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने की शक्तियाँ जिलाधिकारी में निहित होती है।

.....(2)

3- पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य देयों की मांग जनपदों में नियमित अमीन के पद सृजित किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है। सीजनल संग्रह अमीन/संग्रह चपरासियों के नियमित पदों के सृजन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी नैनीताल एवं अन्य जिलाधिकारियों द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-9557/1997 उमराव सिंह रावत बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16-7-1997 का समादर करते हुये मुख्य देयों तथा विविध देयों की गत चार वर्ष की मांग के औसत के अनुक्रम में रु० 6.50 लाख प्रति अमीन प्रतिवर्ष को आधार मानते हुये राज्यपाल महोदय निम्नलिखित तहसीलों/जनपदों में सीजनल अमीनों (कुल 192 पद), संग्रह चपरासियों (कुल 192 पद) एवं ए०डब्ल्यू०बी०एन० (कुल 30 पद) के पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में सृजित किये जाने तथा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि या नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी, 2007 तक के लिये, इस प्रतिबन्ध के अधीन कि उनको बिना पूर्व नोटिस के पहले ही न समाप्त कर दिया जाये, बनाये रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	जनपद/तहसीलों का नाम	संग्रह अमीन संख्या/वेतनमान	संग्रह चपरासी संख्या/वेतनमान	सहा०वा०वा०न० संख्या/वेतनमान
1-	नैनीताल (तहसील धारी, नैनीताल, कोश्याकुटोली एवं बेतालघाट)	12 (रु०3200-85-4900)	12 (रु० 2550-55- 2660-60 - 3200)	2 (रु० 3050-75-3950-80 -4590)
2-	अल्मोड़ा	20 (तदैव)	20 (तदैव)	3 (तदैव)
3-	पिथौरागढ़	11 (तदैव)	11 (तदैव)	2 (तदैव)
4-	बागेश्वर	8 (तदैव)	8 (तदैव)	1 (तदैव)
5-	चम्पावत (तहसील चम्पावत, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट)	6 (तदैव)	6 (तदैव)	1 (तदैव)
6-	रुद्रप्रयाग	7 (तदैव)	7 (तदैव)	1 (तदैव)
7-	उत्तरकाशी	26 (तदैव)	26 (तदैव)	4 (तदैव)
8-	चमोली	11 (तदैव)	11 (तदैव)	2 (तदैव)
9-	टिहरी	31 (तदैव)	31 (तदैव)	5 (तदैव)
10-	देहरादून (चकराता, त्यूनी, एवं कालसी)	13 (तदैव)	13 (तदैव)	2 (तदैव)
11-	पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार को छोड़कर)	47 (तदैव)	47 (तदैव)	7 (तदैव)
	योग-	192	192	30

.....(3)

-3-

- 4- उपर्युक्त कर्मचारियों को उपरोक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हो, देय होंगे।
- 5- उपरोक्त पद निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जा रहे हैं:-
- (एक) शासनादेश जारी होने की तिथि से मण्डलायुक्तों को पद सृजित किये जा रहे जनपदों/तहसीलों में सीजनल संग्रह स्टाफ के पदों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार समाप्त हो जायेगा।
- (दो) अमीनों का पर्वतीय क्षेत्रों में वसूली का मानक रु0 6.50 लाख के स्थान पर रु0 8.00 लाख कर दिया जायेगा।
- (तीन) भविष्य में समय-समय पर वसूली का मानक प्रति अमीन इस तरह से निर्धारित किया जायेगा कि इन अशासकीय देयों की वसूली पर शासन को कोई धनराशि व्यय न करनी पड़े अथवा न्यूनतम धनराशि ही शासन को वहन करनी पड़े।
- (चार) सृजित किये गये पदों पर उन्हीं सीजनल कर्मचारियों का नियमितीकरण/नियुक्ति की जायेगी जिनकी मूल नियुक्ति उपरोक्त पर्वतीय तहसीलों/जनपदों में सीजनल कर्मचारी के रूप में हुई हो।
- (पाँच) सीजनल संग्रह अमीनों का नियमितीकरण उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974 (यथा संशोधित तथा उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के अधीन दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रथम बार शत प्रतिशत पदों को सीजनल संग्रह अमीनों द्वारा ही भरा जायेगा। यदि सीजनल संग्रह अमीनों में से आरक्षण सुनिश्चित नहीं हो पाता है तो आरक्षित अवशेष पदों को सीधी भर्ती से भरा जायेगा।
- (छः) इस शासनादेश द्वारा सृजित अन्य पदों पर भर्ती संगत सेवा नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।
- (सात) संग्रह चपरासी व ए0डब्लू0बी0एन0 के पदों को भरते समय भी आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (आठ) इन पदों पर नियमित किये गये कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति, त्याग पत्र अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर रिक्त पदों को तभी भरा जायेगा, जबकि तत्समय लागू वसूली के मानक के अनुरूप जनपद में पदों की आवश्यकता हो अन्यथा तत्समय लागू मानक से अधिक स्वीकृत पद निरस्त समझे जायेंगे।

..(4)



6- यह शासनादेश सिविल मिसलेनिय रिट याचिका संख्या-9557/1997 उमराव सिंह रावत बनाम जिलाधिकारी, नैनीताल एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-7-1997 के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

7- उक्त पदों पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुदान संख्या-6 लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-भू-राजस्व (मालगुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-204/वि0अनु0-5/2006 दिनांक 04 अप्रैल, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- 3- आयुक्त, कुमाँयू/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
- 4- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय उत्तरांचल।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

९

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व पोरबंद, उ०प्र०,
अनुभाग-२, लखनऊ ।

सेवा में,

- 1-समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०,
- 2-समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०,

संख्या 5453/2-संग्रह-57वीं/88 दिनांक: मई 23, 1998.

विषय: संग्रह अमीनों का वसूली हेतु वार्षिक मानक निर्धारण ।

महोदय,

संग्रह अमीनों द्वारा प्रातिवर्षीय प्राति अमीन का वसूली का मानक निर्धारित करने संबंधित पोरबंद के अ०सा०म०सं० 2363/2-संग्रह-57वीं/88 दि० 9 फरवरी 1994 का क्रमवा संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें मण्डलवार वसूली हेतु मानक निर्धारित किए गए हैं । इस संबंध में मुझे यह कानून का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में अमीन सोर्स में वेतन पर उभय होने वाली छनराशि के आधार पर प्राति अमीन संग्रह का मानक निर्धारित करने के लिए मैं पोरबंद एवं शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से संग्रह अमीनों की वार्षिक वसूली के लिए मानक निम्नानुसार रहेगा ।

1. नए अमीनों के लिए १० 10 लाख, प्राति वर्ष

2. पूर्ववर्ती व सुनियोजित अमीनों के लिए १० लाख, प्राति वर्ष

भवदीय,

21.2.2000

संख्या व दिनांक उपरोक्त;

अपर सचिव/अति.भू.उप.आयुक्त,
आर.एस.सक्सेना
कृते आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिनिधि उप सचिव उ०प्र० शासन राजस्व अनु०-7, लखनऊ को
उनके पत्र सं० 657/1-7/98-1068/93 दि० 27-4-88 के संदर्भ में सूचनाएं ।

आज्ञा से,

21.2.2000

अपर सचिव/अति.भू.उप.आयुक्त,
आर.एस.सक्सेना
कृते आयुक्त एवं सचिव।

उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 590/कार्मिक-2/2003-55 (26)/2002
देहरादून, 13 मई, 2003

अधिसूचना प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003

भाग-1

सामान्य

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली "उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003" कही जाएगी।
- सेवा की प्राप्ति 2. (2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- इन नियमों का लागू होना 3. किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।
- अध्यासोही प्रभाव 4. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।
- परिभाषा 5. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-
- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर के पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है;
- (ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
- (ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;
- (घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है;
- (ङ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 590/ Karmic-2/2003-55 (26)/2002, dated May 13, 2003 for general information :

No. 590/ Karmic-2/2003-55 (26)/2002
Dated Dehradun, May 13, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Government Department Driver's Service :--

THE UTTARANCHAL GOVERNMENT DEPARTMENT DRIVER'S SERVICE RULES, 2003

PART -- I General

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. (1) These Rules may be called the Uttaranchal Government Department Driver's Service Rules, 2003. | Short title and Commencement |
| (2) They shall come into force at once. | |
| 2. The service of Drivers in a Government department or office comprises group "C" posts. | Status of Service |
| 3. These rules shall apply to Drivers in a Government department or office under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution. | Applications of these rules |
| 4. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force. | Overriding effect |
| 5. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-- | Definitions |
| (a) "Appointing authority" means an authority empowered to make appointment to a post of Driver in a Government department or office, under relevant service rules or executive instructions, as the case may be ; | |
| (b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution ; | |
| (c) "Constitution" means the Constitution of India ; | |
| (d) "Government" means the Government of Uttaranchal ; | |
| (e) "Member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service ; | |

उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003

- (च) "सेवा" का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन गठित ड्राइवर सेवा से है;
- (छ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;
- (ज) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-2

संवर्ग

- सेवा का संवर्ग 6. प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या, उतनी होगी जितनी यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय-समय पर सरकार द्वारा, अवधारित की जाय।

भाग-3

भर्ती

- भर्ती का स्रोत 7. सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।
- आरक्षण 8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-4

अर्हताएं

- राष्ट्रिकता 9. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी—
- (क) भारत का नागरिक हो; या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या
- (ग) भारतीय उद्भव या ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्द्र, युगोस्लाविया और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जिजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा है कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

- (f) "Service" means the Service of Drivers in a Government department or office, constituted under relevant service rules or executive instructions, as the case may be ;
- (g) "substantive appointment" means an appointment not being an ad-hoc-appointment on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ;
- (h) "year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART -- II

Cadre

6. The strength of the Service in each Government Department or office shall be such as may be determined by the Government from time to time under the relevant Service Rules or executive instructions, as the case may be. Cadre of Service

PART -- III

Recruitment

7. Recruitment to a post in the Service shall be made by direct recruitment. Source of recruitment
8. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment. Reservation

PART -- IV

Qualifications

9. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be -- Nationality
- (a) A citizen of India, or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India ;
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided also that if a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

आयु

10.

सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित या अधिसूचित की जायें पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और पैंतीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

प्राविधिक और
शैक्षिक अर्हताएं

11.

सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :-
(एक) किसी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;
और

(दो) यथास्थिति भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस नियम 16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

अधिमानी अर्हता

12.

अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी की सेवा में अधिमान दिया जायगा, जिसने-

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो;

(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

चरित्र

13.

सेवा में भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्रधिकारी द्वारा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम निकाय द्वारा पदव्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र होंगे।

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

NOTE -- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty-one years and must not have attained the age of more than thirty-five years on the first day of the year of recruitment in which vacancies are advertised or notified ? Age

Provided that the Upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. A candidate for direct recruitment to the service must -- Technical and academic qualifications
- (i) have passed class VIII examination from a recognised educational institution ; and
 - (ii) possess a valid driving licence for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years preceding the date on which vacancy is notified to the employment exchange under rule 16.

12. A candidate who has -- Preferential qualification
- (i) passed High School examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or Uttaranchal Shiksha & Pariksha Parishad ;
 - (ii) knowledge of vehicle mechanism ;
 - (iii) served in the territorial army for a minimum period of two years ;
- shall, other things being equal, be given preference in the matter of recruitment to the service.

13. The character of a candidate for recruitment to the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. Character
The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE -- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or a Local authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall be ineligible for recruitment to the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

हिक प्रास्थिति

14.

सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 15.

किसी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड-बुक, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

भाग-5

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का
अवधारण

16.

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और वह प्रमुख समाचार-पत्रों में रिक्तियों को विज्ञापित भी करायेगा।

सीधी भर्ती की
प्रक्रिया

17. (1)

सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

अध्यक्ष

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;

सदस्य

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी;

सदस्य

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हों तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

सदस्य

(चार) (1) संबंधित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो।

14. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for recruitment to the Service : Marital status

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

15. No person shall be appointed to service by direct recruitment unless be in good mental and bodily health and free from all physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment to the service, he shall be required to produce a certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand-book, Volume II, part III. Physical fitness

PART -- V

Procedure of Recruitment

16. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other categories under rule 8. The appointing authority shall, notify the vacancies to the Employment Exchange in accordance with the rules and orders of the Government for the time being in force, and he may also advertise the vacancies in the leading newspapers. Determination of vacancies

17. (1) For the purpose of direct recruitment there shall be constituted a selection committee comprising -- Procedure for direct recruitment

(i) Appointing authority ;

Chairman

(ii) An officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe nominated by the appointing authority if the appointing authority does not belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe. If the appointing authority belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, an officer other than belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, to be nominated by the appointing authority ;

Member

(iii) Two officers nominated by the appointing authority, one of whom shall be an officer belonging to Minority Community and the other belonging to Backward Class. If such suitable officers are not available in his department or organisation, such officers shall on the request of the appointing authority be nominated by the concerned District Magistrate ;

Members

- (iv) (1) Regional Transport Officer of the concerned region or his nominee not below the rank of Assistant Regional Transport Officer. Member

(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिये बुलायेगा :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता एवं वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स की अवधि के आधार पर इतने आवेदकों को साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलायेगी जितना वह उचित समझे।

(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता को उनकी आयु के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग-6

नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आयें हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय।

परीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी।

(3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवाएं उप नियम (3) के अधीन समाप्त जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2) The applications received directly or through the Employment Exchange shall be scrutinised by the appointing authority who shall call for an interview and driving test to such persons as appear qualified under these rules :

Provided that for the purpose of direct recruitment the selection committee shall call such number of applicants on the basis of educational qualification and length of period of valid driving licence for interview and driving test as it may consider fit.

(3) The Selection Committee shall, after the interview and driving test, prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in interview and driving test. If two or more candidates obtain equal marks, the Selection Committee shall arrange their names in order of merit on the basis of their age of general suitability for the post. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of the vacancies. The selection committee shall forward the list to the appointing authority.

PART -- VI

Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

18. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 17. Appointment

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

19. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years. Probation

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, except in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, or has otherwise failed to give satisfaction his services may be dispensed with.

(4) A probationer whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

12

उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003

स्थायीकरण

20.

ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21.

ड्राइवर के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायगी।

भाग-7

वेतन आदि

वेतनमान

22.

सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23.

फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

भाग-8

अन्य विनियमन

पक्ष समर्थन

24.

सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों, चाहे मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25.

ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation if -- Confirmation

- (i) his work and conduct are found to be satisfactory ;
- (ii) his integrity is certified ; and
- (iii) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

21. The seniority of persons substantively appointed to the posts of driver shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servants Seniority Rule, 2002 as amended from time to time. Seniority

PART -- VII

Pay Etc.

22. The scale of pay admissible to a person appointed to a post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. Scale of pay
23. Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment into the time scale when has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and also confirmed : Pay during probation

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

PART -- VIII

Other Provisions

24. No recommendations, either written or oral, other than these required under these rules applicable to the Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature by other means shall disqualify him for appointment. Canvassing
25. In regard to matters not specifically covered by these rules, or by special orders persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State. Regulation of other matters

सेवा की शर्तों में
शिथिलता 26.

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अवमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

27.

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

26. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner. Relaxation in the conditions of service
27. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard. Saving

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,
Secretary.

CHAPTER XXV**The Commissioners Offices Ministerial Service Rules, 1980****Part I - General**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 54/2/1/65/Rev.-4, dated May 29, 1980.

No. 54/2/1/65/Rev.-4, dated May 29, 1980.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Commissioners Offices Ministerial Service.

1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called the Commissioners Offices Ministerial Service Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the service :- The Commissioners Offices Ministerial Service comprises group 'C' posts.

3. Definitions :- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

- (a) "appointing authority" means the Commissioner of the Division;
- (b) "Additional Commissioner" means the Additional Commissioner of a Division;
- (c) "Board" means the Board of Revenue, Uttar Pradesh;
- (d) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
- (e) "Commissioner" means the Commissioner of a Division;
- (f) "Commissioner's Office" includes the office of the Additional Commissioner;
- (g) "Constitution" means the Constitution of India;
- (h) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;
- (i) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
- (j) "Head of Department" means the Board of Revenue;
- (k) "Member of Service" means a person appointed in a substantive capacity under these rules of the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service; and
- (l) "year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year;
- ¹[(m) "Substantive appointment" means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the Cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules and if there are rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being, by executive instructions issued by the Government.]

1. Inserted by Notification No. 7422/1-4/86-305 B-486 dated 1-12-1986 with immediate effect.

Part II - Cadre

4. Cadre of service :- (1) The Ministerial posts in the office of each Commissioner shall form a separate cadre.

(2) The strength of the Cadre and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

(3) The strength of Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (2), be as given in Appendix I :

Provided that -

- (1) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, or
- (2) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part III - Recruitment

5. Sources of recruitment :- Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :

Category 'A'

Joint Assistant (Grade II)
Routine Clerk, Record
Keeper, Typist, Copyist
and Ahalmad.
(Rs. 200-300).

1. By direct recruitment and promotion of Group 'D' employees in accordance with the provisions of Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975 as amended from time to time.

Provided that Paid Apprentices appointed before the commencement of these rules will be absorbed in posts of category-A before appointments are made by direct recruitment and promotion.

Category 'B'

Junior Assistant (Grade I) and Reader in the Court of Additional Commissioner.
(Rs. 230-385).

2. By promotion from amongst permanent incumbents of the posts under Category 'A'.

Category 'C'

Senior Assistant and Sarishtedar (Rs. 280-450).

3. [By promotion from amongst the permanent incumbents of the posts under category 'B' in the Commissioners Office and the permanent Junior Clerks of the Collectorate of the concerned division working in this pay scale of Rs. 430-685.

Note :- For the purpose of promotion a Combined Seniority list shall be prepared by arranging the names of the eligible persons in order of seniority as determined from the date of their Substantive appointment in the pay scale of Rs. 430-685].

184

Revenue Service Rules in U. P.

Category 'D'Head Assistant
(Rs. 450-700)

4. ¹[By promotion amongst the permanent incumbents of the posts under category 'C' of the Commissioners Office and the permanent Senior Assistants of the Collectorate of the concerned division working in the pay scale of Rs. 470-735.

Note :- For the purpose of promotion a combined eligibility list shall be prepared by arranging the names of the eligible persons in order of seniority as determined from the date of their substantive appointment in the pay scale of Rs. 470-735]

Category 'E'

Stenographer to Commissioners (Rs. 400-600).

5. By promotion from amongst permanent stenographer to Additional Commissioner and permanent Camp Assistant in the scale of Rs. 300-500.

Category 'F'Stenographer to Additional Commissioner and Camp Assistant.
(Rs. 300-500).

6. By direct recruitment.

6. Reservation :- Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of Government in force at the time of recruitment.

Short Notes

If the Scheduled Caste and Backward Classes candidates are not available the post may be filled by candidate of general category. (Sharwan Kumar v. State of Haryana and others 1989 (1) SLR P&H 264)

1989 (1) SLR Bombay 289.

Part IV - Qualifications

7. Nationality :- A candidate for direct recruitment to a post in the service must be-

- (a) a citizen of India; or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

1. Substituted by Not No. 7422/1-4/86-305-13-4-86 dated 1-12-1986 with immediate effect.

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note :- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic and other qualifications :- A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the following qualifications :

Posts	Qualification
For the posts in category 'A'.	As prescribed in the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975 : Provided that in the case of the posts of typists a candidate must also possess a minimum speed of 25 words per minute in Hindi typewriting.
2. Stenographer and Camp Assistant.	(i) Must have passed Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto; and (ii) must have a minimum speed of 80 words per minute in Hindi shorthand and 30 words per minute in Hindi typewriting.

9. Preferential qualification :- A candidate who has-

- (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
 - (ii) obtained a 'B' certificate of the National Cadet Corps,
- shall, other things being equal be given preference, in the matter of direct recruitment.

10. Age :- (1) A candidate for direct recruitment to the post covered by the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975 must be within the age-limit laid down in the said Rules.

(2) A candidate for direct recruitment to posts not covered by sub-rule (1) must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 30 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January 1 to June 30 and on July 1 if the posts are advertised during the period July 1 to December 31 :

Provided that the upper age-limit in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Short Notes

Selection made in pursuance to the guidelines can not be held to be arbitrary, 1989
(1) SLJ Kerala 324.

11. Character :- The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note :- Persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital status :- A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical fitness :- No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III;

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part V - Procedure For Recruitment

14. Determination of vacancies :- The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled by direct recruitment shall be notified to the Employment Exchange in accordance with the rules and orders for the time being in force.

15. Procedure for direct recruitment to post of Junior Assistant, Grade II :- Subject to the provisions of rule 5, direct recruitment to the post of Junior Assistant Grade II shall be made in accordance with the procedure laid down in the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rule, 1976 as amended from time to time.

16. Procedure for direct recruitment to the post of Stenographer and Camp Assistant :- (1) For the purpose of direct recruitment to the post of Stenographer and Additional Commissioner and Camp Assistant there shall be constituted a Selection Committee comprising :

- (i) The Commissioner of the Division.
- (ii) The District Magistrate of the Headquarters of the Commissioner.
- (iii) The Staff Officer of the Commissioner.

(2) The Selection Committee shall scrutinize the applications and require eligible candidates to appear in competitive test and interview.

(3) After the marks obtained by the candidates in the written test have been tabulated, the Selection Committee shall have regard to the need for securing representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes

and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates as on the result of the written test, have come up to the standard fixed in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written test.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of merit, as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in the written test and interview. If two or more candidates obtain equal marks the candidates obtaining higher marks in the written test shall be the vacancies.

17. Procedure for recruitment by promotion to the post of Head Assistant :-

(1) Recruitment to the post of Head Assistant shall be made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, through the Selection Committee constituted under rule 16 (1).

(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority and place it before Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2), and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

18. Procedure for recruitment by promotion to the posts not covered by rule 17 :-

(1) Recruitment by promotion to the posts of different categories shall be made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit through the Selection Committee constituted under rule 16 (1).

(2) The appointing authority shall prepare categorywise eligibility lists of the candidates arranged in order of seniority and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such record pertaining to them as considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2) and if considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

Part VI - Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

19. Appointment :- (1) On the occurrence of substantive vacancies the appointing authority shall make appointment by taking candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 15, 16, 17 and 18 as the case may be.

(2) The appointing authority may make appointments in temporary and officiating vacancies also from the lists, referred to in sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointment in such vacancies from persons eligible for appointment under these rules but such appointment in the case of posts to which direct recruitment is made in accordance with the subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975 shall not last for a period exceeding six months and one year in respect of other posts, or till the next selection whichever is earlier.

20. Probation :- (1) A person on appointment to a post in the service in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that save for exceptional reasons the period of probation shall not be extended for more than one year and in no case beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

21. Confirmation :- A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if -

(a) his work and conduct are reported to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

22. Seniority :- Seniority in any category of post in the service shall be determined from the date of order of substantive appointment and where two or more persons are appointed together from the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that-

(i) the *inter se* seniority of persons directly appointed to the service shall be the same as determined at the time of selection.

(ii) the *inter se* seniority of persons appointed to the service by promotion shall be the same as it was in the substantive post held by them at the time of promotion.

Note :- (i) A candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons will be final.

(ii) Where the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is appointed substantively that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment. In other cases it will mean the date of issue of the order.

Part VII - Pay Etc.

23. Scales of pay :- (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are as follows :

Name of the post	Scale of Pay
Junior Assistant Grade II, Routine Clerk, Record Keeper, Copyist, Typist and Ahalmel in court of Additional Commissioner and Commissioner.	Rs. 200-5-250-E.B.-6-280-E.B.-8-320.
Junior Assitant grade I, Reader in the court of Additional Commissioner.	Rs. 230-6-290-E.B.-9-335-E.B.-10-385.
Senior Assistant, Sarishtedar	Rs. 280-8-296-9-350-E.B.-10-400-E.B.-12-450.
Head Assistant	Rs. 450-25-575-E.B.-25-700.
Stenographer to Commissioner	Rs. 450-20-500-E.B.-20-600.
Stenographer to Additional Commissioner	Rs. 300-8-340-E.B.-10-440-E.B.-12-500
Camp Assistant to Commissioner	Rs. 300-8-240-E.B.-10-440-E.B.-12-500

Short Notes

The above pay scale has been revised by the U. P. Pay Commission with effect from 1-1-1986.

24. Pay during probation :- (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed Departmental Examination and undergone training where prescribed and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also Confirmed.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rule :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

25. Criterion for crossing efficiency bar :- (1) No Head Assistant or Stenographer to the Commissioner shall be allowed to cross efficiency-bar unless he has worked diligently and to the best of his ability, his work and conduct have been found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

(2) A Person not covered by sub-rule (1) shall not be allowed to cross-

(i) the first efficiency-bar unless his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

- (ii) the second efficiency bar unless he has worked diligently and to the best of his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

Part VIII - Other Provisions

26. Canvassing :- No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post of service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

27. Transfers :- (1) Transfers from one post to another in the same office may be made by the Commissioner.

(2) Transfers from one Commissioners Office to another may be made by the Board and persons so transferred shall retain their lien in the parent cadre.

28. Regulation of other matters :- In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulation and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

29. Relaxation from the conditions of service :- Where the State Government is satisfied that operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rule applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

30. Saving :- Nothing in these shall rules affect the reservation or any other concession required to be provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

Appendix I
(See Rule 4 and 5)
Statement showing strength of Service and of each categories of posts in the Ministerial Establishment of Commissioner's
and Additional Commissioner's Office
Categories of posts

Name of division	Category 'A'		Category 'B'		Category 'C'		Category 'D'		Category 'E'		Category 'F'	
	No. of Posts	Tempo-Perma- nent	No. of Posts	Tempo-Perma- nent	No. of Posts	Tempo-Perma- nent	No. of Posts	Tempo-Perma- nent	No. of Posts	Tempo-Perma- nent	No. of Posts	Tempo-Perma- nent
1. Meerut	2	7	2	5	...	4	...	1	...	1	2	1
2. Agra	3	7	1	5	1	4	...	1	...	1	2	1
3. Allahabad	1	9	...	7	1	4	...	1	...	1	1	2
4. Faizabad	1	8	...	4	1	4	...	1	...	1	...	2
5. Garhwal	2	4	1	1	1	3	...	1	...	1	1	...
6. Gorakhpur	4	7	3	5	...	4	...	1	...	1	1	3
7. Jhansi	2	7	...	4	1	4	...	1	...	1	1	1
8. Kumaon	...	3	...	2	...	5	...	1	...	1	1	...
9. Lucknow	2	8	...	4	...	5	...	1	...	1	1	1
10. Rubelkhand	2	7	2	5	1	4	...	1	...	1	1	1
11. Varanasi	2	6	2	5	1	4	...	1	...	1	1	1
Grand Total	21	73	11	47	7	47	...	11	...	11	1	13

43

CHAPTER XXVI

The Uttar Pradesh District Offices (Collectorates) Ministerial Service Rules, 1980¹

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation notification no. 4749/1-4-80-445, B-4-62, dated October 13, 1980.

No. 4789/1-4-80-445-B-4-62 October 13, 1980 :- In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh District Offices (Collectorates) Ministerial Service :

Part I - General

1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh District Offices (Collectorates) Ministerial Service Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the Service :- The Uttar Pradesh District Offices (Collectorates) Ministerial Service is a non-gazetted service comprising Group XX 'C' posts.

3. Definitions :- In these rules, unless there is anything repugnant in subject context :

- (a) 'appointing authority' in the case of Office Superintendent means the Commissioner of the Division and in the case of all other posts means the District Officer of the District;
- (b) 'Board' means the Board of Revenue, Uttar Pradesh;
- (c) 'citizen' of India means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
- (d) 'Commissioner' means the Commissioner of a Division;
- (e) 'Constitution' means the Constitution of India;
- (f) 'District Officer' means the District Officer of a district;
- (g) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;
- (h) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;
- (i) 'Head of Department' means the Board of Revenue, Uttar Pradesh;
- (j) 'Member of Service' means a person appointed in a substantive capacity under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of the rules to a post in the Service; and
- (k) 'Year of recruitment' means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part II - Cadre

4. Cadre of Service :- (1) The strength of the service and of each category posts therein each district shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

¹ Published in U. P. Gazette, Part I-Ka, dated 7-2-1981.

(2) The strength of the Service and of in each category of posts therein each district shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix I :

Provided that

- (1) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; or
- (2) the Governor may create such additional permanent or temporary posts from time to time as he may consider proper.

Part III - Recruitment

5. Sources of Recruitment :- Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made district-wise from the following sources :

Category 'A'

Assistant Bill Clerk, Ahalmad, Naib Nazir (Grade II), Library Clerk, Assistant Routine Clerk, Assistant Revenue Clerk, Assistant Revenue Assistant (Grade III), Assistant English Record Keeper, Assistant Judicial Assistant (Grade III), Arms Forms-Keeper Appeal Ahalmad, Assistant Record Keeper, Arrangers, Weeders, Copyist, Assistant Local Bodies Clerk, Syaha Navees, Suits Clerk, Judicial Moharrir, Revenue Moharrir, Kurk Amin, Assistant Record Keeper (Indexer, Town Clerk, Typist, Land Acquisition Clerk, Assistant Excise Clerk, Stamp Clerk, Assistant Record Keeper (Revenue), Assistant Record Keeper (Judicial) Despatcher, Assistant Record Keeper, (Lekhpal), Political Pension Clerk, Local Bodies Clerk, Assistant Commissioner's Clerk, Cell Clerk, Junior Clerk, Assistant Session Clerk, Nazul Clerk, Assistant Moharrir (Judicial), Embossing Clerk, Junior Clerk, Freedom Fighters Clerk, Complaints Clerk, Assistant General Clerk, Small Saving Clerk, Honorary Court Clerk, Auction Clerk, Suits Clerk (Grade II), Land Record Clerk, Mutation Clerk, Assistant Record Keeper, Teleprinter Operator, Assistant Vasil Baqi Navis, Ceiling Clerk, Assistant Chief Revenue Accountant, Agriculture Income Tax Clerk, Government State Clerk, Moneylending Clerk, Finance and Revenue Clerk, Mela Clerk, Assistant Suits Clerk, Zileadar Government Estate and any other ministerial posts in the scale of pay Rs. 200-320.

By direct recruitment and promotion of Group 'D' employees in accordance with the provisions of the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975 as amended from time to time: Provided that subject to the provision of rule 6 where paid Apprentices were enlisted before the commencement of these Rules in accordance with the G.O. no. B-2876/IB-149B/59, dated August 16, 1961, they shall, if available, be considered for appointment to the post in Category 'A' before appointments are made by direct recruitment and promotion.

Category 'B'

Bill Clerk, Routine Clerk, Judicial Record Keeper, Arms Clerk, Excise Clerk, Naib Nazir, Local Bodies Clerk (Grade I), Stamp Clerk, Assistant Judicial Clerk (Grade II), Assistant Revenue Assistant, (Grade-II), Land Acquisition Clerk, Peshkar, General Clerk Senior, Senior Clerk (Freedom Fighters) Assistant English Record Keeper, Sub-Divisional Clerk, National Saving Scheme Clerk, Calamity Clerk, Land Records Peshkar, Record Keeper, Establishment Clerks, Flood Clerk, Suits Clerk (Grade I), Head Operator Teleprinter, Wasil Baqi Navis, Mines Clerk, Ceiling Clerk, Z.A.C. Clerk, Senior Accounts Clerk, Nazul Clerk and any other ministerial posts in the scale of pay Rs. 230-385.

By Promotion from amongst the permanent incumbents of the posts mentioned in Category 'A'.

Provided that for promotion to the post of Head Teleprinter Operator a candidate having the minimum speed of 40 words per minute in English type writing shall be given preference.

Category 'C'

Enquiry Clerk in the scale of pay of Rs. 250-425.

By promotion from amongst the permanent incumbents of the posts mentioned in Category 'B' :

Category 'D'

Senior Assistant which term includes Nazir, Judicial Assistant, Revenue Assistant, Revenue Record Keeper, English Record Keeper, Chief Revenue Accountant and any other ministerial post in the scale of pay of Rs. 280-460.

By promotion from amongst the permanent incumbents of the posts mentioned in Category 'B' and 'C' above.

Notes :- (1) For the purpose of promotion to the posts in Category 'D', a combined seniority list shall be prepared by arranging the name of Enquiry Clerk and thereafter the names of persons holding the posts in Category 'B', in order of seniority.

(2) Where a person is Selected both for the posts in Category 'C' and 'D', the person in category 'D' shall be first offered to the person in order of seniority.

Category 'E'

Office Superintendent (in the pay scale of Rs. 450-700).

By promotion from amongst the permanent incumbents of the posts in Category 'D'.

Category 'F'

(i) Stenographer-Grade II, (in the scale of Rs. 250-700).

By direct recruitment.

(ii) Stenographer, Grade I, (in the scale of Rs. 300-500).

By promotion from amongst the permanent Stenographers in the scale of Rs. 250-425, If suitable persons are not available for promotion the post may be filled up by direct, recruitment.

Short Notes

The above pay scale has been revised by the U. P. Pay Commission with effect from 1-1-1986, (See Chapter XXXVIII).

6. Reservation :- Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories, shall be made in accordance with the orders of the Government in force to the time of the recruitment.

Part IV - Qualification

7. Nationality :- A candidate for direct recruitment to a post in the service must be-

- (a) a citizen of India; or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of Permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government ;

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note :- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic Qualifications :- A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the following qualifications :

Post	Qualification
1. For the posts in Category 'A'	As prescribed in the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975 : Provided that in the case of the post of Typist, a candidate must also possess a minimum speed of 26 words per minute in Hindi typewriting : Provided further that for the post of Teleprinter Operator a candidate must also possess a minimum speed of 40 words per minute in English typewriting.

2. Stenographer (Grade I or II)

- (i) Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Governor as equivalent thereto; and
- (ii) a minimum speed of 80 words per minute in Hindi shorthand and 30 words per minute in Hindi typewriting.

9. Preferential qualification :- A candidate who has :

- (1) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
- (2) obtained a 'B' certificate of the National Cadet Corps shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10. Age :- (1) A candidate for direct recruitment to the posts in category 'A' shall be within the age limits prescribed in the Subordinate Offices Ministerial Staff (Recruitment) Rules, 1975.

(2) A candidate for direct recruitment to the posts of Stenographer must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 30 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made if the posts are advertised during the period January 1 to June 30 and on July 1 if the posts are advertised during the period July 1 to December 31 :

Provided that the upper age-limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. Character :- The Character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on the point.

Note :- Persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital Status :- A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the Service :

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical Fitness :- No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any Physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of Fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule, 10 and contained in Chapter III of the Financial Handbook Volume II, Para III :

Provided that a Medical Certificate of Fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Short Notes

Fundamental Rules, 10 as contained in Chapter III of the Financial Hand Book Volume II Part III is reproduced as under :

"Unless any other form of medical certificate is prescribed in the rules, regulations or instructions regulating recruitment to a particular service or post, a medical certificate of fitness for Government service shall be in the following form :"

"I do hereby certify that I have examined.....a candidate for employment in the.....department and cannot discover that he/she has any diseases (communicable or otherwise), constitutional weakness of bodily infirmity except.....do not consider this a disqualification for employment in the.....department.

The candidate's age according to his/her own statement is.....years and the appearance.....years.

Note :- When a candidate for appointment in a non-gazetted post is sent for medical examination the examining medical officer or board should in his or its presence obtain on the medical certificate the signature of candidate. These signatures should afterwards be verified by the head of the office with those in the service book. In the case of an illiterate person it will be sufficient to obtain his thumb and finger impressions on the certificate. In the case of a person for whom a service book is not maintained, the head of the office should verify the signature on the medical certificate with the signature of the candidate obtained in his presence.

A medical certificate of fitness shall not be required in the following cases :-

- (1) from a person appointed by the president of India.
- (2) from persons passed civil engineer students of the Thomson Civil Engineering College, Roorkee who have been examined and passed as fit by a medical board at Roorkee at the end of their third year in that college.
- (3) from a Government servant promoted from inferior to superior service ;
- (4) from persons appointed on the results of competitive examinations for which medical examinations by medical board is prescribed if they are appointed within six months of the date of which they are examined by the medical board;
- (5) from persons who have been examined and passed as fit by a medical Board before selection for training in the Superior Forest Service Course at the Indian Forest College, Dehra Dun;
- (6) from persons who have been examined and passed as fit by a Civil Surgeon before selection for training in the Forest Rangers' Course at the Indian Forest Rangers' College Dehra Dun;
- (7) from engineer officers in the Public Works Department who have been examined and passed fit by the Medical Board, Lucknow, on their first appointment to a gazetted post, whether permanent or temporary, unless at the time of confirmation it may be found necessary for any special reasons to require an officer to undergo a second medical examination.

Orders of the Governor regarding Subsidiary Rule 11

Once a person is asked to produce a medical certificate of fitness for entry into Government service and has actually been examined and declared unfit, it is not open to the appointing authority to use its discretion to ignore the certificate that has been produced.

Part V - Procedure for Recruitment

14. Determination of Vacancies :- The appointing authority shall determine and notify to the Secretary of the District Selection Committee of the Employment Exchange, as the case may be in accordance with the rules and orders for the time being in force, the number of vacancies to be filled during the course of the year and also number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

15. Procedure for direct Recruitment to the Posts in Category 'A' :- Direct recruitment to the post mentioned in Category 'A' in rule 5 shall be made in accordance with the procedure laid down in the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975 as amended from time to time.

16. Procedure for Direct Recruitment to the post of Stenographer :- (1) For purpose of direct recruitment to the posts of Stenographer, there shall be constitute Selection Committee comprising -

- (i) the District Officer of the District ;
 - (ii) two other officers of the District not below the rank of Deputy Collector to be nominated by the District Officer.
- (2) The Selection Committee shall scrutinize the applications and require eligible candidates to appear in a competitive test and interview.

Note :- The syllabus and procedure for competitive test is given in Appendix II.

(3) After the marks, obtained by the candidate in the written test, have been tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates as on the result of the written test, have come up to the standard fixed by the Committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written test.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of merit, based on the aggregate of marks obtained by them in the written test and interview. If two or more candidates obtain equal marks, the candidates obtaining higher marks in the written test shall be placed higher. The number of names in the list shall be large (but not larger by more than 25 per cent than the number of vacancies).

17. Procedure for Recruitment by Promotion to the posts other than the post of Office Superintendent :- Recruitment to the posts of Category 'B' 'C' and 'D' as Stenographer, Grade I mentioned in rule 5, shall be made on the basis of Seniority subject to the rejection of the unfit through the Selection Committee constituted under rule 16 (1).

(2) The appointing authority shall prepare categorywise eligibility list of the candidates arranged in order of seniority and place the list before the Selection Committee along with their character rolls and such records pertaining to them so may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of their character rolls and records referred to in sub-rule (2) and if it considers necessary it may also interview the candidates.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

18. Procedure for recruitment to the posts of Office Superintendent :- (1) Recruitment to the post of Office Superintendent in a District Office shall be made by promotion from amongst the permanent assistants of Category 'D' of that office on the basis of Seniority subject to the rejection of the unfit in the manner laid down hereinafter by a Selection Committee consisting of :

- (i) the Commissioner or the Division,
- (ii) the District Magistrate of the District where the vacancy has occurred, and
- (iii) one other senior officer not below the rank of Additional District Magistrate to be nominated by the Commissioner or the Division.

(2) For recruitment to the post of Office Superintendent, the Commissioner shall call for the names of the five senior most assistants of Category 'D' of the District where the vacancy is expected to occur. The names shall be arranged in order of seniority on the basis of dates of confirmation in the grade and selection by the Selection Committee shall be made from the list so prepared.

(3) The list alongwith the character rolls of the persons included in it and such other records pertaining to them as may be considered proper shall be placed before the Selection Committee.

(4) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the character rolls and record referred to in sub-rule (3) and, if it considers necessary, may also interview the candidates.

(5) The Selection Committee shall forward the name of the selected candidate to the appointing authority.

Part VI - Appointment, Probation Confirmations and Seniority

19. Appointment :- (1) On the occurrence of substantive vacancies, the appointing authority shall make appointments by taking candidates in the order in which they stand in the list prepared under rules 15, 16, 17 and 18 as the case may be.

(2) The appointing authority may make appointments in temporary and officiating vacancies also from the lists referred to in sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available he may make appointment in such vacancies from amongst the persons eligible for appointment under these Rules provided that such appointment in the posts included in Category 'A' shall not be made for a period exceeding six months or till the next selection whichever is earlier and in the remaining posts it shall not last for a period exceeding one year or till the next Selection whichever is earlier.

20. Probation :- (1) A person on appointment to a post in the Service in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted.

Provided that save for exceptional reasons period of probation shall not be extended for more than one year and in no circumstances beyond the limit of two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of period of probation or the extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service rendered in a officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of commuting the period of probation.

21. Confirmation :- A probation shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if :

- (a) his work and conduct are reported to be satisfactory,
- (b) his integrity is certified, and
- (c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

22. Seniority :- (1) Seniority in any category of posts in the Service shall be Districtwise.

(2) Seniority in any category of posts in the service shall be determined from the date of order of substantive appointment and where two or more persons are appointed together from the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that :

- (i) the *inter-se-seniority* of persons directly appointed to the service shall be the same as determined at the time of selection.
- (ii) the *inter-se-seniority* of persons appointed to the service by promotion shall be the same as it was in the substantive post held by them at the time of promotion.

Note :- (i) Where the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is appointed substantively that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment. In other cases it will mean the date of issue of the order.

(ii) A candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reason when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons will be final.

Part VII - Pay Etc.

23. Scales of Pay :- (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay in force at the time of the commencement of these rules are as follows :

Names of the posts	Scale of Pay
1. Posts mentioned in Category 'A' in rule 5	Rs. 200-5-250-E.B.-6-280- E.B.-8-320
2. Posts mentioned in Category 'B' in rule 5	Rs. 230-6-290-E.B.-9-335- E.B.-10-385
3. Posts mentioned in Category 'C' in rule 5	Rs. 250-7-285-E.B.-9-375- E.B.-10-425
4. Posts mentioned in Category 'D' in rule 5	Rs. 280-8-296-9-350- E.B.-10-400-E.B.-12-460

5. Office Superintendent	Rs. 450-25-575-E.B.-25-700
6. Stenographer Grade I	Rs. 300-8-324-9-360- E.B.-10-440-E.B.-12-500
7. Stenographer Grade II	Rs. 250-7-285-E.B.-9-375- E.B.-10-425

Short Notes

The above pay scales have been revised by the U. P. Pay Commission with effect from 1-1-1986. (See Chapter XXXVIII)

24. Pay during Probation :- (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed the Departmental Examination and undergone training where prescribed, and the second increment after two years service when he has completed the period of probation and is also confirmed;

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

25. Criteria for Crossing efficiency bar :- (1) No person holding any of the posts mentioned in category 'A' in Rule 5 shall be allowed to cross;

(i) i.e. first efficiency bar unless his work and conduct have been found to be satisfactory he possesses a minimum speed of 20 words per minute (25 words per minute in the case of typists) in Hindi typewriting and his integrity is certified ;

(ii) the second efficiency bar unless he has worked with diligence and distinct ability, he possesses a minimum speed of 20 words per minute (25 words per minute in the case of typists) in Hindi typewriting and unless his integrity is certified.

(2) No person holding any of the posts mentioned in category 'B' in Rule 5 shall be allowed to cross;

(i) the first efficiency bar unless his record of service shows that he has worked steadily with distinct ability and strict honesty and unless his integrity is certified ;

(ii) the second efficiency bar unless it is found that he is well acquainted with rules and regulations and he has worked with diligence and intelligence and unless his integrity is certified.

(3) No person holding any of the posts mentioned in category 'C' and 'D' in rule 5 shall be allowed to cross-

- (i) the first efficiency bar unless he has worked with efficiency and has knowledge of departmental Rules Manuals, Pension Rules and Financial Rules and unless his integrity is certified ;
- (ii) the second efficiency bar unless it is found that he is well acquainted with all departmental rules relating to financial matters and that he is able to put up good notes and drafts and unless his integrity is certified.

(4) No Office Superintendent shall be allowed to cross the efficiency bar unless his work and conduct during the last five years have been found to be satisfactory, his integrity is certified and it is certified that his control over the staff of the office was adequate and that he has capacity to supervise the work properly.

(5) No Stenographer in either of the two scales of pay shall be allowed to cross-

- (i) the first efficiency bar unless the officer with whom he is attached certified that his work and conduct as a stenographer have been satisfactory and unless his integrity is certified ;
- (ii) the second efficiency bar unless his record of service shows that he has worked steadily with distinct ability and strict honesty and unless integrity is certified.

Part VIII - Other Provisions

26. Canvassing :- No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

27. Transfers :- Transfer from one post to another in the same office shall be made by the District Officer. Transfer from one district to another in the same Division may be made by the Commissioner. Transfer from one Division to another may be made by the Board of Revenue or by mutual arrangement between the Commissioner of the concerned divisions with the approval of the Board of Revenue.

In making these transfers the general Policy laid down by the Government from time to time shall be followed.

28. Regulation of other matters :- In regard to matters not specifically covered by the rules or by special orders, Persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

29. Relaxation from the conditions of service :- Where the State Government is satisfied that the operation of any Rule regulating the conditions of service of persons appointed to this service causes undue hardship in any particular case it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to his case by order dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

30. Saving :- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

Appendix I
(See Rule 4)

Statement showing the number of posts in each category, in the ministerial Establishment of District (Collectorates) Office as on
1st January, 1978 Categories of Posts (See Not Below)

Name of district	Category 'A'		Category 'B'		Category 'C'		Category 'D'		Category 'E'		Category 'F'		Total
	No. of Posts	Temp. Permt.	No. of Posts	Temp. Permt.	No. of Posts	Temp. Permt.	No. of Posts	Temp. Permt.	No. of Posts	Temp. Permt.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Saharanpur	16	84	2	22	...	...	...	6	...	1	5	1	137
2. Muzaffarnagar	18	96	3	17	...	...	...	6	...	1	5	1	147
3. Meerut	5	104	...	22	...	1	...	6	...	1	5	1	145
4. Bulandshahr	16	99	2	16	...	...	...	6	...	1	5	1	146
5. Ghazipur	50	27	12	6	...	...	6	...	1	...	...	...	102
6. Bijnor	1	52	1	12	...	...	...	6	...	1	...	1	77
7. Aligarh	18	116	6	23	...	...	...	6	1	1	7	1	178
8. Mathura	10	84	2	22	...	...	...	6	...	1	5	1	131
9. Agra	16	99	8	24	...	1	...	6	...	1	7	1	162
10. Mainpuri	2	51	1	14	6	...	...	5	...	1	...	1	81
11. Etah	6	54	2	11	...	...	...	5	...	1	5	...	84
12. Bareilly	16	94	4	20	...	1	...	6	...	1	6	1	149
13. Budaun	3	87	1	17	...	...	...	5	...	1	6	1	121
14. Saharanpur	11	82	2	19	...	...	...	6	...	1	5	1	127
15. Sitabdi	12	52	2	15	...	...	...	6	...	1	4	1	93
16. Moradabad	12	111	4	24	...	...	...	6	...	1	7	1	166

17. Rampur	3	62	...	13	...	...	...	...	6	...	1	6	1	92
18. Farrukhabad	8	89	2	18	...	...	...	...	6	...	1	4	1	129
19. Etawah	13	72	2	17	...	...	...	...	6	...	1	5	1	115
20. Kanpur	16	146	5	29	...	...	...	...	6	...	1	7	2	213
21. Fatehpur	14	71	2	18	...	...	...	...	6	...	1	5	1	117
22. Allahabad	61	137	8	30	...	...	...	...	6	...	1	2	11	257
23. Jhansi	24	55	5	15	...	...	...	...	6	...	1	6	1	113
24. Lalitpur	13	18	4	3	...	...	...	...	...	1	...	4	...	46
25. Jalaun	16	61	2	17	...	...	...	...	6	...	1	1	5	109
26. Hamirpur	38	68	6	18	...	...	...	...	6	...	1	6	1	144
27. Banda	8	60	...	14	...	...	...	...	5	...	1	5	1	94
28. Varanasi	26	77	6	15	...	...	...	...	5	...	1	8	1	135
29. Mirzapur	10	41	3	13	...	...	...	...	5	...	1	4	1	78
30. Ghazipur	15	96	3	21	...	...	...	...	6	...	1	5	1	141
31. Ballia	25	78	2	15	...	...	...	...	6	...	1	3	1	131
32. Gorakhpur	22	130	5	24	...	...	...	...	6	...	1	5	2	196
33. Jaunpur	35	92	4	18	...	...	...	...	6	...	1	6	1	163
34. Basti	16	132	2	21	...	...	...	...	5	...	1	8	1	176
35. Azamgarh	16	104	...	16	...	...	...	...	5	...	1	7	1	150
36. Deoria	5	96	5	18	...	...	...	...	6	...	1	...	1	132
37. Lucknow	48	85	13	21	...	...	...	...	6	...	1	7	1	182
38. Unnao	28	79	2	18	...	...	...	...	8	...	1	5	1	142
39. Rae Bareilly	17	69	2	18	...	...	...	5	6	...	1	1	1	120
40. Sitapur	36	86	5	16	...	...	...	...	6	...	1	6	1	157
41. Hardoi	18	89	3	17	...	...	...	...	6	...	1	5	1	140

U. P. District Offices (Collectorates) Ministerial Service Rules, 1980

205

42. Kheri	9	29	4	11	...	...	...	6	...	1	1	4	65
43. Faizabad	43	81	4	17	...	1	...	6	...	1	5	1	159
44. Gonda	32	91	2	17	...	...	...	6	...	1	5	1	155
45. Bahraich	24	68	4	14	...	...	...	6	...	1	5	1	113
46. Sultanpur	45	77	2	16	...	...	...	6	...	1	5	1	153
47. Pratapgarh	18	60	2	14	...	...	...	6	...	1	4	1	116
48. Bara Banki	2	86	2	17	...	...	...	6	...	1	5	1	120
49. Naini Tal	36	60	10	23	...	...	...	6	...	1	7	3	146
50. Almora	4	54	1	12	...	...	...	5	...	1	4	1	81
51. Pithoragarh	17	35	5	9	...	...	...	6	...	1	6	1	80
52. Chamoli	5	25	2	8	...	...	1	5	...	1	4	1	52
53. Uttar Kashi	8	18	2	5	...	...	2	4	...	1	5	2	47
54. Tehri-Garhwal	11	34	5	10	...	...	...	7	...	1	4	1	72
55. Garhwal	17	46	1	12	...	...	...	6	...	1	3	1	87
56. Dehra Dun	7	41	2	16	...	...	...	7	...	1	3	1	78

Note :- Posts which are to be shown in each Category are indicated in the Annexure, please ensure that there is no mistake in this respect.
Temp. means Temporary and Permt. means Permanent.

Appendix II

(See Rule 16)

Syllabus of Competitive test for recruitment to the posts of Stenographer :

1. The competitive test shall consist of a written test and interview.
2. The subjects of the test and the maximum marks on each subject shall be as follows :

(a) Written test-

	Marks
(i) A test in Hindi stenography	100
(ii) A test in Hindi typewriting	50
(iii) A short test in Hindi and English composition	50

(b) Interview -

(i) Personality	25
(ii) General Knowledge and suitability for the post	25

3. (a) The test in stenography shall consist of a dictation in Hindi for 5 minutes at the rate of 80 words per minute. One hour will be allowed for transcribing and typing the shorthand record of the dictation. The passage will be selected with a view to testing the candidates not only on their speed in stenography but also in their knowledge of good Hindi. No candidate will be considered to have qualified for employment whose percentage of errors in the test exceeds five.

(b) Test in Hindi and English composition shall consist of a written examination for which one hour will be allowed and candidate will be required to write a letter or a short essay on a subject of general interest.

CHAPTER XXVII

The Class IV Employees Services Rules, 1975

Part I - General

1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called the Class IV Employees Services Rules, 1975.

(2) They shall come into force at once.

2. Application of these rules :- ¹[These rules shall apply to all Class IV (Now Group D) posts referred to in rule 6 in all the Subordinate offices as defined in clause (h) of rule 4].

Short Notes

Rule 2 has been substituted by Notification No. 27/2/1974 personnel (2) dated October 11, 1979.

3. Overriding effect of these rules :- In the event of any inconsistency between these rules and a specific rule or rules pertaining to any of the aforesaid posts in any department :

- (i) the provisions, contained in these rules shall prevail to the extent of the inconsistency in case the specific rules were made prior to the commencement of these rules; and
- (ii) the provisions contained in the specific shall prevail in case they are made after the commencement of these rules.

4. Definitions :- In these rules, unless the context otherwise requires :

- (a) "appointing authority" means the authority specified in a particular department to be the appointing authority in regard to any category or categories of posts to which these rules apply ;
- (b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be citizen of India under Part II of the Constitution;
- (c) "Constitution" means the Constitution of India;
- (d) "Establishment" means the class IV establishment on which the posts are borne;
- (e) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;
- (f) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
- (g) "High Court" means the High Court of Judicature at Allahabad, including its Bench at Lucknow;
- (h) "Subordinate Offices" shall refer to all the offices under the control of the Government excluding the Secretariate Offices of State Legislature, Lok Ayukt, Public Service Commission, High Court, Subordinate Courts under the control and the superintendent of the High Court, Advocate General and the establishments under the control of the Advocate General;
- "(hh) "Retrenched employee" means a person-
 - (i) who was employed on a post under the rule-making power of the Governor,
 - (ii) in permanent, temporary or officiating capacity.

¹ Substituted by Notification No. 27/2/1974-Personnel-2 dated 15-9-1982.

- (iii) for a total minimum period of one year, out of which at least three months service must have been continuous service,
 - (iv) whose service were or may be dispensed with due to reduction to, in or winding up the establishment, and
 - (v) in respect of whom a certificate of being a retrenched employee has been issued by the appointing authority;
- but does not include a person employed on *ad hoc* basis only;
- (i) "Year of recruitment" means the period of twelve months from the first day of July of a calendar year".

Comments

In rule 4, clause (h) has been substituted and new clause (hh) inserted Notifi. No. 27/2/1974-Personnel-2 dated 11-10-1979.

Part II - Cadre

5. Strength of Service :- The strength of a Class IV Establishment in a particular Department Office and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time :

Provided that the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any post or class of posts without thereby entitling any person to compensation :

Provided further that the Government in the Administrative Department may, in consultation with the Personnel Department and the Finance Department, create such permanent or temporary posts in any establishment from time to time as may be found necessary.

Part III - Recruitment

6. Sources of recruitment :- The sources of recruitment to the various categories of Class IV posts shall be as follows :

- | | |
|---|--|
| (a) Peon, Messenger, Chaukidar, Mail, Farrash, Sweeper, Waterman/Bhisti, Tindal, Thelaman, Fireguard, Record-Lifter and every other non-technical post (scale at the commencement of these rules is Rs. 165-215). | By direct recruitment. |
| (b) Peon-Jamadar (scale at the commencement of these rules is Rs. 170-225) | By promotion from amongst permanent peons. |
| (c) Daftri/ Book Binder/Cyclostyle Operator (scale at the commencement of these rules is Rs. 170-225). | By promotion from amongst qualified peons, Messengers and Farrashes. |
| (d) Farrash Jamadar (scale at the commencement of these rules is Rs. 170-225). | By promotion from amongst permanent Farrashes. |
| (e) Sweeper Jamadar (scale at the commencement of these rules is Rs. 170-225) | By promotion from amongst permanent Sweepers. |
| (f) Head Mail (scale at the commencement of these rules is Rs. 170-225). | By promotion from amongst permanent Malis. |

Provided that where no eligible candidate/suitable candidate is available for promotion to a particular posts which is required to be filled by promotion the post may be filled by direct recruitment.

Short Notes

The above scales of pay have been revised by the Pay Commission.

Part IV - Qualifications

7. Reservation :- Reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes dependents of freedom-fighters and other categories of candidates, if any, shall be in accordance with the orders of the Government for reservation in force at the time of recruitment.

8. Nationality :- A candidate for recruitment to a Class IV post must be-

- (a) a citizen of India, or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before January 1, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and such candidate can be retained in service after a period of one year only if he has acquired Indian Citizenship.

Note :- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

9. Age :- A candidate for the direct recruitment to a Class IV (now Group D) posts must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 30 years on the first day of January following the year in which the applications for recruitment are invited :

Provided that the upper age-limit shall, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, be greater by such number of years as may be specified.

Comments

Rule 9 is as substituted by Notifi. dated 11-10-1979 *ibid*.

10. Academic qualifications :- (1) A candidate for recruitment to the post of peon, messenger or cyclostyle operator must have passed at least Class V Examination.

(2) No education qualifications are required for any other category of post but preference will be given to a person who is educated or is at least able to read and write Hindi in Devanagari Script.

(3) No person shall be eligible for appointing to the post of Mali unless he is found to possess requisite knowledge pertaining to the work of a Mali and has good experience of that work.

(4) No person shall be eligible for appointment as Daftri/Book Binder unless he is found to possess requisite knowledge of book binding work and has good experience of that work.

(5) No person shall be eligible for appointment as cyclostyle operator or any other post requiring technical knowledge, unless he is found to possess the requisite technical knowledge, and has good experience pertaining to the particular job.

(6) A candidate for recruitment to each category of class IV post must know cycling :

Provided that the condition shall not be applicable to female candidates.

(7) A candidate who has served in the Territorial Army for a minimum period of two years shall, other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment to the Establishment.

11. Relaxation for ex-servicemen and certain other categories :- Relaxation if any from maximum age-limit, educational qualifications or/and any procedural requirements of recruitment in favour of the ex-servicemen, disabled military personnel, dependants of military personnel dying in action, dependants of Uttar Pradesh Government servants dying in harness and sportsmen shall be in accordance with the general rules or orders of the Government in this behalf in force at the time of recruitment.

11-A. [Expired].

Comment

By Notification dated 6-7-1977 commencing on the same date, for 3 years Rule 11-A was inserted for relaxation in case of retrenched employees on the lines of Rule 13-A of U. P. Subordinate Staff Ministerial Service (Direct Recruitment) Rules, 1975 which may please be seen. It has expired now and necessary provisions have been incorporated elsewhere.

12. Character :- The character of a candidate for direct recruitment must be such as to render him suitable in all respects for employment in the Establishment. It shall be the duty of the appointing authority to satisfy himself on this point.

Note :- Persons dismissed by the State Government, the Union Government or by any other State Government or a corporation owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be deemed ineligible.

13. Marital status :- A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to the Establishment :

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

14. Physical fitness :- No candidate shall be appointed to the Establishment unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment by direct recruitment he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 and contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III.

15. [Deleted by Notifi. No. 27/2/74 Karmik-2 dated 11-10-1979 *ibid*].

16. **Constitution of Selection Committee :-** For the purpose of recruitment to any post, there shall be constituted a Selection Committee as follows :

- (i) Appointing Authority ;
- (ii) An Officer to be nominated by the Appointing Authority ;
- (iii) District Harijan and Samaj Kalyan Officer and if there is no such officer an officer to be nominated by the District Officer.

Note :- The District Harijan and Social Welfare Officers or an officer nominated by the District Officer in his place shall ensure that the Government Orders regarding reservations are complied with in making selection.

Comment

Rule 16 is substituted by Notifi. dated 11-10-1979 *ibid*.

17. **Recruitment to be made every year :-** Selection for recruitment under these rules shall, subject to existence of vacancies, be made for all the subordinate offices in a district once within a year of recruitment :

Provided that a second or any subsequent recruitment may, keeping in view the requirements, also be made in a particular district or for a particular office/offices within a district.

18. [Deleted].

19. **Procedure for Selection :-** (1) The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of the vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other categories. The vacancies shall be notified to the Employment Exchange. The appointing authority may also invite application directly from the persons who have their names registered in the Employment Exchange. The names shall be placed before the Selection Committee.

(2) When the names both of the general candidates and Reserved candidates (for whom vacancies are required to be reserved under the orders of the Government), have been received by the Selection Committee it shall interview, and select the candidates for the various posts.

(3) In making selection the selection committee shall give weightage to the retrenched employees awarding marks in the following manner :

- (i) For the first completed year 5 Marks.
- (ii) For the next and every completed year of service. 5 Marks.

Provided that the maximum marks awarded to a retrenched employee under this sub-rule shall not exceed. 15 Marks.

(4) The number of the candidates to be selected will be larger (but not larger by more than 25 per cent) than the number of vacancies for which the selection has been made. The names in the select list shall be arranged according to the marks awarded at the interview.

20. [Deleted].

21. **Common List :-** When the names of selected candidates, both general and reserve have been received, the appointing authority shall arrange them in a common list, the first name to be from the list of the general candidates followed by the name of

212

Revenue Services Rules U. P.

the reserve candidate and so on. The select list of prepared shall hold good for a period of one year from the date of selection :

Provided that person selected in accordance with the procedure prescribed in the Class IV Employees Rules 1975, prior to the commencement of the Class I Employees (Third Amendment) Rules, 1979 shall be appointed in the vacancies available up to November 30, 1979 and thereafter it shall stand cancelled.

Comments

Rules 18 20 were deleted and Rules 19 and 21 substituted by Notifi. dated 11-10-1979 ibi. The date of commencement of the amendment rules referred to in the proviso is 11-10-1979.

Part VI - Promotion

22. Procedure of promotion :- (1) Criterion of promotion in respect of all the posts shall be seniority subject to the rejection of the unfit.

(2) Promotions shall be made within the same establishment from amongst eligible candidates through selection by the Departmental Selection Committee. The constitution of the Departmental Selection Committee which shall consist of three members shall be in accordance with the orders of the Head of the Department.

23. Appointment :- (1) On the occurrence of substantive vacancies the appointing authority shall make appointments from the list of candidates prepared under rule 21 of rule 22, as the case may be, in the which their names appear in the list.

(2) The appointing authority shall also make appointment in officiating and temporary vacancies from the said list and the manner referred to in sub-rule (1).

(3) When the list of selected candidates becomes exhausted or no candidate is available for appointment from out of the selected candidates, *ad hoc* appointment may be made by the appointing authority from amongst the eligible candidates;

Provided that no *ad hoc* direct appointment shall be made for a period exceeding six months.

24. Probation :- (1) A person on appointment to a post in the establishment in a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of one year :

Provided that continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post borne on the Establishment may be taken into account in computing the period of probation for that post :

Provided further that the appointing authority may, for reasons to be recorded extend the period of probation up to a specified date in individual cases.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during, or at the end of, the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, or if he does not hold a lien on any posts, his services may be dispensed with without entitling him to any compensation in either case.

Part VII - Confirmation

25. Confirmation :- A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation, as the case may be, if his work and conduct have been found to be satisfactory, the appointing authority considers him fit for confirmation and his integrity is certified.

26. Seniority :- Seniority of the members of the Establishment in each category of posts shall be determined according to the date of the order of substantive appointment in that category.

Explanation :- If two or more persons are appointed on the same date their seniority *inter se* shall be determined in the same order in which the appointments have been made.

Note :- A direct recruit may lose his seniority if he fails to join without sufficient reason when the post is offered to him. Whether the reasons in a particular case are sufficient or not will be decided by the appointing authority, whose decision shall be final.

Part VIII - Pay

27. Scale of Pay :- The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Establishment whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time.

28. Pay during probation :- (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall draw, during the period of probation, increments on the condition that his work is reported to be satisfactory; provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, the extended period shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person already in the permanent service of the Government shall be regulated by the relevant rules referred to in rule 32.

29. Criteria for crossing the efficiency bars :- No person shall be allowed to cross an efficiency bar unless he is found to have worked steadily and to the best of his ability, his conduct has been good and his integrity is certified.

30. Retirements :- The age of retirement of the various categories of class IV employee shall be according to the relevant rules/orders of the Government.

Part IX - Other Provisions

31. Canvassing :- No recommendation, either written or oral, other than those required under these rules will be taken into consideration, any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature by other means will disqualify him for appointment.

32. Regulations of other matters :- In regard to the matters not especially covered by these rules or by special orders, persons appointed to the establishment shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of Uttar Pradesh.

33. Relaxation from conditions of service :- Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Establishment cause undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

65

CHAPTER XVIII

Lekhpals Service Rules, 1958

Notification No. 3426/IB-1422-B-53

Dated, May 9, 1958

Preamble :- In supersession of all existing rules and orders on the subject and in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rules regulating the recruitment to, and the conditions of the service of Lekhpals.

1. Short title and commencement :- These rules may be called the Lekhpals Service Rules, 1958 and shall take effect from the date of the issue of the notification.

2. Status of Service :- The Lekhpal's service is a non gazetted subordinate service.

3. Definition :- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

- (a) "Assistant Collector" means the Assistant Collector Incharge of a sub-division.
- (aa) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution or a subject of Sikkim.
- (b) "Constitution" means the Constitution of India.
- (c) "Collector" means the Collector of the district.
- (d) "Director" of Land Records hereinafter called the Director means the authority for the time being exercising the powers of the Director of Land Records.

Note :- At present the Board of Revenue exercises the powers of the Director.

- (e) "Direct recruitment" means recruitment in the manner prescribed by Rule 5 of these rules.

Short Notes

Ministerial staff is made only after selection in accordance with the procedure prescribed in the statutory rules. Adhoc appointments are made in the interest of work when selected candidates are not available.

- (f) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh.
- (g) "Service" means the Lekhpal Service.
- (h) "Member of the service" means a person appointed to the service in accordance with the provisions of these rules or of rules or orders in force previous to the introduction of these rules.

4. Cadre :- (i) The strength of the service shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

(ii) The cadre of Lekhpals shall be district-wise and the district-wise allocation of strength will be made by the State Government.

(iii) The Assistant Collector may leave unfilled, or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation.

(iv) The Governor may create any additional, temporary or permanent post from time to time as may be found necessary.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), persons who belong to the category mentioned in paragraph 2 (3) (d) of Revenue (B) Department G. O. No. 4434/B, dated April 27, 1953, and are working in a temporary or officiating capacity, with or without break in service, shall be deemed eligible for appointment to the service.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), persons who belong to the category mentioned in paragraph 2 (3) (d) of Revenue (B) Department G. O. No. 4434/B, dated April 27, 1953, and are working in a temporary or officiating capacity, with or without break in service, shall be deemed eligible for appointment to the service.

(3) The ex-patwaris who had a good record of service and fulfil other qualifications and conditions prescribed for appointment shall also be eligible for appointment to the service.

(4) Ex-patwaris shall be treated as new candidates and shall not get the benefit of their past service in any matter.

(5) Ex-patwaris who have already been absorbed in the service shall be deemed to have been appointed under these rules.

6. Procedure for recruitment :- (1) For purposes of recruitment, the Collector shall maintain in the following form a list of candidates who have passed the Patwari or Lekhpal School Examination :

Year of passing the Patwari or Lekhpal School Examination	Total No. of marks obtained in the Examination with Division	Dates of officiating periods with remarks about work	Remarks
5	6	7	8

(2) Necessary material for the maintenance of this list shall be supplied each year, as soon as examination results are out, by the Collector in whose district the Lekhpal School is located. The Collector may, subject to the approval of the Director, add to the list so received the name of any other candidate who has passed the Patwari of Lekhpal School Examination.

(3) The names, in the list shall be arranged in order of seniority as determined by the year of examination. Seniority as between the candidates of the same year shall be judged on the basis of the aggregate marks obtained at the examination. Where the aggregate marks are equal, the seniority shall be determined on the basis of age.

¹(3-A) A district-wise list of ex-patwaris fulfilling the conditions laid down in sub-rule (3) of rule 5 shall be maintained by each Collector. The names in this list shall be arranged according to the length of service. If the length of service of two or more ex-patwaris is the same the names shall be arranged according to age.

Note :- If any list is already maintained in this behalf under executive orders of Government it shall be deemed to be maintained under this sub-rule.

(4) The lists referred to the examination and the Collector shall remove the names of-

- (a) Candidates who have received permanent appointment;
- (b) Other candidates for good and sufficient reasons to be recorded in writing;
- (c) Those candidates in the list prescribed in sub-rule (3) of rule 6 who have exceeded the maximum age-limit for appointment.

7. Appointment :- (1) Whenever posts of Lekhpal fall vacant, the Assistant Collector shall appoint thereto alternatively the senior-most candidate on each of the two lists maintained under rule 6. In case no candidate is available in the relevant list, the Assistant Collector may make the appointment from the other list :

Provided that the Assistant Collector may pass over any name or names for good and sufficient reasons to be recorded in writing :

Provided further that any person aggrieved by any order passed by the Assistant Collector under the first proviso may prefer an appeal before the Collector whose decision thereon shall be final.

(2) If a candidate does not accept the appointment, when offered, shall be passed over, and the next candidate in order of seniority shall be appointed. The candidate so refusing shall not be considered for appointment in any subsequent vacancy unless he furnishes good and sufficient reasons for his refusal to the satisfaction of the Assistant Collector. Any person aggrieved by the order passed by the Assistant Collector, may prefer an appeal before the Collector, whose decision thereon shall be final.

(3) When a district is under settlement or record operations or under operations for consolidation of holding, the Settlement or Record Officer or the Settlement Officer of the Consolidation, as the case may be, make a temporary appointment against a permanent vacancy pending the appointment of a permanent Lekhpal by the Assistant Collector.

8. Educational Qualifications :- The minimum educational qualification shall be Hindustani Middle or Junior High School Examination.

Note :- Under Education Department G. O. No. A. 6146/XV-3001 (3)-51, dated September 18, 1951, the Parthama, Purva Madyama (with English) and Shastri (With English) Examination conducted by the Government Sanskrit college, Varanasi have been recognized as equivalent, respectively, to the Junior High School (Class VIII

1. Suba. by Notification No. 7/2 (2)-F-66, dated 25-8-1969.

High School, Intermediate and B. A. Examinations for purpose of appointment to posts under the State Government.

9. Age :- Except in the case of ex-patwaris, a candidate for direct recruitment must not be less than 18 or more than 35 years of age on the date of order of appointment, provided that if a candidate is already officiating in a substantive capacity in an equivalent or higher post, under a Consolidation Scheme, Record Operations or Settlement Operations, he shall be eligible for appointment.

Note :- The Governor may order, declare any service as equivalent to that of Lekhpal for this purpose.

10. Reservation of seats for Scheduled Castes :- Reservation of Scheduled Castes, etc., shall be in accordance with the orders for reservation in force at the time of recruitment. (A copy of the orders in force on the date of the promulgation of these rules will be found in Appendix 'A')

11. Nationality :- A candidate for recruitment to the Service must be :

- (a) A citizen of India, or
- (b) A subject of Sikkim, or
- (c) A Tibetan refugee who came over to India before January 1 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (d) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylone and East African countries of Kenya: Uganda, Zanzibar, with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to a category (c) or (d) above shall have been a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided further that a candidate belonging to category (c) will also be required to obtain a certificate of eligibility-granted by Deputy Inspector-General of Police, Intelligence Branch, U. P.

Provided also that if a candidate belongs to category (d) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and such a candidate may be retained in service after a period of one year only if he has acquired Indian Citizenship.

Note :- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview conducted by the recruiting authority and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

12. Canvassing :- No recommendations for recruitment either written or oral will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his appointment or confirmation shall disqualify him.

13. Character :- The character of a candidate must be such as to render him suitable in all respects for employment in the service. It shall be the duty of the appointing authority to satisfy himself on this point.

14. Production of Medical Certificates :- No candidate shall be appointed as a member of the service, unless he is in good mental and bodily health and free from any

physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally appointed, he shall be required to furnish a medical certificate of health in accordance with the rules from under Fundamental Rule 10 and contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Vol. II, Part III.

15. Test of physical endurance :- A candidate shall not be confirmed as a Lekhpal unless he has obtained a certificate from the Assistant Collector that he can walk six miles in not more than 100 minutes.

16. Probation and Confirmation :- (a) All persons on appointment in or against a substantive vacancy in the service shall be placed on probation for a period of two years; provided that service rendered in an officiating or temporary capacity as Lekhpal if it is continuous and service in higher posts may be taken into account in computing the period of probation.

(b) The Assistant Collector may at his discretion extend the period of probation in individual case for a period not exceeding one year. Any such extension shall specify the exact date up to which the extension is granted.

(c) A probationer shall draw during the period of probation increments as they accrue on condition that his work has been reported to be satisfactory. If the period of probation is extended for failure to give satisfaction, the extended period shall not count for increments unless the Assistant Collector directs otherwise.

(d) Where it transpires at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a Lekhpal has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to acquaint himself satisfactorily, his services shall be terminated.

(e) The probationer shall be confirmed in his appointment by the Assistant Collector at the end of the period of probation or the extended period of probation if his work and conduct are found satisfactory. The period of probation shall continue till the order of confirmation is passed or the probation is terminated.

[17. Gradation List :- (1) There shall be single gradation list for the Lekhpals in the ordinary grade as well as in the selection grade. Seniority in the ordinary grade determined shall not be liable to any change subsequently upon appointment in the selection grade.

(2) **Seniority :-** Seniority of Lekhpals shall be determined from the date of substantive appointment provided that if two or more candidates are appointed on the same date, the seniority shall be determined from the date of their passing the Patwari or Lekhpals School Examination. If the year of passing the examination is the same, the seniority shall be determined on the basis of the aggregate marks obtained at the examination. If the aggregate marks are also equal the seniority shall be determined on the basis of age.

Exception :- In the case of Lekhpals recruited in 1953, as a result of reorganisation of the service of Patwaris, the list shall be arranged in the following order :

- (a) Patwaris absorbed as Lekhpals;
- (b) Fresh recruits holding the Patwari School Examination Certificate.
- (c) Fresh recruits not holding the Patwari School Examination Certificate.

Note :- The Lekhpals in group (a) shall rank *inter-se* according to their seniority immediately before the reorganisation of the service of Patwaris, those in group (b) according to the conditions laid down above in this sub-rule and those in group (c) according to the date of their substantive appointment, and in case in which the date of appointment and the date of substantive appointment are the same, according to their age.

18. Temporary vacancies :- (a) In temporary vacancies exceeding one month, candidates borne on the list maintained under paragraph 5 shall, as far as possible, be appointed in accordance with their seniority.

(b) In the case of vacancies not exceeding one month, or in vacancies exceeding one month for which a qualified candidate is not available, the Assistant Collector may appoint an unqualified candidate provided that he is satisfied that the candidate is otherwise suitable for the job.

19. Pay :- (a) The scale of pay admissible to a person appointed to a post in the service whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure shall be Rs. 75-2-85 E. B.-2-97-E. B.-3-115. Fifteen per cent of the posts in each district shall carry the selection grade of Rs. 80-3-95 E. B.-3-110-E. B.-3-125-E. B.-3-140. The Lekhpals shall be placed in selection grade on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.

Note :- (a) The rate of dearness allowance shall be in accordance with the orders of the State Government for the time being in force.

(b) Promotion to the selection grade will be made by the Collector himself with an appeal to the Commissioner, whose orders shall be final.

Note :- In calculation percentages, fractions will be rounded off to the nearest whole number.

Criterion for crossing the efficiency bars (b) "No member of the Service shall be allowed to cross any efficiency bars unless his record of Service shows that he has worked steadily with ability and honestly, and he also possesses executive tract and ability and can undertake touring in rural areas."

Short Notes

The above pay scale has been revised by the U. P. Pay Commission with effect from 1-1-1986. (See Chapter XXXVIII)

20. Rewards :- Rewards may be granted to deserving Lekhpals to the extent of the sum annually allotted for the purpose in the Land Records Budget.

21. Transfers :- (a) The Collector may at his discretion transfer a Lekhpal from one halqa to another within the district and the Assistant Collector may similarly transfer a Lekhpal within the sub division.

(b) When any tract is under survey, record or settlement operation or under the operations for consolidation of holdings, the transfer of a Lekhpal outside the area under the aforesaid operations, shall not be made by the Collector or the Assistant Collector without consulting the Records of Settlement Officer, or the Settlement Officer of Consolidation, as the case may be.

22. Leave :- The Assistant Collector may grant leave to Lekhpals and make temporary arrangements for the duties of Lekhpals' leave.

23. Travelling Allowance :- The travelling and daily allowance admissible to Lekhpals shall be governed by the following rules :

Lekhpals are entitled to travelling allowance when they are transferred from one halqa to another only on public grounds and not at their own request or in consequence of misconduct or punishment. The Travelling allowance shall be paid to them at the ordinary rates admissible to Government servants of the fourth class but if they travel with their families they shall be granted an extra railway fare of the lowest class for a journey by rail and mileage allowance at 12 naya paisa for a journey by road.

- (2) Subject to the collector's express sanction, Lekhpals, are entitled to railway fare admissible to Government servants of the fourth class for railway travel and to daily allowance as in sub rule (3), for journeys not connected with case work under the authority of an officer not lower in rank than as Assistant Collector.
- (3) (a) For halts on Government work at the headquarters of their tahsil or at a place outside their halqa but within the limits of their tahsil Lekhpals shall be paid daily allowance at the rate of 75 naya paise per day from the third day of the halts. No, daily allowance shall be admissible to them for the first two days of their halts.
- (b) For halts at district headquarters which are not the headquarters of the tahsil in which the halqa are situate or as any place other than those mentioned in clause (a), provided they are outside their tahsil and the halqa is necessary on account of Government work, they shall be paid an allowance of 75 naya paise per day for their entire period of halt.
- (4) Lekhpals who live beyond a radius of five miles from the headquarters of the tahsil in which their halqa is situate shall also be paid a fixed travelling allowance of Rs. 4 per mensem.
- (5) Lekhpals will be granted by the Courts in the Ordinary way actual expenses incurred by them when summoned to give evidence in criminal, civil or revenue cases, provided, that, except in criminal cases in which the expenses are payable by the State Government, the cost shall be borne by the parties summoning the Lekhpals.
- (6) Lekhpals selected for training at the Kanungo Training School shall be allowed travelling allowance at the ordinary rates for journeys from the districts to which they are attached to the Kanungo Training School and back; provided that if at the end of the training any of them is posted to a station other than that from which he was deputed to the training class he shall be entitled to the following additional travelling allowance for journey from the old district to the new district.

For the journey by rails :- An extra fare of the lowest class, and

For the journey by road :- One extra road mileage at 6 n. p. per mile, provided that his family proceeds to the new district.

No daily allowance shall be admissible for halts at the training school.

24. Survey instruments :- Each member of the service shall be supplied with such survey instruments as may be specified from time to time. The maintenance and disposal of these instruments will be regulated by executive orders.

Note :- The Survey instruments at present sanctioned to be supplied each member of the service are in Appendix "C".

25. Restrictions on Lekhpals :- The member of this service may cultivate land in their halqas with the written permission of the Collector of the district to which they are posted such permission will ordinarily be given unless the Collector considers that it will interfere with the discharge of his official duties.

26. Obligation of Residence :- The Lekhpal shall reside within his halqa unless he has obtained permission of the Collector to reside outside it.

Note :- The principal to be followed in allowing exemption and in dealing with absentees are laid down in paragraph 538-544 of the Land Records Manual.

27. Medical Concessions :- The members of the Service shall be entitled to medical facilities enjoyed by Uttar Pradesh Governments servants under the Uttar Pradesh Government Servants (Medical Attendance) Rules 1946.

28. Charge of Records :- When a Lekhpal submits resignation or is ordered to be transferred, he shall before leaving his post make over all his papers and records to the Supervisor Kanungo or to such other person as the Supervisor Kanungo may indicate.

29. Fines :- (Omitted).

30. Pension :- The service of Lekhpals shall be pensionable but the past service of the Patwaris, absorbed as Lekhpals shall not count for pension.

¹[31. Age of Retirement :- The age of retirement in the case of Lekhpals governed by conditions, laid down in sub-paragraph 3 (a), (b) and (c) of para 2 of G. O. No. 4434/IB-, dated 27th April, 1953, shall be 60 years and in the case of other members of the service shall be the date on which he attains the age of 58 years. He may be retained in service after the date of compulsory retirement with the sanction of the State Government on public grounds, which may be recorded in writing, but he shall not be retained after age of 60 years except under very special circumstances.

Provided that-

- (i) the appointing authority may, after giving at least 3 months previous notice in writing to the Lekhpals without assigning any reason retire him from service on the date on which he attains the age of 55 years or on any date thereafter to be specified in the notice.
- (ii) a Lekhpal may after giving at least three months previous notice in writing to the appointing authority, voluntarily retire from service on the date on which he attains the age of 55 years or on any date thereafter to be specified in the notice.

Provided further that-

- (i) the notice of voluntary retirement given under the first proviso by a Lekhpal against whom a disciplinary proceeding is pending or contemplated, shall be

1. Subs. by Notification No. 8/2 (1)-F-66, dated 25-8-1967.

effective only if it is accepted by the appointing authority subject to the condition that in case of a contemplated disciplinary proceeding the Lekhpal is so informed before the expiry of the notice;

- (ii) the notice once given by a Lekhpal under the first proviso shall not be withdrawn by him except with the permission of the appointing authority.

32. Pay, Allowances, Leave, Pension and other conditions of service :- Except as provided in these rules, the pay, leave allowance, pension and other conditions of service shall be regulated by rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution and, pending the issue of such rules by the rules, declared applicable by Notification No. A 582/X-6308, dated November 14, 1930 and No. G-689/X-534-(44), dated July 16, 1937 and by those made under Section 242 (2) of the Government of India Act, 1935 (since repealed) and continued in force by Article 313 of the Constitution :

Provided that the service rendered prior to the enforcement of these rules shall not count for purposes of leave :

Provided further that where disciplinary proceedings are pending on the date immediately preceding the date of commencement of these rules the same shall be continued as if these rules have not commenced.

33. When the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in these rules, by order dispense with or relax the requirement of that rule to such extent subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Appendix "A"

The Governor has been pleased to order in pursuance of the provisions of clause (4) of Article 16 and Article 335 of the constitution that consistently with the maintenance of efficiency of administration-

- (i) the interest of the backward classes shall in general be borne in mind in making appointments, and
- (ii) there shall be a general reservation of 18 per cent of the vacancies to be filled by direct recruitment for members of the Scheduled Castes in making appointments to service and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh;

Provided that if any one year candidates of the Scheduled Castes fall to be recruited to any service or establishment to the extent of 18 per cent the deficiency shall be made good in the recruitment to the service or establishment concerned in the following two years :

Provided further that the reservation on account of the deficiency shall not be carried forward for more than two years.

Appendix "B"

(Deleted)

Appendix "C"

Copy of Letter No. 10420/I-B dated October 26, 1953, from The Deputy Secretary to Government, U. P., Uttar Pradesh Revenue (B) Department to the Land Reforms Commissioner, Uttar Pradesh.

Subject : Recruitment of Lekhpals

With reference to the correspondence resting with your U. O. No. 10091 (4)/VI-94 dated September 28, 1953, and in partial modification of para 2 (12) of G. O. No. 4434/IB, dated April 27, 1953. I am directed to say that in addition to the survey instruments mentioned therein, one brass scale (6 inches in length) also be supplied to every Lekhpal at Government expense. The additional cost on this account must be met from within the budget allotment in the Land Records Budget for the current financial year as reduced by economy cuts, etc.

Extract from G. O. No. 4434/I-B, dated April 27, 1953

2. (12) The following survey instruments will be supplied to each member of service at Government expense :

- (a) A Gunia (off set squares)
 - (b) An area comb.
 - (c) A pair of dividers.
 - (d) A Gatha.
-

CHAPTER XVII

Uttar Pradesh Sadar Kanungo Service Rules, 1968¹

Notification No. 84/2(2) F/65, dated Lucknow April 25, 1968 :- In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 84/2(2) F-65, dated 25th April, 1968.

Preamble :- In exercise of the power under the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supercession of the Subordinate Revenue Executive (Sadar Kanungos)* Service Rules, 1957, the Governor of U. P. is pleased to make the following rules.

Part I - General

1. Short title extent and commencement :- (1) These Rules may be called the U. P. Sadar Kanungos* Service Rules 1968.

(2) They shall apply to the whole of the State.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette.

Short Notes

Now the designation of Sadar Kanungo has been changed to Sahayak Bhulekh Adhikari.

2. Status :- The status of the service shall be that of non-Gazetted Subordinate Revenue Executive Service.

3. Administrative control :- The service shall be under the administrative control of the Board of Revenue, U. P.

4. Definitions :- In these rules unless there is any thing repugnant in the subject or context-

(a) "Board" means the Board of Revenue, U. P.

(b) "Commissioner" means the Commissioner of a division in U. P.

(c) "Collector" means the Collector of a district.

(d) "Member of Service" means a person appointed in a substantive capacity in a cadre of the service.

(e) "Service" means the U. P. Sadar Kanungo* Service.

Part II - Cadre

5. Strength of the service :- The strength of the service shall until orders varying of the same have been passed by 58.

Provided that-

(a) The Governor may increase the cadre by creating additional, permanent or temporary posts from time to time, as may be found necessary, and

(b) The Board may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to Compensation.

¹ Published in U. P. Gazette pt. 1-Ka, dated 4-5-1968.

Part III - Recruitment

16. Source of Recruitment :- Recruitment to the service shall be made by the Board by promotion from amongst :

- (i) Supervisor Kanungos (including those such Supervisor Kanungos who may be working for the time being in the Consolidation of Holdings operations or any other special duty post), who have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, U. P., or an examination recognised by the Governor as equivalent thereto, and
- (ii) Registrar Kanungos, who have put in atleast five years, service as such, on the first day of June of the year of selection and have passed High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Governor as equivalent thereto :

Provided first that the reservation in favour of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other categories, if any, shall be in accordance with the orders of the Government issued from time to time :

Provided secondly that the Board may for special reasons to be recorded in writing exempt any candidate from the educational qualification, if it is satisfied that this is necessary in the interest of fair dealing or in public interest :

Provided thirdly that a Registrar Kanungo selected for appointment to the post of Sadar Kanungo shall, before his appointment as Sadar Kanungo have to undergo the same training of one year in the Survey and Land Records Training Institute as is required to be undergone by persons selected for appointment to the post of Supervisor Kanungo and such Registrar Kanungo shall, while on such training, be treated on duty and he shall, during the period of such training, get his pay and allowances admissible to him as Registrar Kanungo :

Provided fourthly that the recruitment from the above two sources shall, subject to the condition laid down in the the first proviso, be so arranged that twenty-five percent of vacancies are filled by promotion from amongst the Registrar Kanungos.

7. (1) The selection of the candidates for promotion to the post of Sadar Kanungos shall be made on the basis of seniority subject to the fitness of a candidate to hold the higher post.

(ii) The Board shall maintain a gradation list of all the Registrar Kanungos and Supervisor Kanungos, including therein the candidate who are eligible for promotion and shall also maintain their character rolls. They will consider the cases of all eligible candidates and draw up to separate lists one from the Registrar Kanungos and other from Supervisor Kanungos.

Part IV - Appointment, Probation and Confirmation

8. There will be two separate lists one from Supervisor Kanungos and the other from Registrar Kanungos for substantive as well as officiating and temporary appointments. The names in the both the list shall be equal to the number of substantive and anticipated officiating and temporary vacancies during the course of

the year in which the selection is made. The lists shall be prepared annually in the first quarter of each year or at longer intervals according to the need. But they shall be reviewed annually. The Board shall remove the names of the candidates who have been absorbed in permanent vacancies and of any other candidate for good and sufficient reasons to be recorded in writing. The appointment against the substantive officiating and temporary vacancies shall be made by the Board from these lists in accordance with the principle laid down in Rule 9.

9. (i) On the occurrence of the substantive, vacancies the Board shall make appointment to the service in the order in which the names of candidates appear in the lists prepared under Rule 8 in such a cycle that so far as may be possible first vacancy shall go to the Registrar Kanungo and nine vacancies occurring subsequently shall go to the supervisor Kanungos, the eleventh vacancy that may occur shall again go to the Registrar Kanungo and so on.

(ii) The Board may make appointments in officiating or temporary vacancies from the list of candidates approved for such appointment.

Provided that if no candidate is available on the list the Board may make appointment in such vacancies from among the candidates eligible for promotion under the Rules.

Provided further that the Collector may also make appointment in officiating and temporary vacancies not exceeding three months in duration, of candidates approved for appointment. The names of such candidates will be ascertained from the Board. If however no such candidate is available in the district, he may make appointment in such vacancies from among the candidates eligible for promotion under the Rules.

10. Seniority :- Seniority in service will be determined by the date of substantive appointment provided that if two or more candidates are substantively appointed from the same date their seniority will be determined according to the order in which their appointments shall be made under Rule 9.

11. Probation :- (i) Every person shall, on appointment to the service in or against a substantive vacancy, otherwise than in an officiating or temporary capacity, be placed on probation for a period of one year from the date on which he joins his appointment. Provided that continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre of the service or an equivalent or higher post as those of Naib-Tahsildars including Naib Tahsildars for Zamindari Abolition Compensation, Collection of Land Revenue demand, Taxation Ceiling or survey work or any other post of Naib Tahsildar may be taken into account in computing the period of probation.

(ii) The Board may for reasons to be recorded in writing extend the period of probation upto a period of one year in individual case. Any such extension shall specify the exact date upto which the extension is granted.

(iii) If during or at the end of the period of probation or the extended period of probation as the case may be, it is found that a candidate has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to satisfy the standard expected of him, he may be reverted to his substantive post without entitling him to any compensation.

12. Confirmation :- A probationer may be confirmed in his appointment at the end of the period of probation, if the Board are satisfied that he is fit for confirmation and his integrity is certified.

Part V - Pay

13. Scale of pay :- (1) The scale of pay admissible to a person appointed to the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time.

¹(2) The scale of pay admissible with effect from October 1, 1975 is Rs. 300-8-324-9-360-E. B. 10-440-E. B. 12-500.

Short Notes

The above pay scales have been revised by the U. P. Pay Commission with effect from 1-1-1986.

14. Criteria for crossing the Efficiency bars :- No member of the service in this time scale of pay shall be allowed to cross the efficiency bar by the Board unless he has worked with distinct ability and integrity.

Part VI - Other Provisions

15. Transfers :- Transfer of Sadar Kanungos will normally be made by the Board but the Commissioner may under intimation to the Board make such transfers with in his division in public interest.

16. Leave :- Leave other than special disability leave not extending beyond the date of compulsory retirement may be granted by the collector upto a duration of six weeks under intimation to the Board.

17. Pay :- Pay, allowances leave pension and other conditions of service. In regard to matter not specifically covered by these rules or orders made or issued there under or by special orders, persons appointed to the establishment shall be governed by the rules, regulations and orders applicable to Government servants serving in connection with the affairs of the State of U. P.

18. Relaxation from the conditions of service :- Where the Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in these rules, by order dispense with or relax the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary.

By order
Sd/ Athar Husain
Sachiv

CHAPTER IX

The Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1985¹

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of all existing rules and orders on the subject the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment of ministerial staff in the subordinate Government Offices in the State :

PART I - General

1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1985.

(2) These rules shall be deemed to have come into force at once.

2. Application these rules :- (1) These rules shall govern recruitment to all the ministerial posts of the lowest grade, other than the posts of Stenographer (which are required to be filled by direct recruitment and which are outside the purview of the Public Service Commission), in all subordinate offices under the control of the Government excluding the Uttar Pradesh Secretariat, the offices of the State Legislature, Lok Auykt, Public Service Commission, High Court, the Subordinate Courts under the control and superintendence of the High Court, the Advocate General, Uttar Pradesh, and of the establishments under the control of the Advocate General.

(2) Recruitment against all the vacancies of ministerial posts to which these rules apply shall be made in accordance with the provisions of these rules.

3. Effect of inconsistency with other rules :- In the event of any inconsistency between these rules and any specific service rules-

(i) the provisions contained in these rules shall prevail to the extent of the inconsistency in case the specific rules were made prior to the commencement of these rules; and

(ii) the provisions contained in the specific rules shall prevail in case they are made after the commencement of these rules.

4. Definitions :- In these rules, unless the context otherwise requires-

- (a) "appointing authority" in relation to a ministerial post in a subordinate office refers to the authority empowered under the relevant rules or orders to make appointments on that post;
- (b) "Constitution" means the Constitution of India;
- (c) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
- (d) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;
- (e) "Head of office" means the highest Gazetted Officer of an office;
- (f) "High Court" means the High Court of Judicature at Allahabad, including its Bench at Lucknow;
- (g) "ministerial staff" shall refer to the clerical staff of the subordinate offices which is required to be appointed by direct recruitment;

1. Vide Notification No. 20/3/82 Personnel 2-85 dated March 16, 1985 (w.e.f. 1-7-1986).

(h) "Subordinate Offices" shall refer to all the offices under the control of the Government excluding the Uttar Pradesh Secretariat, the offices of State Legislature, Lok Ayukt, Public Service Commission, High Court, the subordinate courts under the control and superintendence of the High Court, the Advocate General, Uttar Pradesh and of the establishment under the control of the Advocate General;

(i) "Retrenched employee" means a person-

(i) who was employed on a post under the rule making power of the Governor, in permanent, temporary or officiating capacity for a total minimum period of one year, out of which at least three months' service must have been continuous service,

(ii) whose services were of may be dispensed with due to reduction in or winding up of the establishment, and

(iii) in respect of whom a certificate of being a retrenched employee has been issued by the Appointing Authority; but does not include a person employed on ad hoc basis only;

(j) "Year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part II - Recruitment

5. Strength of Service :- The strength of ministerial staff in a particular Department Office and of each category of posts therein shall be such as may be determined by Government from time to time :

Provided that the Appointing Authority may have unfilled or the Governor may hold in abeyance any post or class of posts without thereby entitling any person to compensation :

Provided further that Government in the Administrative Department may, in consultation with the Personnel Department and Finance Department create such permanent or temporary posts in any Department/Office from time to time as may be found necessary.

6. Source of recruitment :- Recruitment to the lowest grade of the ministerial staff in a subordinate office shall be made by direct recruitment through the Selection Committee referred to in rule 17 on the basis of academic and other attainments as provided in rule 9 :

Provided that up to 15 per cent of the vacancies in a particular subordinate office may be filled by the Appointing Authority by promotion from amongst High School pass Group D employees of that office in accordance with the orders of Government issued from time to time.

Note :- The orders in force at the time of commencement of these rules are contained in G. O. no. 37/1/196-Karmik-2, dated August 31, 1982 (Annexure).

Part III - Qualifications

7. Reservation :- Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

8. Nationality :- A candidate for direct recruitment under the provisions of these rules must be-

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the east African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belonging to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note :- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

9. Academic qualification :- A candidate for direct recruitment must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination declared by the Governor as equivalent thereto.

10. Preferential qualification :- A candidate who has-

- (i) served in the territorial army for a minimum period of two years, or
- (ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other thing being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

11. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 30 years on the first day of July of the year of recruitment :

Provided that the upper age-limit shall, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time, be greater by such number of years as may be specified.

12. Relaxation for ex-servicement and certain other categories :- Relaxation, if any, in maximum age-limit, educational qualifications or in any procedural requirements of recruitment in favour of the ex-servicemen, disabled military personnel dependents of military personnel dying in action, dependents of Uttar Pradesh Government servants dying in harness, Sportsmen, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes and other categories shall be in accordance with the general rules or orders of the Government in this behalf in force at the time of recruitment.

13. Character :- The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy on the point.

13. Persons employed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible appointed to any post in the Service. Person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

14. Marital Status :- A male candidate who has more than one wife living or female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Provided that the Government : may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

15. Physical fitness :- No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rules 10 contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III :

Part V - Procedure for Recruitment

16. Recruitment in the subordinate offices within a district to be common :-
¹[X X X X X]

²[**17. Constitution of Selection Committee :-** For the purpose of recruitment to any post, there shall be constituted a Selection Committee as follows :

(1) Appointing Authority

(2) An officer belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe, nominated by the District Magistrate, the appointing authority on his nominee does not belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe. If the appointing authority or his nominee belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, an officer other than belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe to be nominated by the District Magistrate.

(3) Two officers nominated by the appointing authority, one of whom shall be an officer belonging to minority Community. If such suitable officer is not available in his department or organisation, such suitable officer shall on the request of the appointing authority, be nominated by the District Magistrate and his failure to do so, by reason of non-availability of suitable officer, such officer shall be nominated by the Divisional Commissioner]

³[**18. Recruitment to be made every year :-** Selection for recruitment under these rules shall.]

⁴[**19. Vacancies to be intimated to the District Selection Committee.]**

20. Vacancies to be filled at regional level.

21. Basis of selection :- Selection of candidates shall be made by the Selection Committee essentially on the basis of academic attainments of the candidates. Accordingly, in forwarding the names of the candidates the Employment Officer shall

1. Omitted by Notification No. 20/7/1986-
Karmik-2 dated 8 September 8, 1986.

2. Substituted by *Ibid*.

3. Substituted by Notification No. 20/7/1986-
Karmik-2 dated 8, September 1986 (w.e.f. 1.7.86).

4. Omitted by *Ibid*.

Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1985 57

have regard to the academic attainment of the candidates particularly their attainments at the minimum qualifying examination referred to in rule 8.

[22. Notification of Vacancies to the employment Exchange :- The appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the vacancies to be reserved under rule 7. The vacancies shall be notified to the Employment Exchange. The appointing authority may also invite application directly from the persons who have their names registered in the Employment Exchange. For this purpose, the appointing authority shall issue an advertisement in a local daily news paper besides pasting a notice for the same on the Notice Board. All such application shall be placed before the Selection Committee.]

[23. Procedure of Selection :- (1) When the names of the candidates have been received by the Selection Committee, it shall prepare a merit list of the candidates in the following manner :

- (a) The percentage of marks at the minimum qualifying examination for the post shall be entered against the name of each candidate.
- (b) For every higher examination passed an additional 10 per cent of the percentage of the marks secured in each such final examination shall be entered.

Explanation :- No Additional marks shall be awarded for a 'pass' in the first or second year examination of three years degree course or for Part I of the Bachelor's/Master's Degree Courses.

(2) The merit list so prepared shall be placed before the Selection Committee.

(3) The interview shall thereafter be held by the Selection Committee and marks shall be awarded at the interview by the Selection Committee in the following manner:

	Marks
(a) General Knowledge	20
(b) Proficiency in sports	5
(c) Retrenched employee	15

Total	40

Note :- (1) In assessing proficiency in sports allotment of marks shall be as follows :

- (i) If the candidate is a sportsman of International level- 5 Marks
- (ii) If the candidate is a sportsman of National level - 4 Marks
- (iii) If the candidate is a sportsman of State level - 3 Marks
- (iv) If the candidate is a sportsman of University/College/School level-2 Marks

(2) Marks to a retrenched employee shall be awarded in the following manner :

- (i) For the first completed year of service 5 Marks
- (ii) For the next and every completed year of service 5 Marks

(4) The marks allotted at the interview shall be added to the marks entered on the basis of academic attainments and the aggregate of the marks so arrived at shall, subject to the provisions of sub-rule (5), determine the positions of each candidate and the merit list shall be drawn up accordingly. If more than one candidate secure equal

marks in the aggregate, the candidate who secures more marks on the basis of academic attainments shall be placed higher.

(5) In the case of candidate to be selected for the post of typist as also for any other post for which typing has also been prescribed as an essential qualification only those candidates who know typewriting will be considered and final assessment of merit shall be made only after adding the marks obtained in Hindi typewriting. The candidates shall be required to appear at the competitive test for Hindi typing. Marks shall be allowed for Hindi typing out of the maximum marks of 50. The marks obtained in Hindi typing shall be added to the marks already obtained under sub-rule (4) and the final merit list shall in such case be prepared on the basis of aggregate marks.

(6) In the case of candidates for the posts for which Commerce or any other special/technical qualification is prescribed as an essential qualification only those candidates will be considered who have Intermediate Commerce or Bachelor of Commerce qualification/who possess the required special/technical qualifications.

(7) The names of candidates belonging to such categories for whom vacancies are required to be reserved in accordance with the general order of the Government shall be arranged in a separate list according to their *inter se* merit at the examination.

(8) The number of candidates to be selected will be larger (but not larger than 25 per cent) than the number of vacancies for which the selection has been made.

24. Fee :- Candidates for selection shall be required to pay to the Selection Committee such fee as may, from time to time, be prescribed by the Government. No claim for the refund of the fee shall be entertained.

Note :- The scale of fee prescribed at the commencement of these rules for the candidates belonging to the Scheduled castes and Scheduled Tribes is Re. 0.50 and for all other candidates Rs. 2.00.

¹[25. Allotment of selected candidates].

Part V - Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

²**26. Appointment by Appointing Authority :-** The select list referred to in sub-rules (6) and (7) of rule 23 shall be forwarded by the selection Committee to appointing authority mentioning the aggregate marks obtained at the selection by each candidate. The name of general and reserve candidates shall be arranged by the appointing authority in a common list according to the merit of the candidates and the appointment shall be offered in the order in which the name are arranged in the list. The select list shall hold good for a period of one year from the date of selection.]

27. Ad hoc appointments :- Where the list of selected candidates is exhausted or no candidate is available for appointment from out of the list of the selected candidates, *ad hoc* appointment from amongst persons eligible for appointment under these rules may be made by the concerned appointing authority. Such appointments should not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier.

28. Probation :- (1) Except where otherwise provided in the rules applicable to any particular service or post a person on appointment to a post in the

1. Omitted by Notification No. 207/1986-Karnik-2 dated 8.9.1986 (w.e.f 1.7.86)

2. Substituted by *Ibid*.

Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1985 59

Department/Office in a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of one year.

Provided that the appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the period is extended :

Provided further that the period of probation shall not be extended beyond one year.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of the probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of the opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to a post, on which he holds a lien, or if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with without entitling him to any compensation in either case.

(3) The appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post on the cadre to be taken into account in computing the period of probation for that post.

29. Confirmation :- A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation, as the case may be, if his work and conduct have been found to be satisfactory, his integrity is certified and the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmations.

30. Seniority :- (1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons appointed under these rules shall be determined from the date of the order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together by the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment, and in other cases, it will mean the date of issue of the order.

(2) The seniority *inter se* of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the Selection Committee :

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

Part VI - Pay etc.

31. Scale of pay :- (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Department/Office whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of commencement of these rules is Rs. 354-10-424-E. B.-10.454-12-514-E. B. 12-550.

Note :- For New Pay Scale See Chapter XXXVIII

32. Pay during probation :- (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and the second increment after he is confirmed.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

33. Criterion for crossing efficiency bar :- No persons shall be allowed to cross-

(i) the first efficiency bar unless his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified, and

(ii) the second efficiency bar unless he has worked diligently and to the best of his ability, his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

Part VII - Other Provisions

34. Canvassing :- No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

35. Regulation of other matters :- In regard to matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to posts in various Departments/Offices shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

36. Relaxation from the conditions of service :- Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to posts in various Departments/Offices causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of the rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

37. Savings :- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

CHAPTER XII

The Uttar Pradesh Service Commission (Limitation of Functions) Regulation, 1954

No. 99/II-B-151-50 dated January 20, 1954.- In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, and in supersession of the regulations published with Notification No. 1792/11-848-40, dated October 15, 1941, as subsequently amended, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following regulations as respects the services and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh, other than services, and posts to which appointments are made from among members of All-India Services, or are regulated by the rules and orders applicable to such service :

1. Short title and commencement :- These regulations may be called "The Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1954", and shall take effect from the date of this notification,

2. Definitions :- In these regulations unless there is anything repugnant in the subject or context-

- (a) "Appointing authority" means the authority which makes appointments to any service or post in connection with the affairs of Uttar Pradesh ;
- (b) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission;
- (c) "Constitution" means the Constitution of India;
- (d) "Direct Recruitment" means recruitment otherwise than by promotion, transfer, or deputation under regulation 4 (a);
- (e) "Governor" and "Government" means respectively, the Governor and Government of Uttar Pradesh;
- (f) "Service" or "Post" means civil service or post in connection with the affairs of Uttar Pradesh.

Short notes

Article 320 of the Constitution of India deals with two situations; namely, the power of the Public Service Commission to conduct Examination and the right of the Government to seek advice in all matters relating to the method of recruitment to Civil Service and Civil posts. The recruitment to seek advice of the Public Service Commission is not mandatory and non-compliance with it will not invalidate the action taken by the Government. The scheme of Article 320 abundantly makes it clear that the Commission has to be consulted in the matter of suitability of candidates for appointment, promotion or transfer. There is nothing in these provisions which makes it imperative for the Government to accept the advice tendered by Commission. The action of the Commission in recommending more candidates for appointment than the one asked for by the State Government is not sustainable under any provision of law or any binding precedent.

(1989 (1) SLJ P & H HC 364)

¹[3. It shall not be necessary for the Commission to be consulted on matters relating to methods of recruitment to civil services and posts, or the principles to be

1. Subs. by Notification 13/19/91-Kamnik-1-199, dated 7-9-1994.

U. P. Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulation, 1954 75

followed in making appointments through direct recruitment to such services and posts or the suitability of candidates for such appointments, in the following cases :

- (a) When the appointing authority in respect of the service or post concerned is an authority other than the Governor, unless in any particular case, Government have directed or may after consultation with the Commission direct that the service or post in question shall be within the purview of the Commission.

Note :- The services and posts mentioned in the Scheduled appended to the U. P. Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1941, as in force before the date of this notification, shall continue to remain under the purview of the Commission until a direction to the contrary is issued by the Government, after consultation with the Commission.

- (b) When the appointing authority in respect of the service or post concerned is the Governor, but the Governor for any reason directs, after consultation with the Commission, that the service or post in question shall be outside the purview of the Commission.
- (c) When the appointing authority in respect of the service or post concerned is the Governor or is an authority other than the Governor and the person concerned being directly appointed on ad hoc basis on or before the date notified by Government possessed requisite qualifications for regular appointment at the time of such ad hoc appointment and has completed three years continuous service on or after the said date.

Short Notes

The Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Function) Regulation 1954 was published in Notification No. 99/11-B-151-5 dated January 29, 1954.

4. It shall not be necessary for the Commission to be consulted on matters relating to methods of recruitment to civil services and post, or the principles to be followed in making appointments to such service and posts, or the suitability of candidates for such appointments in the following cases namely ;

- (a) When it is proposed by the Governor to appoint a member of a state service or a Subordinate Service on deputation to a post, whether temporary or permanent, outside the cadre of that service, the status and responsibilities of which are such as may, in the opinion of the Governor, be adequately fulfilled by that member of the service.

Note :- The term "member of a service" in the clause means a person holding in a substantive capacity a post included in the cadre of that service.

Illustrations

- (i) The appointment of an officer of U. P. Educational Service to the post of Secretary, Deputy Secretary or Under Secretary to Government, or to that of Officer on Special Duty in the Secretariat, does not require consultation with the Commission.
- (ii) The appointment of a member of the U. P. Civil Service (Executive Branch) as Deputy Development Commissioner, or Inspector of Stamps and Registration, or Personal Assistant to the Excise Commissioner, on the basis of deputation which does not involve the termination of his lien in the U. P.

Civil Service (Executive Branch), does not require consultation with the Commission.

- (iii) The appointment of a member of the U. P. Secretariat Service (Assistant Secretaries' Grade) as an Under or Deputy Secretary to Government, or of a member of the Subordinate Revenue Executive (Tahsildar). Service to the temporary post of Assistant Director of Panchayat Raj, does not require consultation with the Commission.
- (b) When an appointment is to be made by the Governor to any post, the expenses of which are charged on the Consolidated Fund of the State.
- (c) The appointment of law officers of the State, the Administrator General and Official Trustee and the Law Reporters in the High Court at Allahabad.
- (d) The appointment of a warrant or non-commissioned officer of the Defence Forces to a civil post which is or in the opinion of the Governor should be, normally held by such officers, and the temporary appointment of an officer of the Defence Forces to a civil post or service.
- ¹[(e) When it is proposed by the Governor, an authority other than the Governor on specific instructions of the Governor to make appointment to any service or post by absorption of any employee of a Government Department or of an undertaking ²[or of an institution provincialised or taken over by the Government].

Explanation :- The expression undertaking in this clause means :

- (i) A statutory body incorporated by or under any Uttar Pradesh Act or Central Act;
- (ii) A government company within the meaning of Section 617 of the Companies Act, 1956;
- (iii) A Local Authority within the meaning of clause (25) of Section 4 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904;
- (iv) A scientific organisation registered under the Societies Registration Act, 1860 wholly or partly under the control of the Central Government or any State Government.

5. Notwithstanding anything contained in Regulations 3 and 4, it shall not be necessary for the Commission to be consulted in the following cases, namely :

- (a) When a temporary or officiating appointment is to be made by direct recruitment by the Governor or an authority other than the Governor, to a permanent or temporary post which falls within the purview of the Commission, if the person to be appointed is not likely to hold the post for a period of more than one year; provided that the person thus appointed shall not hold the post in question for a total continuous period of more than one year without the Commission being consulted.

Illustration

A retired officer of the U. P. Civil Service (Executive Branch) is re-employed as a Deputy Secretary to Government in a temporary post. It will not be necessary to consult the Commission if the re-employed officer is not likely to hold the post for

1. Ins. by Notification No. 13-2-1990-
Karmik-1, dated 2-3-1990.

1. Added by Notification No. 13/2/90-
Karmik-1, dated 22-7-1992.

U. P. Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulation, 1954 77

more than one year, but he shall not be retained in the post for more than one year without the Commission being consulted.

- (b) In regard to the selection for appointment to any post which falls within the purview of the Commission, if the Governor has decided, after consultation with the Commission, that it should be filled by recruitment from outside India, provided that consultation with the Commission may be dispensed with if it necessary in the opinion of the Governor that the appointment should be made immediately and reference to the Commission would cause undue delay.
- (c) In regard to recruitment to the subordinate ranks of the Police Force of the State.

Explanation :- The expression "Police Force" in this clause includes the P. A. C. and other similar formation.

¹[6. **Promotion :-** It shall not be necessary to consult the Commission -

- (a) on the suitability of candidates in making promotion to a post, notwithstanding the fact that certain percentage of such post is within the purview of the Commission.
- (b) on the principles to be followed in making promotion to a post where :
 - (i) promotion is the only source of recruitment.
 - (ii) direct recruitment is one of the sources of recruitment and the same is not made through the Commission.

Explanation :- The provisions of this regulation shall also apply to requisition pending with the Commission on the date of commencement of the Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) (Thirteenth Amendment) Regulation, 1994 in which selection for promotion has not been finalised by the Commission.]

²[6-A. Notwithstanding anything contained in Regulations 3, 4, 5 and 6, it is not be necessary for the Commission to be consulted when a selection for a temporary or officiating appointment is to be made by the Governor or by an authority other than the Governor to a post which falls within the purview of the Commission, where the post is expressly created in connection with the Emergency declared by the President under clause (1) of Article, 352 of the Constitution of India on October 26, 1962, and the person to be appointed to such post is not likely to hold the same longer than the period of the said Emergency or three years, whichever is less and where further it is certified-

- (i) by the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department concerned, where the appointing authority is the Governor, or
- (ii) by the Head of the Department concerned where he or an authority subordinate to him is the appointing authority, that the post needs to be filled up immediately.

Provided that every such appointment shall be reported to the Commission immediately after it is made.]

7. Transfers :- It shall not be necessary to consult the Commission on the principle to be followed in making transfers or on the suitability of candidates for transfer, from one post to another in the same service;

Provided that if a service is divided into two or more separate sections, and it is proposed to transfer an officer from one such section to another, the Commission shall be consulted if, according to the rules of the service, recruitment to the section to which the officer is to be transferred may be made, either directly or by promotion, in consultation with the Commission.

Note :- The persons engaged on contract through the Commission shall be treated like temporary Government Servant, if engaged for a definite or specified period, and like persons recruited to posts which are advertised as being likely to become permanent, if engaged for indefinite period (see G. O. No. 2949/II-B-1953, dated December 10, 1953)

Illustration

In the U. P. Industries Service, Class II, there are several Sections A, B, C, etc. Under the rules of the service, it is provided that posts in Section A may be filled by transfer from one of the other sections. It is also provided in those rules that recruitment to posts in Section A may be made directly or by promotion after consulting the Commission. The Commission shall be consulted before an officer is transferred to Section A from one of the other sections.

8. Disciplinary matters :- It shall not be necessary to consult the Commission before an order is passed in any disciplinary case except when-

- (a) an original order is passed by the Governor imposing any of the following penalties-
 - (i) withholding of increment in the time scale at stages where there is no efficiency bar;
 - (ii) reduction to a lower post or time scale or to a lower stage in a time scale;
 - (iii) recovery from pay or pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of rules or orders;
 - (iv) removal from service;
 - (v) dismissal from services; and
 - (vi) reducing or withholding or withdrawing the pensions as admissible under the rules governing pensions :

Provided that if the order is passed by the Governor under proviso (c) to clause (2) of Article 311 of the constitution or by the Governor or the High Court under the Uttar Pradesh Disciplinary Proceeding (Administrative Tribunal) Rules, 1947 as amended from time to time or the increment is stopped as a result of withholding of the integrity certificate, it shall not be necessary to consult the Commission :

Provided further that if in any case, the Commission have already, at any previous stage, given advice to the order to be passed, and no fresh question of substance has, in the opinion of the Governor thereafter arisen for determination, it shall not be necessary for the Commission to be consulted again before a final order is passed by the Governor.

- (b) a final order is passed by the Governor on appeals against the orders passed by a subordinate competent authority, if the appeal is admissible under the rules.

U. P. Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulation, 1954 79

Explanation :- An order passed by the Governor, in view of certain material defects in procedure followed by a subordinate authority, requiring the competent subordinate authority to start disciplinary proceedings afresh, or from a subsequent stages as the case may be shall not be deemed to be a final order by the Governor for the purpose of this clause.

¹*[Exception :-* In cases of appeals from Civil Court employees against the punishment awarded under the Subordinate Civil Court Officials (Punishment and appeals) Rules, 1948, consultation with the Public Service Commission would not be necessary.

- (c) an order is proposed to be passed by the Governor, otherwise than under clause (b), over-ruling or modifying the order of a subordinate authority whether original, appellate or revisionary :

Provided that if the order proposed to be passed by the Governor merely directs a competent subordinate authority to start disciplinary proceedings, afresh or from a subsequent stage, as the case may be, in view of certain material defects in procedure followed by the subordinate authority concerned, consultation with the Commission shall not be necessary.

Illustration

(1) The Governor proposes to censure an officer of the U. P. Civil Service (Executive Branch) or to stop him for one year at the first efficiency bar in the time-scale of the service. Consultation with Commission is not necessary before such an order is passed by the Governor. Similarly, consultation with the Commission will not be necessary before such an officer is placed under suspension pending enquiry into the officer's misconduct.

(2) The Governor proposes to reduce a Tahsildar X, who had been substantively promoted to the U. P. Civil Service (Executive Branch) to the rank of Tahsildar. The Commission should be consulted before such an order is passed by the Governor. But if X, is merely officiating as a Deputy Collector, and finding his work unsatisfactory, the Governor at any time proposes to revert X to his substantive post of Tahsildar, it shall not be necessary to consult the Commission before orders are passed by the Governor regarding X's reversion. In another case, certain grave allegations are made against Tahsildar A who is officiating as a Deputy Collector which prima facie seem to the Governor to be justified and the Governor, therefore, considers it necessary in the public interest that A should be formally punished. After disciplinary proceedings have been conducted against A in the prescribed manner, the Governor proposes to impose upon him the penalty of "reduction to a lower post" and in consequence to revert him to his substantive post of Tahsildar. A's reversion in this case will require consultation with the Commission.

(3) A temporary Assistant Engineer in the Public Works Department who is officiating as an Executive Engineer is alleged to have committed certain serious irregularities in connection with the construction of a departmental building. Charges are framed against him accordingly and the Chief Engineer is asked by the Governor to conduct formal disciplinary proceedings against the Executive Engineer, and to submit his report to the Governor. After considering the Chief Engineer's report, the Governor decides not to impose any of the formal penalties mentioned under clause (a) upon the

¹. By Correction slip No. 1 of 1964.

Executive Engineer, but in view of certain unsatisfactory aspects of the officer's conduct as disclosed in the Chief Engineers' report, the Governor considers that the officer is not fit to hold the post of Executive Engineer, and therefore, issues orders reverting the officer to the post of Assistant Engineer. Consultation with the Commission is not necessary before such an executive order of reversion is passed by the Governor because the order does not specifically involve the imposition of the formal penalty of "reduction to a lower post", as mentioned under clause (a) of the regulation.

(4) Certain bags of wheat flour are found missing from a rationing godown in a District Supply Office. After considering the report of the District Supply Officer, the Governor considers that the loss has been caused by the negligence of the District Supply Officer, and calls upon the latter to make good the loss to Government. The District Supply Officer agrees to do so. Consultation with the Commission will not be necessary in this case, because the recovery of the amount has not been formally ordered to be made from the pay of the District Supply Officer. But in case the District Supply Officer does not agree to make good the loss, and the Governor proposes that the loss should be made good to Government by making recoveries from the pay of the District Supply Officer, the Commission should be consulted before such an order is passed by the Governor.

(5) A subordinate service officer employed under the Director of Agriculture is dismissed from service by the latter who is competent to do so. Consultation with the Commission is not necessary in this case because the penalty of dismissal from service is not imposed by the Governor.

²(6) A who is a member of the U. P. Civil Service (Executive Branch) on probation is reported at the end of his period of probation, to have failed to give satisfaction and the Governor proposes to despatch him with his services in accordance with sub rule (3) of rule 21 of the Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch) Rules, 1982. Consultation with the Commission is not necessary before such an order is passed by the Governor, because the discharge of a person under such circumstance does not amount to removal or dismissal from service within the meaning of rule 49 of the Classification, Control and Appeal Rules.

(7) X is a temporary Government servant employed as a Regional Transport Officer, his service being terminable on one month's notice. His work is not found satisfactory, and the Governor, therefore, proposes to terminate his service after giving him the prescribed notice of one month. Consultation with the Commission is not necessary before such an order is passed by the Governor.

(8) According to the rules of U. P. Civil (Executive Branch) a member of the service on probation is not entitled to draw the first increment in the time-scale unless he passes Part I of the Departmental Examination, and to draw the second increment unless he is confirmed in service. The withholding of the first and second increments according to these rules does not require consultation with the Commission because it has not been imposed by the Governor as a penalty, but is merely the consequence of the accepted condition of service.

(9) A Head of Department imposes upon an official who has been appointed to him, the penalty of withholding of two increments or of recovery from the official.

2. Substituted by G. O. No. 12-1-74-Karmik-1, dated 2-5-1983.

U. P. Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulation, 1954 81

pay of the part of the pecuniary loss which has been caused to Governor against the imposition of these penalties. The Governor proposes to reject these representations. Consultation with the commission will not be necessary, because under the rules, no appeal lies in either of these two cases. But if the Governor proposes to reduce the penalty in the first case to the withholding of increment for one year only or in the second case to enhance the penalty to the recovery of the whole of the pecuniary loss caused to Government, the Commission should be consulted before such an order is passed by the Governor, as the cases will then fall under clause (c) of the regulation.

(10) The pension of an official is reduced by the Head of the Department who is competent to do so, and that official submits an appeal to the Governor within the prescribed time-limit. The commission should be consulted before the appeal is disposed of by the Governor. But if the appeal is not filed within the prescribed time-limit and on that ground the Governor proposes to dismiss the appeal, consultation with the Commission will not be necessary, because the appeal is not admissible under the rules. If, on the other hand the Governor finds that the Head of the Department was not competent to pass the order of reduction in pension, and the Governor, therefore, proposes to deal with the case himself, even though the appeal is time-barred, after cancelling the order passed by the Head of the Department, consultation with the Commission will not be necessary regarding the cancellation of the order passed by the Head of Department but in case the Governor himself proposes to make a reduction in the official's pension the Commission should be consulted before such a final order is passed by the Governor.

(11) A clerk in district office is dismissed by the District officer. The clerk appeals to the Commissioner who rejects the appeal. The clerk then files a revision before the Board of Revenue. The Commission will not be consulted before an order is passed by any of these authorities. The clerk finally submits a representation or memorial to the Governor to which the later proposes to reject. Consultation with the Commission will not be necessary before such an order is passed by the Governor. But if the Governor proposes to over rule or modify the order passed by any of the subordinate authorities, the ground being that the District Officer did not comply with the prescribed procedure, the Commissioner should be consulted before a final order is passed in the case by the Governor but not if the Governor merely cancels the order of dismissal passed by the District Officer and directs the latter to start disciplinary proceedings afresh in accordance with the prescribed procedure.

(12) An officer who was dismissed from service by an original order of the Governor, passed after consultation with the Commission, submits a memorial on the Governor against the order. Consultation with the Commission will not be necessary about the disposal of the memorial. But if the Governor proposes on reconsideration, to modify the original order of dismissal into that of reduction to a lower post, consultation with the Commission would be necessary if this modification is that variance with the advice that had been given by the Commission on the previous occasion.

¹[9. Claim of pensions/gratuity :- It shall not be necessary to consult the Commission on any claim for the award of, pension/gratuity in respect of injuries sustained by or death due to injuries of any person to whom the provisions of the U. P. Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1941, or the U. P. Police (Extraordinary Pension) Rules, 1961, apply.

1. Inserted by Notification No. 15/43-80-Ka-1, dated 10 December, 1980 (published in U. P., Gazette dated 17-1-1981).

CHAPTER XIX

उत्तर प्रदेश अवर राजस्व लिपिक (रजिस्ट्रार कानूनगो और सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो) सेवा नियमावली, 1958

[U. P. Aur Rajsaw Lipik (Registrar Kanungo Aur Sahayak Registrar Kanungo) Sewa Niyamawali, 1958]

विज्ञप्ति

विविध

सं 9403/1-ख-1099-ख-54

30 अगस्त, 1958 ई०

प्रस्तावना :- इस विषय के सभी वर्तमान नियमों तथा आज्ञाओं को निष्प्रभाव करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के गवर्नर (राज्यपाल) रजिस्ट्रार कानूनगो तथा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों के लिए भर्ती (recruitment) तथा उन पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तों (condition of service) को नियमित करने के निमित्त निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और प्रारम्भ :- यह नियमावली उत्तर प्रदेश अवर लिपिक (रजिस्ट्रार कानूनगो तथा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो) सेवा नियमावली, 1958 कहलायेगी और विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

2. नाम और सेवा की आस्थिति (status of service) :- इस सेवा का नाम "उत्तर प्रदेश अवर राजस्व लिपिक (रजिस्ट्रार कानूनगो तथा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो) सेवा" है और इसकी आस्थिति अराजपत्रित अवर लिपिक सेवा (non-gazetted subordinate ministerial service) की है।

3. परिभाषा :- विषय या प्रसंग (subject or context) में कोई बात प्रतिकूल (repugnant) न होने पर इस नियमावली में-

(क) "कलेक्टर" से तात्पर्य जिले का कलेक्टर है।

(ख) "कमिश्नर" (Commissioner) से तात्पर्य डिवीजन का कमिश्नर है।

(ग) "संविधान" से तात्पर्य भारत का संविधान है।

(घ) "संचालक" से तात्पर्य भूमि लेख संचालक है।

(ङ) "राज्य (State)" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश का राज्य है।

टिप्पणी :- आजकल राजस्व परिषद (Board of Revenue) उत्तर प्रदेश, संचालक के अधिकारों का प्रयोग करता है।

4. नियुक्ति प्राधिकारी (appointing authority) :- कलेक्टर अपने जिले में रजिस्ट्रार कानूनगो और सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

5. कोटि (काडर) :- (1) इस सेवा के पदों की संख्या और उसके प्रत्येक वर्ग के पदों की संख्या वही होगी जो राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) इस सेवा के स्थायी पदों की संख्या और उसके प्रत्येक वर्ग के पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसको परिवर्तित करने की आज्ञा न दे दी जाय, निम्नलिखित होगी-

रजिस्ट्रार कानूनगो ... 214

सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो ... 611

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि :-

(क) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पदों का, जिनकी आवश्यकता प्रतीत हो, सृजन करके इस सेवा के पदों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं।

(ख) कलेक्टर किसी भी रिक्त पद को खाली छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल उसको आस्थगित रख सकता है (may hold in abeyance) किन्तु इससे किसी भी व्यक्ति को प्रतिकर पाने का अधिकार उत्पन्न न होगा।

6. वेतन :- रजिस्ट्रार कानूनगो या सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर नियुक्त किये गये व्यक्ति का चाहे उसकी नियुक्ति स्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से या अस्थायी प्रकार से हुई हो, वेतन-क्रम निम्नलिखित होगा-

(1) रजिस्ट्रार कानूनगो ... 60-4-80-को० बा०-5-105 को बा०-120 रु०
तथा-15 रु० प्रति मास का विशेष वेतन।

(2) सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो ... 60-4-80-को० बा०-5-105- को० बा०-120 रु०।

संक्षिप्त टिप्पणी

समता सीमित की संस्तुतियों के आधार पर वेतन मान संशोधित कर दिये गये हैं। राज्य सरकार ने इनको दिनांक 1-1-1986 से लागू करने की स्वीकृति दे दी है।

उत्तर प्रदेश अवर राजस्व लिपिक

7. भर्ती के स्रोत :- रजिस्ट्रार कानूनगो की कोटि में भर्ती स्थायी सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो की, जिनकी कम से कम तीन वर्ष की सेवा हो गई हो, पदोन्नति द्वारा की जायेगी और सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो की कोटि में भर्ती कम से कम 6 वर्षों की सेवा वाले लेखपालों की पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

टिप्पणी :- ऐसा पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कानूनगो भी जो अपनी दीर्घ आयु अथवा निर्बलता के कारण पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कानूनगो के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुपयुक्त हो, रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जायेगा।

8. भर्ती करने की प्रणाली :- (1) नियम 7 के अधीन रजिस्ट्रार कानूनगो की भर्ती के प्रयोजनों के लिए चयन ऐसे स्थायी सहायक रजिस्ट्रार कानूनगोओं में से ज्येष्ठता के आधार पर किया जायगा, जिनकी उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें चयन किया जाय, तीन वर्षों की सेवा पूरी हो गयी हो, किन्तु अनुपयुक्त व्यक्तियों को नहीं लिया जायगा।

(2) (क) सहायक रजिस्ट्रार कानूनगोओं की भर्ती के प्रयोजनों के लिए उन लेखपालों में से जो इस उप-नियम के खण्ड (ख) के अधीन नामांकित किये गये हों, ज्येष्ठता के आधार पर चयन किया जायगा, किन्तु अनुपयुक्त व्यक्तियों को नहीं लिया जायगा।

टिप्पणी :- ऐसा अभ्यर्थी जो अनुपयुक्त होने के कारण न लिया जाय, केवल उसी अवसर के लिए अनुपयुक्त समझा जायगा और बाद को किये जाने वाले प्रत्येक चयन में उसके प्रसंग में सम्यक रूप से विचार किया जायगा।

(ख) कलेक्टर प्रत्येक वर्ष सितम्बर में, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो की जिले की कोटि में होने वाली रिक्तियों की लगभग संख्या मालूम करेगा और अपने जिले के प्रत्येक परगना अधिनियम 1952 शीतकालीन दौरे के पश्चात् ऐसे कुछ लेखपालों को, जिनकी संख्या वह निश्चित करेगा, नामांकित करेगा।

के लिए कहेगा, जिन्होंने लेखपाल के रूप में उस वर्ष की, जिसमें नामांकन किया जाय, पहली जनवरी को कम से कम 6 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, राज्य की जूनियर या हाई स्कूल परीक्षा (अंग्रेजी के साथ) या उसके समकक्ष या उससे ऊँची परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जिनकी आयु उस वर्ष की, जिसमें नामांकन किया जाय, पहली जनवरी को 35 वर्ष से अधिक न हो, और जो सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर उन्नति पाने के लिए उपयुक्त समझे जायें, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायगी, जिनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यताएं और सेवा लेखा अधिक अच्छा होगा।

(ग) कलेक्टर खण्ड (ख) के अधीन नामांकित सभी अभ्यर्थियों के प्रसंग पर विचार करेगा और अपने विवेक से उनमें से उतने व्यक्तियों से, जिन्हें वह आवश्यक समझे जिले के मुख्यावास पर साक्षात्कार करेगा।

(घ) पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जायगा:-

(1) पूर्व सेवा का विवरण,

(2) सत्यनिष्ठा,

(3) चरित्र, और

(4) बुद्धि वैभव (intelligence) और योग्यता, किन्तु प्राथमिकता उन व्यक्तियों को दी जायगी, जिनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यताएं और सेवा लेखा अधिक अच्छा हो।

(ङ) कलेक्टर उन लेखपालों के नामों की सूची तैयार करेगा जिनको उसने पदोन्नति के लिए चुन लिख हो। उक्त सूची में अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित खण्ड (च) में बताये हुए रूप में रखी जायगी:-

(च) उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन चुने हुए लेखपालों के नाम उस सूची में चढ़ाये जायेंगे जो कलेक्टर अपने जिले के लिए रखता है। सूचीगत अभ्यर्थियों के नाम उनके चयन के दिनांक के अनुसार रखे जायेंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक ही दिनांक पर चुने लेखपालों के पारस्परिक नाम चयन के पूर्व उनके मूल वेतन के अनुसार रखे जायेंगे, और यदि उनके वेतन बराबर हों तो उनकी सेवा की दीर्घकालीनता के अनुसार रखे जायेंगे। उक्त सूची में लेखपालों की संख्या उन रिक्तियों की संख्या की लगभग दो तिहाई होगी जिनकी जिले के सहायक रजिस्ट्रार कानूनगोओं की कोटि (cader) में तीन वर्ष की अवधि में होने की सम्भावना है, किन्तु जिले के लिए स्वीकृत सहायक रजिस्ट्रार कानूनगोओं की संख्या की दो तिहाई से कम नहीं होगी।

9. सूची से नामों को हटाना :- (1) कलेक्टर सूची में रखे ऐसे गये लेखपाल का नाम जिसे चयन करने के दिनांक से उसके कार्य तथा आचरण की दृष्टि से उक्त सूची में रखना न्यायसंगत न हो, उसके सम्बन्ध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध उसे कारण प्रस्तुत करने का यथोचित अवसर देने के पश्चात्, पूर्वोक्त नियम 8 के खण्ड (च) में उल्लिखित सूची से किसी भी समय हटा सकता है अथवा सूची में उसे नीचे स्थान पर रख सकता है। सूची में रखे गये ऐसे लेखपाल का नाम भी, जिसकी आयु 45 वर्ष की पूरी हो गई हो और जो सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर स्थायी नियुक्ति न पा सका हो, उक्त सूची से हटा दिया जायगा, किन्तु ऐसे सूचीगत लेखपाल का नाम जिसकी 45 वर्ष की आयु किसी रिक्ति में स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुए पूरी हुई हो, उस सूची में तब तक बना रहेगा जब तक वह स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहे अथवा अपनी स्थानापन्न नियुक्ति में कार्य करते हुए अन्त में किसी स्थायी रिक्ति में नियुक्त हो जाय।

(2) संचालक किसी प्रसंग विशेष में किसी लेखपाल को यथोचित व्यवहार अथवा सार्वजनिक हित की दृष्टि से आयु की सीमा अथवा शिक्षा सम्बन्धी योग्यता से मुक्त कर सकता है।

(3) किसी लेखपाल के सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर नियुक्ति के लिए चयन न किये जाने अथवा 45 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के आधार पर सूची से लेखपाल का नाम हटा दिये जाने के विरुद्ध अपील नहीं होगी, किन्तु सूचीगत लेखपाल को नियम 9 के अधीन रखी जाने वाली सूची से अपना नाम हटाये जाने अथवा उस सूची में नीचे स्थान पर रख दिये जाने अथवा उक्त सूची में अपने स्थान के अनुसार नियुक्ति न पाने के विरुद्ध संचालक को अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा।

10. परीक्षण :- (1) नियम 8 (1) के अधीन सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो की किसी मूल रिक्ति अथवा उस पर नियुक्त किया गया कोई स्थायी लेखपाल एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षण पर रखा जायगा।

टिप्पणी :- सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर स्थानापन्न अथवा अस्थायी रूप से की गई सेवा, चाहे वह अखण्ड हो या सखण्ड, परीक्षण की अवधि की गणना करने में सम्मिलित कर ली जायेगी।

(2) कलेक्टर अपने विवेक से परीक्षण की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है। इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की आज्ञा से उस निश्चित दिनांक का उल्लेख किया जायगा, जब तक उक्त अवधि बढ़ाने की स्वीकृति दी गयी है।

(3) यदि परीक्षण की अवधि में या उसके अन्त में अथवा परीक्षण की बढ़ायी गयी अवधि में किसी भी समय यह मालूम हो कि उक्त कर्मचारी ने अपने समय का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्य प्रकार से अपना आचरण या व्यवहार सन्तोषजनक रीति से रखने में असफल रहा है, कलेक्टर सिविल सर्विसेज (क्लीसीफिकेशन कंट्रोल एण्ड अपील) रूलस के नियम 55 के उप-नियम) में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् उसे किसी प्रकार का प्रतिकर पाने का अधिकार दिये बिना ही, उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर देगा।

11. स्थायीकरण (Confirmation) :- परीक्षण की अवधि अथवा परीक्षण की बढ़ायी गयी अवधि के समाप्त होने पर कलेक्टर किसी अभ्यर्थी को यदि उसका कार्य तथा आचरण सन्तोषजनक रहा हो, उसके पद पर पक्का कर देगा।

12. पक्ष प्रचार :- (1) भर्ती के लिए इन नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों के अतिरिक्त किसी भी लिखित या मौखिक सिफारिश पर नियम 9 (2) के अधीन सूचीबद्ध करने के निमित्त चयन में अथवा नियम के अधीन नियुक्ति करने में विचार नहीं किया जायगा, अथवा।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी अन्य साधनों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने पक्ष में समर्थन-प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तो वह चयन के लिए अनर्ह हो जायगा।

13. कलेक्टर को रजिस्ट्रार कानूनगो तथा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो को छुट्टी देने और उससे हानि होने वाली रिक्तियों पर स्थानापन्न व्यवस्था करने का अधिकार है।

14. बदली :- रजिस्ट्रार कानूनगोओं तथा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगोओं की जिले के भीतर बदली कलेक्टर द्वारा, डिवीजन के एक जिले से दूसरे जिले में कमिश्नर द्वारा और राज्य में एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में बदली संचालक द्वारा की जायगी।

15. भू-मापन (सर्वे) या अभिलेख या बन्दोबस्त क्रियाओं में नियोजन :- किसी क्षेत्र में भू-मापन (सर्वे), अभिलेख, बन्दोबस्त अथवा चकबन्दी की क्रियाओं के होते समय रजिस्ट्रार कानूनगो और उसका सहायक कानूनगो, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), जैसी भी दशा हो, के अधीन और उसके नियंत्रण में होंगे और उन्हें ऐसा कार्य करना आवश्यक होगा, जो उक्त अधिकारी उनसे करने के लिए कहें। ऐसी अवधि में उक्त अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी/या बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) दण्ड देने के अधिकार का प्रयोग करेंगे, किन्तु पद से हटाने तथा पदच्युत करने के अधिकारी का जो नियुक्ति अधिकारी में निहित होता है, प्रयोग नहीं करेंगे।

16. सेवा की अन्य शर्तें : उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था इन नियमों में की गयी है, वेतन, छुट्टी, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें भारत के अधिकार के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धक के अधीन बनाये हुए नियमों द्वारा नियमित होगी और ऐसे नियमों के जारी होने तक 14, नवम्बर, 1930 की विज्ञप्ति संख्या ए-5822/10-303 और 16 जुलाई 1937 को विज्ञप्ति संख्या जी-698/10-534-44 द्वारा लागू किये गये नियमों द्वारा और गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 (जो अब निवर्तित हो गया है) की धारा 241 (2) (ख) के अधीन तैयार किये गये और संविधान के अनुच्छेद 313 द्वारा प्रचलित रखे गये नियमों द्वारा नियमित होंगे।

आज्ञा से,
जहूरल हसन
सचिव

CHAPTER XIII

Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970¹

PART I

Preliminary

1. Short title, and commencement :- (1) These rules may be called Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970.

(2) They shall come into force at once.

2. Extent of application :- These rules shall apply to all services and posts in connection with the affairs of Uttar Pradesh to which recruitment by promotion is required to be made by selection in consultation with the Uttar Pradesh Public Service Commission otherwise than the result of a competitive Examination.

3. Overriding effect of these Rules :- The Provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith in any service rules in force immediately before the commencement of these rules.

4. Definitions :- In these rules, unless the context otherwise requires :

- (a) "appointing authority" in relation to any service or post means the authority empowered to make appointment to that service or Post, and in the case of the Governor being the appointing authority includes the Chief Secretary to Government or the Secretary to Government in the Department concerned.
- (b) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission;
- (c) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;
- (d) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
- (dd) ²[X X X]
- (e) "Service rules" means rules, regulation or government orders regulating recruitment to, or the conditions of service of persons appointed to, any service or post in connection with the affairs of Uttar Pradesh;
- (f) "year of recruitment" means the period of twelve months beginning from the first day of July of a calendar year.

Short Notes

The duty of Public Service Commission is to make available to the Government a complete list of qualified candidates arranged in order of merit.

Public Service Commission is an independent body to ensure selection of best available persons for appointment to a post to avoid arbitration and nepotism in the matter of appointment. The selection is to be made by the Commission and the Government has to fill up the post by appointing these selected and recommended by the Commission according to the order of merit in the list of candidates sent by the Public Service Commission. The commission is required to make the recommendation only and the final authority for appointment is the Government.

1. Notification No. 42/4/66 Appdt. (B)
dated Lucknow, October 6, 1970.

2. Clause (dd) of Rule 4 has been deleted by
Noti. No. 15/66/81-Karmik-1 dated 24-7-1987

U. P. Promotion by Selection in Consultation with P.C.S. (Procedure) Rules, 1970 83

The Government may accept the recommendation or decline to accept it. In the case of non acceptance of the recommendation of the Commission, the Constitution enjoins upon the State to state the reasons and laying the report before the House of Legislature for so doing. The Government is thus answerable to the House for any departure under Article 321 of the Constitution. 1989 (1) SLJ SC 364; AIR 1984 SC 1850; 1973 (2) SLR 137; AIR 1987 SC 169.

PART II

Criteria for Promotion

5. **Criterion for promotion :-** (1) Where any service rules provide either "strict merit" or "primarily on merit" or "rigorous selection on merit from the whole field of eligibility" or "strictly on merit" or "seniority counting where merits are equal" or any such other criterion, howsoever expressed, as lays primary stress on merit as the basis of selection for promotion the criterion to be followed on and after the commencement of these rules shall be "merit".

(2) Where any service rules provide either "seniority" or "seniority cum fitness" or "seniority subject to the rejection of the unfit" or any such other criterion, howsoever expressed, as lays primary stress on seniority as the basis of selection for promotion, the criterion to be followed on and after the commencement of these rules shall be "seniority subject to the rejection of the unfit".

(3) In all cases in which no service rules exist, or in which the service rules do not lay down clearly which of the two criteria for promotion mentioned in sub-rules (1) and (2) is to be followed, such criterion of the two shall be followed as may be decided upon by the Governor in consultation with the Commission.

¹6. **Others conditions of eligibility :-** (1) Nothing in these rules shall affect any provision in any service rule in respect of the conditions of eligibility for promotion relating to age, educational or technical qualifications, nature of experience or length of service except to the extent that the relevant date with reference to which a candidate shall be deemed to have fulfilled such conditions shall be the date of commencement of the year of recruitment.

(2) In the absence of any provision in the service rules in respect of the conditions of eligibility as aforesaid, the said conditions shall be such as may be determined by the Governor in consultation with the Commission.

²(3) Deleted.

PART III

Procedure of Promotion where the Criterion is Merit.

7. **Application of this part :-** Where by virtue of the provisions of rule 5 promotion is to be made on the criterion of merit, the procedure laid down in this Part shall be followed.

[7-A. Re-arrangement of the Select List :- X X X]

³[7-B. Appointment from Select List :- X X X]

1. Substituted by G. O. No. 42/4/1966-Apppt-3, dated July 4, 1972 with effect from 6.10.70.
2. Deleted by Notification No. 42/4/1966-Apppt, 3 dated 4-7-1972 (w.e.f. 1-10-70).

3. Rule 7-A and 7-B have been deleted by Notification No. 15/66/81-Karmik-1 dated 24-4-1987.

8. Preparation of eligibility list :- The appointing authority shall prepare a list (hereinafter in this Part referred to as the eligibility list) of the senior-most eligible candidates containing names so far as may be, in the following proportion. ¹[3 time the number of vacancies subject to the minimum of 8]

Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such years in such a case while preparing the eligibility list for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be-

- | | | |
|-------------------------|-----|--|
| (a) for the second year | ... | the number of according the said proportion plus the number of vacancies in the first year; |
| (b) for the third year | ... | the number according to the said proportion plus the number of, vacancies in the first and second years; |

and so on :

Provided further that candidates who are not considered suitable, prima facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a not to the effect that they are not so considered shall be added against their names :

Provided also that in the case of higher research posts in departments in which research work is done, the names of all eligible candidates shall be included in the list irrespective of the number of vacancies.

²[Provided also that if eligibility list is being prepared for substantive vacancies, the names of candidates who have previously been appointed in temporary or officiating vacancies from List B shall be included in the eligibility list if otherwise found eligible]

Explanation I :- In this rule -

- (a) "the number of vacancies" means the total number of substantive, temporary or officiating vacancies occurring during the year of recruitment. ³[X X X]
- (b) "higher research posts" means posts requiring technical knowledge and ability or a high order for undertaking and guiding research work.

Explanation II :- A single eligibility list shall be prepared to cover all types of vacancies.

9. Sending of lists to Commission :- The appointing authority shall forward to the Commission the eligibility list or lists together with the gradation list of all persons within the field of eligibility and the character rolls of the candidates included in the eligibility list or lists, and also intimate to it the number of different types of vacancies taken into account for the purpose of preparing the list or lists.

10. Revision of eligibility list :- If in any case the Commission feels that requisite number of suitable candidates may not be available from amongst those whose names are included in the list or lists received by it under rule 9, it may ask the appointing authority to include therein the names and character rolls of such larger number of the

1. Subs. by *Ibid.*

2. Inserted by Not. No. 15/66/81-Karmik-1 dated April 24, 1987 with immediate effect.

3. Omitted by *Ibid.*

U. P. Promotion by Selection in Consultation with P.C.S. (Procedure) Rules, 1970 85

senior-most, or of all eligible candidates, as it thinks fit, and the appointing authority shall notwithstanding anything contained in rule 8 revise the list or lists accordingly.

11. Selection Committee :- A Selection Committee consisting of the following shall be constituted by the appointing authority-

- (i) the Chairman or Member representing the Commission who will be the Chairman of the Committee;
- (ii) the appointing authority; and
- (iii) a senior officer of that or any other department nominated by the Government, provided that where the appointing authority is the Governor the head of that department shall ordinarily be nominated under this clause.

12. Fixing of dates for selection :- (1) The appointing authority shall in consultation with the Commission fix a date for selection :

Provided that the process of selection may spread over the dates more than once.

(2) In case the Commission or the appointing authority considers it necessary that all or any of the candidates included in the eligibility list or lists should be interviewed by the Selection Committee, the appointing authority shall call such candidates or candidate, as the case may be for the purpose on the aforesaid date or dates.

(3) The Selection Committee shall in each case consider the character rolls of the candidates and may other factor relevant in its opinion.

13. Lists A and B :- (1) the Selection Committee shall prepare two lists, in order of merit, as follows, namely :

- (i) List A - Containing names of candidates recommended for substantive appointment against the permanent vacancies intimated to the Commission under rule 9 :
- (ii) List B - Containing names of candidates recommended for temporary or officiating appointments intimated to the Commission under rule 9 ¹[X X X]

Provided that if recruitment is made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, the selection in respect of each such year shall be made from the eligibility list prepared for that year. In such a case, the names of candidates selected against vacancies of one year will be excluded from the eligibility list or lists of subsequent year or years, as the case may be, before making the selection from eligibility lists of the second and subsequent years.

(2) [X X X X]

14. Commission approval :- The Commission shall consider the recommendations of the Selection Committee and thereafter send the Lists A and B as approved to the appointing authority.

²[**15. Re-arrangement of each List in order of Seniority :-** The appointing authority shall, rearrange each of the Lists A and B in order of seniority.]

16. Duration of lists :- [X X X]

17. Appointment from List 'A' :- (1) Candidates included in List A shall be appointed against permanent vacancies in the order in which their names appear in the List as rearranged under rule 15.

1. Omitted by Notification No. 15/66/81-
Karmik-1 dated 24.4.1987.

2. Substituted by *Ibid.*

(2) Candidates included in List A, for whom permanent vacancies are not immediately available, shall be appointed, in the said order, against temporary or officiating vacancies in preference to those included in List B.

¹[18. Appointment from List 'B' :- Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 17, candidates included in List B shall be appointed in the order in which their names appear in the List as re-arranged under rule 15 against temporary or officiating vacancies.

Provided that if it appears to the appointing authority at any time that a government servant appointed against a temporary or officiating vacancy has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, it may revert him to the post from which he was promoted without assigning any reason.

19. Absorption of List B candidates in substantive vacancies :- Subject to the provisions of rule 8, candidates remaining in List B shall be appointed against fresh substantive vacancies in preference to any candidate selected for List A at the succeeding year of recruitment for the first Time.

PART IV

Procedure of Promotion

Where the Criterion in seniority subject to the rejection of the unfit.

20. Application of this Part :- Where by virtue of the provisions of rule 5, promotion is to be made on the criterion of seniority subject to the rejection of the unit, the procedure laid down in this Part shall be followed.

²[21. (1) Except as otherwise provided in Rule 22, the appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior most eligible candidates from each of the sections namely general, Scheduled Caste and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said sections containing names so far as may be in the following proportion :

For one to five vacancies :- Two times the number of vacancies subject to a minimum of five.

For over five vacancies :- One and half time the number of vacancies subject to a minimum of 10. The proviso and explanations to Rule 8 shall *mutatis mutandis* apply to this rule.

(2) The rest of the procedure prescribed in part III shall *mutatis mutandis* apply to promotion made under this Part except that each of the two Lists A and B referred to in Part III shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit and that from among those considered fit the senior-most candidates shall be placed in List A.

22. Power to dispense with Selection Committee in certain case :- Notwithstanding anything in rule 21 if in any case the number of vacancies to be filled is small, and the appointing authority considers the senior-most candidate or candidates clearly fit for promotion and accordingly no supersession is involved, the Commission may, if it agrees with the view of the appointing authority, approve the proposal straightway. In that case no Selection Committee need be constituted and the candidate so approved shall be deemed to have been duly selected for promotion.

1. Substituted by Notification No. 15/66/81
Kramik-I dated 24-4-1987 with immediate effect.

2. Subs. by Notification No. 15/38/84-K-I,
dated 21-6-1984, Published in U. P. Gazette,
dated 5-1-1985.

U. P. Promotion by Selection in Consultation with P.C.S. (Procedure) Rules, 1970

Notifications G. O. No. 19/7/72-Appoint-3 dated May 10, 1973

विषय : लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से अस्थायी पदों के लिये चुने गये व्यक्तियों की उन पदों के स्थायी होने पर मौलिक नियुक्ति।

Subject : Persons directly recruited by the Service Commission in temporary vacancy, to be taken when post becomes Permanent.

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2949/2-बी-100-1953, दिनांक 10 दिसम्बर 1953 के प्रस्तर 2 (2) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें दिये गये अनुदेशों के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित बिल्कुल स्थायी पदों के लिए अथवा जिनके एक निर्दिष्ट अवधि तक ही चलते रहने की सम्भावना हो, चुने गये व्यक्तियों की उन पदों के स्थायी हो जाने पर मौलिक नियुक्ति (सब्सटेन्टिव एम्प्लॉयमेंट) हेतु आयोग से पुनः परामर्श करना आवश्यक होता है। इस सम्बन्ध में शासन ने, लोक सेवा आयोग की सहमति से, यह निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में मौलिक नियुक्ति देने के लिये अब आयोग से पुनः परामर्श करना आवश्यक न होगा, यदि उन पदों पर भर्ती की अर्हताओं या अन्य सेवा शत में कोई परिवर्तन न किया गया हो।

संख्या 19/4/74-नियुक्ति-3

दिनांक 20 अप्रैल, 1974

विषय : लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थियों के बारे में पूछ-ताछ की मनाही।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की जानकारी में एक ऐसा मामला आया है, कि जिसमें लोक सेवा आयोग ने एक अभ्यर्थी की तदर्थ नियुक्ति की अनुमोदित नहीं किया क्योंकि वह अर्ह नहीं पाया गया। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह पूछे जाने पर कि उस अभ्यर्थी को किस आधार पर अर्ह नहीं पाया गया लोक सेवा आयोग ने आपत्ति की है और कहा है कि अभ्यर्थी की अर्हताओं के आंकने का अधिकार मात्र आयोग को है।

2- लोक सेवा आयोग की परिधि में रखे गये पदों पर भर्ती करने का दायित्व आयोग का है। अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में आयोग स्वतन्त्र है तथा किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करना अथवा चुनाव सम्पन्न हो जाने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी के मामले को लेकर, जो चुना नहीं गया, आयोग से पूछ-ताछ करना अत्यन्त अवांछनीय है। अतः आप से अनुरोध है कि चुनाव फल प्राप्त हो जाने पर आप ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में, जो चुने नहीं जा सके, आयोग से कोई पूछ-ताछ न करें।

Notification No. 19/5/74 Appointment-3 dated May 27, 1974

विषय :- सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति पर रोक।

Subject :- Prohibition of adhoc appointments/promotions under Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulation, 1954.

अधोहस्ताक्षरी को नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 35/13-69-नियुक्ति (ख), दिनांक 19 दिसम्बर, 1969 की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम 1954 के विनियम 5 या 6 (ग) के अधीन तदर्थ, स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियों/प्रोन्नतियों के विनियमन हेतु (क) लोक सेवा आयोग को यथा समय सूचित किया जाना चाहिये तथा आवश्यकतानुसार उनका अनुमोदन भी प्राप्त कर लेना चाहिये। शासन की जानकारी में यह बात आई है कि नियुक्ति प्राधिकारी तदर्थ नियुक्तियों/प्रोन्नतियों को विनियमित करने के

लिये लोक सेवा आयोग को बहुधा काफी विलम्ब से लिखते हैं। कभी-कभी तो तदर्थ नियुक्तियां वर्षों तक चलती रहती हैं। कुछ मामलों में सम्बन्धित व्यक्ति उन पदों से अन्यत्र भी चले गये होते हैं अथवा एक तदर्थ नियुक्ति समाप्त होने पर दूसरे पद तदर्थ रूप से नियुक्त हो चुके होते हैं। तदर्थ पदोन्नतियों के मामलों में भी ऐसा ही होता है। यह स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है।

2- शासन इस बात पर पुनः जोर देना चाहता है कि तदर्थ नियुक्तियां/प्रोन्नतियां यथासम्भव न की जायें। यदि लोक हित में ऐसा करना अनिवार्य हो जाय तो यह नियुक्तियां, प्रोन्नतियां कम से कम अवधि के लिये होनी चाहिये। यदि इस व्यवस्था की एक वर्ष से अधिक समय तक चलने की सम्भावना हो, तो प्रारम्भ में ही उसके विनियमन हेतु लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज देना चाहिये। शासन अपेक्षा करता है कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस सम्बन्ध में की गई ढिलाई को कड़ी दृष्टि से देखा जाये।

3- अनुरोध है कि इन आदेशों से समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को अवगत कर दिया जाय और सचेत कर दिया जाय कि वे इनका कड़ाई से पालन करें।

संख्या 19/7/1974-नियुक्ति (3) दिनांक 10 जून, 1975

विषय :- नियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में आदेश जारी किया जाना।

Subject :- Issue of orders in connection with regular appointment.

मुझे आपका ध्यान शा० आ० संख्या 4936/2-बी-125-1961 दिनांक 6 फरवरी, 1965 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम 1954 के विनियम 5 (क) अथवा 6 (ग) के अधीन की गई तदर्थ नियुक्तियों अथवा प्रोन्नति के समस्त मामलों में, यदि बाद में वही व्यक्ति लोक सेवा आयोग के परामर्श से उन पदों पर नियमित नियुक्तियों के लिए चुन लिये जायें अथवा अनुमोदित कर दिये जायें तो नये आदेश पुनः अनिवार्य रूप से जारी किया जाना चाहिये। इन आदेशों में नियमित नियुक्ति की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये और यह भी सूचित कर देना चाहिये कि सम्बन्धित व्यक्ति को लोक सेवा आयोग के परामर्श से पद पर बने रहने की अनुमति दी गई है। इन आदेशों की प्रतिलिपि आयोग को भी पृष्ठांकित की जानी चाहिये।

2- लोक सेवा आयोग ने शासन की जानकारी में यह बात लाई है कि उक्त आदेशों का सर्वत्र पालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। नियमित नियुक्ति के वांछित आदेश जारी न करने से अभ्यर्थी अपनी सेवा सम्बन्धी स्थिति से अनभिज्ञ रहता है और पुनः उसी पद के लिये आवेदन करता है जिससे आयोग का भी काम बढ़ जाता है। अतः अनुरोध है कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि भविष्य में उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

का० ब्राप संख्या-4/2/1977 (14)-कार्मिक-1, दिनांक 30 जनवरी, 1979

विषय :- घोषित परीक्षाफल की आबंटन सूची में परिवर्तन न किया जाय।

अधोहस्तधारी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के आधार पर प्रदेश की कतिपय राज्य सेवाओं में सीधी भर्ती की जाती है। इस परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा जिन अभ्यर्थियों की संस्तुति की जाती है उनका आबंटन उनकी परीक्षा में श्रेष्ठता तथा उनके द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिये दी गई अधिमान्यता के आधार पर विभिन्न सेवाओं में आबंटन कर दिया जाता है। आबंटन हो जाने के उपरान्त संबंधित विभाग आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने के उपरान्त संबंधित व्यक्तियों के नियुक्ति के आदेश जारी कर देते हैं।

U. P. Promotion by Selection in Consultation with P.C.S. (Procedure) Rules, 1970 89

2- सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी होने के उपरान्त कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जिन अभ्यर्थियों को किसी विशेष सेवा के लिये आबंटित किया जाता है वे उन पदों का कार्यभार ग्रहण न करके कहीं अन्यत्र सेवा में चले जाते हैं। उदाहरणस्वरूप जो अधिकारी पी० सी० एस० के लिये आबंटित किये जाते हैं उनमें से कुछ पी० सी० एस० अथवा एलाइड सेवाओं में भर्ती हेतु चुन लिये जाते हैं ऐसा होने पर वे पी० सी० एस० में नियुक्ति का आफर स्वीकार न करते हुये कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार की जो रिक्तियां होती हैं उन्हें अन्य सेवाओं में आबंटित अथवा प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों में की जाती रही है। कतिपय ऐसे अवसर आये हैं कि पूर्व में किये आबंटन में परिवर्तन कई वर्षों के बाद किये जाते हैं जिससे अनेक व्यवहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। इन कठिनाइयों के निराकरण हेतु शासन के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन रहा है कि सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के आधार पर विभिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त कोई समय निर्धारित कर दिया जाय जिसके बाद किसी परीक्षा विशेष के परीक्षाफल के आधार पर अभ्यर्थियों का आबंटन न किया जाय।

3- शासन ने समुचित विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के दिनांक से एक वर्ष के बाद किसी भी सेवा में हुई रिक्तियों के लिये किये गये आबंटनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा और उक्त रिक्तियों के लिये उस परीक्षाफल का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4- यह आदेश तुरन्त लागू होंगे। इन आदेशों के जारी होने के पूर्व किसी परीक्षा में परीक्षाफल के आधार पर लोक सेवा आयोग के परामर्श से मूल आबंटन में किये गये परिवर्तन इन आदेशों से प्रभावित नहीं होंगे।

CHAPTER VI

Uttar Pradesh Subordinates Revenue Executive (Tahsildar) Service Rules, 1966

This was published on pages 1244-1248 of Part I-Ka of the U. P. Gazette dated 30 April, 1966. This is as under :

भाग 1 - सामान्य

1. संक्षिप्त शीर्षक नाम तथा प्रारम्भ :- (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा नियमावली, 1966" कहलायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्ति होगी।

2. सेवा की प्राप्ति तथा नियन्त्रण :- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा राष्ट्रपति प्राप्ति की एक अधीनस्थ सेवा है। यह राजस्व परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् पदच्युति, हटाने या पदावनति को छोड़कर स्थानान्तरण करने, तैनात करने तथा दण्ड देने के सम्बन्ध में अपने किन्हीं कृत्यों तथा अधिकारों को अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारियों को प्रतिनिहित कर सकती है।

3. परिभाषाएँ :- (1) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में :

(क) 'परिषद्' का तात्पर्य 'राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश' से है;

(ख) 'आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है;

(ग) 'आयुक्त' का तात्पर्य किसी डिवीजन के आयुक्त से है;

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(ङ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त राज्य सेवक से है;

(छ) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; और

(ज) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा से है।

भाग 2 - संवर्ग

4. सेवा के पदों की संख्या :- (1) सेवा की पदों की और उसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।

(2) सेवा के पदों की ओर उसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार के पदों की स्थायी संख्या, जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, निम्नलिखित होगी :

(1) जिलों के लिए स्वीकृति सामान्य कर्मचारी वर्ग

225

(2) विविध तथा विशेष पद (इसके अन्तर्गत भूमि अर्जन उप-अधिकारी

के 7 पद, तहसीलदार, आयकर, कानपुर का 1 पद, सहायक सचिव,

श्री बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का 1 पद और सहायक प्रशासनिक

अधिकारी, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का पद भी सम्मिलित है),

10

(3) प्रति-नियुक्ति कर्मचारी (उपर्युक्त [1]) के 10 प्रतिशत से	...	22
(4) अवकाश कर्मचारी (उपर्युक्त (1) और (2)) के 10 प्रतिशत से	...	23

	योग	280

प्रतिबन्ध यह कि राज्यपाल, समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित करके जो आवश्यक समझे जायें, संवर्ग से पदों की संख्या बढ़ा सकते हैं।

प्रतिबन्ध यह भी है कि परिषद् किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकती है अथवा राज्यपाल उसे स्थगित रख सकते हैं और ऐसा किये जाने पर कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

भाग 3 - भर्ती

1[5. भर्ती का स्त्रोत :- सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से पदोन्नति द्वारा की जायेगी-

- (1) 89 प्रतिशत रिक्तियाँ नायब तहसीलदारों में से
- (2) 4 प्रतिशत रिक्तियाँ कुमायूँ और गढ़वाल डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के पेशेकारों में से;
- (3) 7 प्रतिशत रिक्तियाँ सदर कानूनगो (सहायक भूलेख अधिकारी) में से।

टिप्पणी :- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग 4 - अर्हतायें

2[6. पात्रता :- 'सेवा में भर्ती के प्रयोजन के लिये योग्यता के आधार पर चयन, नियम 5 में विनिर्दिष्ट ऐसे स्थायी कार्मिकों में से किया जायेगा जिन्होंने उस वर्ष की पहली जुलाई को जिस वर्ष चयन कि जाय, अपने मूल पद पर मौलिक और स्थानापन्न रूप में कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।'

भाग 5 - भर्ती के लिए प्रक्रिया

7. रिक्तियों का अवधारण :- "परिषद् भर्ती के वर्ष के दौरान नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 5 के नीचे दी गयी टिप्पणी के अनुसार अनुसूचित जातियों, सूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।"

8. 3[* * *]

9. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :- "पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार योग्यता के आधार पर की जायेगी।"

भाग 6 - नियुक्ति, परीक्षा तथा स्थायीकरण

10. ज्येष्ठता :- सेवा में ज्येष्ठता, मौलिक रिक्त में नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निर्धारित की जायेगी।

1. नियम 5 के जगह पर प्रतिस्थापित किया गया-नोटिफिकेशन नं० 3-3 (1) 87-72 रा०-9 दि० 9 जुलाई 1990 जो कि सरकार गजट दि० 11-8-90 को प्रकाशित हुआ।
2. नियम 6 व 7 के जगह पर प्रतिस्थापित किया गया जो नं० 3-3- (1) 87-72 रा० - 9 दि० 8-7-90 जो कि सरकारी गजट दि० 11-8-90 को प्रकाशित हुआ।
3. निकाल दिया गया।

प्रतिबन्ध यह है कि :

- (क) एक ही सेवा से एक ही दिनांक को चुने गये अभ्यर्थियों की पारस्परिक श्रेणी उक्त सेवा में उनकी ज्येष्ठता के अनुसार होगी, और
- (ख) विभिन्न सेवाओं से एक ही दिनांक को चुने गये अभ्यर्थियों की श्रेणी उनकी अपनी-अपनी सेवाओं में मौलिक नियुक्ति के अनुसार होगी और यदि मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक ही होगी तो उनके मौलिक वेतन के अनुसार होगी।

11. नियुक्ति :- (1) परिषद् सेवा से मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियम 9 (6) के अधीन तैयार की गयी प्रथम सूची से उन पर नियुक्तियाँ करेगी।

(2) (क) ऐसी समस्त अस्थायी तथा स्थानापन्न रिक्तियों की पूर्ति जिनकी तीन महीने से अधिक चलने के सम्भावना न हों, सम्बद्ध जिलाधिकारी नियम 3 (6) के अधीन तैयार की गयी 'प्रवर सूची' से कर सकता है, किन्तु यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सबसे उपयुक्त कर्मचारी जो नियमावली के अधीन पदोन्नति के लिये पात्र हों, नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) तीन महीने से अधिक किन्तु एक वर्ष से अधिक अनधिक अवधि के लिए चलने वाली ऐसी समस्त रिक्तियों की पूर्ति जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर परिषद् 'प्रवर सूची' से करेगी और जब यह सूची निःशेषित हों जाय तो इस नियमावली के अधीन भर्ती के पात्र कर्मचारियों में से करेगी। किन्तु साथ ही साथ ऐसी नियुक्ति करने पर आयोग को भी सूचना दी जायेगी जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित होगा कि नियुक्ति इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन की गयी है।

(3) इस नियमावली के अधीन की गयी समस्त नियुक्तियाँ सरकारी गजट में विज्ञापित की जायेगी।

12. परिवीक्षा अवधि :- मौलिक रिक्तियों में अथवा उनके प्रति, नियुक्ति किये जाने पर सभी व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि परिवीक्षा अवधि की संगणना करने में सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर अथवा किसी उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा पर विचार किया जा सकता है।

13. परिवीक्षा अवधि का बढ़ाया जाना :- (1) परिषद् परिवीक्षा अवधि की एक वर्ष से अनाधिक और अवधि के लिए बढ़ा सकती है। परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी प्रत्येक परिवीक्षा अवधि के आदेश में वह ठीक दिनांक निर्दिष्ट होगा जब तक के लिए वह बढ़ायी गयी हो।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि में या उसके अन्त में किसी समय यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है अथवा या यह अन्य प्रकार से संतुष्ट करने में असफल रहा है, उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पद से उसकी पदोन्नति की गयी हो।

14. विभागीय परीक्षा :- (1) प्रत्येक व्यक्ति से चाहे वह भौतिक रिक्त में अथवा अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाय, यह अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसा प्रशिक्षण ले और ऐसे विषयों में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ले जो राज्यपाल, समय-समय पर नियमत करें।

प्रतिबन्ध यह है कि यह शर्त उस व्यक्ति की दशा लागू न होगी जो स्थानापन्न या अस्थायी रूप में एक वर्ष से कम अवधि के लिए नियुक्त किया जाय।

प्रतिबन्ध यह भी है कि एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त व्यक्ति से यह अपेक्षा न की जायेगी कि वह ऐसी परीक्षा में बैठे जो उसकी ऐसी नियुक्ति के दिनांक से छः महीने के भीतर की जाय।

(2) प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी प्रत्येक ऐसी अनुवर्ती परीक्षा में जिसमें उससे उप-नियम (1) के अधीन बैठने का अपेक्षा की जाय तब तक बैठेगा जब तक कि वह उत्तीर्ण न हो जाय अथवा जब तक कि वह बीमारी के कारण बैठ न सके अथवा परिषद् द्वारा तीन वर्ष की सीमा तक उसे विशेष रूप से मुक्त न कर दिया जाये। बीमारी की दशा में चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा।

टिप्पणी :- विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा नियम उत्तर प्रदेश में विभागीय परीक्षाओं का संचालन और कनिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षण नियमावली "रूल्स फार द कन्डक्ट आफ डिपार्टमेंटल इक्जामिनेशन एण्ड द ट्रेनिंग आफ जूनियर-आफिसर्स इन उत्तर प्रदेश" नामक पुस्तिका में दिये हुए हैं :

15. परिवीक्षाधीन व्यक्ति यथा स्थिति अपनी परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि के अन्त में स्थायी कर दिया जायगा, यदि

- (1) स्थायीकरण :- उसने तहसीलदार की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;
- (2) आयुक्त यह रिपोर्ट दे कि वह स्थायी किये जाने के लिये उपर्युक्त है और उसकी सत्य-निष्ठा पर आपत्ति नहीं की जा सकती है; तथा
- (3) स्थायीकरण के लिये उसकी उपयुक्तता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय।

16. प्रत्यावर्तनों तथा परिवर्तनों की सूचना :- जिलाधिकारी, तहसीलदारों में होने वाली सभी प्रत्यावर्तनों तथा परिवर्तन की सूचना जैसे ही वे हों, आयुक्त तथा परिषद् को ऐसी रीति से देगा जो परिषद् नियत करें।

भाग 7 - वेतन

17. वेतन :- सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के लिये चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न रूप में नियुक्त हो या अस्थायी रूप में अनुमन्य वेतनमान निम्नलिखित होगा।

1 अप्रैल, 1947 को या उसके पश्चात् किन्तु 15 जनवरी, 1959 ई० के पूर्व नियुक्त व्यक्तियों के लिये :

200-10-250-द० रो० 15-400 रु०।

15 जनवरी, 1959 ई० को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1965 के पूर्व नियुक्त व्यक्तियों के लिये :

200-10-250-द० रो० 15-325-द० रो० 15-400।

1 अप्रैल, 1965 ई० को या उसके पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों के लिये : 225-15-300 द० रो०-15-360-20-380 द० रो०-20-500 रुपया।

संक्षिप्ती टिप्पणी

समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान संशोधित कर दिये गये हैं। राज्य सरकार ने इन वेतनमानों को दिनांक 1 जनवरी 1986 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है :

देखिये अध्याय XXXVIII

18. दक्षता रोक पर करने के लिए मानदण्ड :- किसी भी तहसीलदार को वेतन के कालमान में दक्षता रोक पार करने की तब तक अनुमति न दी जायगी जब तक कि उसके सेवा वृत्त से यह न पाया जाय कि उसने विशिष्ट योग्यता और पूरी ईमानदारी के साथ अविचलित रूप से कार्य किया है।

भाग 8 - अन्य उपबन्ध

19. पक्ष समर्थन :- भर्ती के लिए इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी भी सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो अथवा मौलिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य उपायों द्वारा अपनी अभ्यर्थता के लिए समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास, सेवा से नियुक्त किये जाने के लिये उसे अनर्ह कर देगा।

37

U. P. Subordinates Revenue Executive (Tahsildar) Service Rules, 1966

20. वेतन, छुट्टी, भत्ते तथा पेंशन आदि का विनियमन :- ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विशेष रूप से इस नियमावली या तदधीन दिये गये या जारी किये गये आदेशों अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, उन विनियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगे जो उत्तर प्रदेश शासन के सम्बन्ध में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हों।

21. इस नियमावली में किसी बात के होते हुये ऐसे अधिकारी जो किसी ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हों जो 15 अगस्त, 1927 ई० के पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य में विलीन हो गया हो अथवा जो इसके पश्चात् विलीन हो जाय, उस क्षेत्र के विलीन होने पर आयोग के परामर्श से संवर्ग के पदों पर नियुक्त किये जा सकते हैं और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को इस नियमावली के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया समझा जायगा।

22. उन मामलों में जिनमें अनुचित कष्ट हो, सेवा नियमावली में शिथिलता :- यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी विषय के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलों में अनुचित कष्ट होते हैं तो वे आयोग के परामर्श से भले ही उस मामले में लागू होने वाले नियमों में कोई बात दी हो, आदेश द्वारा, उन नियमों की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के आधीन रहते हुए अभियुक्त कर सकते हैं, जिन्हें वे उस मामले को ठीक और उचित रीति से निपटने के लिए आवश्यक समझें।

23. निर्वचन :- यदि इस नियमावली के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो उसे सरकार के राजस्व विभाग को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

CHAPTER VII

The U.P. Subordinate Revenue Executive Service (Naib Tahsildars) Rules, 1944

Notification No. 4333/I-21 N. T. T. 39, dated : Lucknow, December 11, 1994 :-
In pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 241 of the Government of India Act, 1935, and section 231 (a) of the United Provinces Land Revenue Act (III of 1901) and in supersession of all existing rules and order on the subject, the Governor of the United Provinces makes the following rules regulating appointment to posts in the Subordinate Revenue Executive Service (Naib Tahsildars), and the conditions of services of persons so appointed :

PART - I - General

1. Short title, extent and commencement :- These rules be called the U. P. Subordinate Revenue Executive Service (Naib-Tahsildars) Rules, 1944, and shall take effect from the date of their notification. They do not apply to Kumaun Division except as specified otherwise hereinafter.

2. Status of service :- The Subordinate Revenue Executive, Service (Naib-Tahsildars) is a subordinate service and shall be under the administrative control of the Board.

3. Definition :- In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context-

- (a) "the Act" means the Government of India Act, 1935;
- (b) "Board" means the Board of Revenue, United Provinces;
- (c) "Commission" means the United Provinces Public Service Commission;
- (d) "Direct Recruitment" means recruitment in the manner prescribed by rule 5 (i) of these rules;
- (e) "Government" means the Government of the United Provinces;
- (f) "Governor" means the Governor of the United Provinces ;
- (g) "Member of the Service" means a servant of the Crown appointed in a substantive capacity under the provisions of these rules or of rules in force previous to the introduction of these rules to a post in the cadre of the service ;
- (h) "Nature born British subject" has the meaning assigned to it in section I of the British Nationality and Status of Aliens Act. 1944 ;
- (i) "Service" means the Subordinate Revenue Executive Service (Naib Tahsildars).

Part II - Cadre and Recruitment

4. Cadre :- The strength of the Service is 238 divided into four grades as follows:

I Grade	30	
II Grade	45	
III Grade	70	238
IV Grade	93	

Provided that-

U. P. Subordinates Revenue Executive (Nah-Tahaldar) Rules, 1944

- (i) the Governor may increase the cadre by creating additional permanent or temporary posts from time to time as may be found necessary; and
- (ii) the Board may leave unfilled or the Governor may keep in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation.

5. Sources of Recruitment :- Recruitment to the service shall be made-

- (i) on the result of a competitive examination to be conducted by the Commission:
- (ii) by promotion from amongst Supervisor Kanungos :
- (iii) by selection of a Kanungo diplomate :
- (iv) by promotion from amongst such Collection Amins who have passed at least the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the U. P. Government as equivalent thereto.

6. Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and others :- Reservation for the Schedule Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Disabled Military personal and dependents of freedom fighter and other for recruitment to the service shall be in accordance with the orders issued by Government from time to time.

Short Notes

A Scheduled Caste candidate qualified in the open competition on merit is to be placed senior upon those candidates who selected under reserved quota. [1985 (2) SLJ APHC 568]

37. Number of appointments to be made :-

- (a) The Board shall report by the 1st day of March every year to Government the number of vacancies, anticipated during the following calendar year and the Governor shall then decide the number of candidates to be taken from each of the sources specified in rule 5. The total number of vacancies shall ordinarily be filled as follows :

- (1) 5/18th of the total number of vacancies by promotion of the officials specified in rule 5 (ii)
- (2) 1/18th of the total number of vacancies by promotion of the officials specified in rule 5 (IV)
- (3) one vacancy by the selection of suitable official mentioned in rule 5 (iii)
- (4) The remaining vacancies by direct recruitment under rule 5 (i)

7. (b) In any year while calculating the number of vacancies to be filled in from Collection Amins under rule 5 (IV) adjustment will be made by considering the number of vacancies of that year and of two previous year and the number of vacancies filled in during the two previous years under rules 5 (IV). Half or more vacancy arrived at in this manner shall be treated as one vacancy while less than half vacancy shall be ignored.

Part III - Qualification

8. Nationality :- A candidate for recruitment to the service must be a citizen of India or a subject of Sikkim.

1. Substituted by Notification No. 7/3(1) F/74-139-dated April 24, 1978.
2. Substituted by Notification No. 55/2(9) F/67/1193/dated August 31, 1979.
3. Substituted by Notification No. 7/3(1) F/74-139-dated April 24, 1978.

9. Age :- A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 27 years on January 1 of the year following in which the examination is held.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified :

Provided further that if a candidate would have been entitled in respect of his age to appear at the examination in any year in which no such examination was held he shall be deemed to be entitled in respect of his age to appear at the next following examination.

10. Academic qualification :- A candidate for direct recruitment must hold a degree from a recognised University.

11. Character :- The character of a candidate for direct appointment must be such as to render him suitable in all respects for employment in the service. It would be the duty of the appointing authority to satisfy itself on this point.

Part IV - Procedure for direct recruitment

12. Application for permission to attend the examination :- Application for permission to sit at the competitive examination shall be invited by the Commission and shall be made in the prescribed form which may be obtained from the Secretary to the Commission.

13. Admission to the examination :- No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission granted by the Commission.

14. Fees :- Candidate for direct recruitment must pay to the Commission such fees as may from time to time be prescribed by the Governor. No claim for refund of these fees will be entertained.

Note :- The scale of fees at present prescribed is shown in Appendix B.

15. Syllabus :- The syllabus and the rules relating to the competitive examination shall be prescribed from time to time by the Commission with the approval of Governor.

Note :- The syllabus and the rules at present in force will be found in Appendix C.

16. Admission to the viva voce :- (1) After the marks obtained by the candidates in the written test have been received, a consolidated list of the candidates shall be prepared in order of merit and laid before the Commission. The list shall show neither the roll number nor the names of the candidates, but shall only give serial number in order of merit, the community to which the candidates belong and the marks obtained by them in the written test. The Commission shall summon for interview as many candidates as have shown their suitability for appointment in the written test having regard to necessity for securing the representation of the communities and classes for which reservation has been made and shall award marks up to a maximum of 100 to each such candidate for his suitability for appointment in respect of character, personality and physique. The marks so allotted shall be added to the marks obtained in the written examination.

(2) Except for the purpose indicated above, the marks obtained by the candidates in the written test shall not be disclosed to the Members of the Commission who conduct viva voce examination until the examination is over and the marks therefore have been finally awarded.

Part V - Procedure for recruitment by promotion

17. (1) (a) For purposes of recruitment to the service under rule 5 (ii) a selection strictly on merit shall be made from amongst the permanent Supervisor Kanungos, who have put in not less than seven years service in the aggregate as Supervisor Kanungo or in a equivalent or higher post in a substantive or officiating capacity on the first day of January of the year in which the selection is made.

(b) In selecting the candidates for promotion regard shall be had to their-

- (i) personality and character,
- (ii) intelligence, tact and energy (including ability to tour on horseback),
- (iii) capacity for effective supervision,
- (iv) capacity for sustained hard and accurate work,
- (v) capacity to undertake responsibility,
- (vi) initiative, drive and dependability,
- (vii) integrity and efforts to eradicate corruption, and
- (viii) previous record of service.

(2) The procedure for selection shall be as follows :

(i) The Board shall draw up in order of merit, a list of the most suitable candidates from amongst those who are eligible for promotion to the post of Naib-Tahsildar. The names in the list shall ordinarily be double the number of substantive vacancies to be filled in during the course of the year.

(ii) The Board shall also drawn up, in order of merit supplementary list containing names of officials considered suitable for officiating or temporary promotions. The names in this list shall, ordinarily be equal to the probable number of officiating or temporary vacancies expected to occur during the course of the year.

(iii) The two lists drawn up under clauses (i) and (ii) above, together with a gradation list indicating therein the reasons for passing over the seniors, if any and the character rolls of all the eligible officials shall be forwarded by the Board to the Commission. The Commission shall consider the cases of all eligible candidates and may add to either of the two lists the names of the officials, if any, who deserve to be considered for promotion. The Commission shall then return the papers to the Board and shall also indicate whether, in their opinion, all or any of the candidates are to be interviewed by the Selection Committee.

(iv) The Board shall then, in consultation with the Commission fix a date on which a Selection Committee, consisting of-

- (a) the representative of the Commission who will preside over the Committee.
- (b) a member of the Board of revenue.
- (c) a Commissioner of a Division whom the Government may nominate.

(The Secretary, Board of Revenue, will act as a non-member Secretary of the Committee.)

shall consider the cases of the eligible candidates who are on the final lists drawn up by the Commission and interview them by the Commission under clause (iii) above.

(v) The lists of names of candidates selected by the Commission shall be submitted to him by the representative of the Commission for placing them before the Board. The Commission will thereafter send their final recommendations to the Board.

(vi) The Board shall draw from the first list received from the Commission, under clause (v) above, as many candidates as there are permanent vacancies. Thereafter, re-arrange their names in accordance with their seniority in their parent service and they will be appointed against substantive vacancies. The remaining names of the first list and those of the second list will be arranged in order of merit, forming the Select List to be drawn up in order of merit, the officials will be appointed to officiating and temporary vacancies in the order in which their names are arranged in the aforesaid select list as and when the vacancies occur during the year. This 'Select List' will hold good only for one year or until such time as a review made at the following selection.

(vii) in case permanent vacancies do not occur for two consecutive years and it becomes necessary to make a selection for temporary or officiating vacancies only, then also the procedure prescribed above will be followed.

Part VI - Procedure for selection of a Kanungo diplomate

18. (1) The Principal of the Kanungo Training School shall, each year, after the final examination of the School, submit to the Board the names of the first three students with the aggregate marks obtained by each.

(2) Towards the end of a period of two years from the date of the final examination which shall include the period of practical training in survey required under paragraph 377 of the Land Records Manual, the Board shall call for a report from the District Officers concerned on the work of all the three diplomates and shall make a selection after considering such reports and consulting the Commission.

(3) The names of a diplomate selected by the Board under sub-rule (2) shall then be entered in the approved list maintained under rule 20.

Part VII - Appointment, probation and confirmation

19. **Selection of candidates for direct recruitment :-** The Commission shall prepare a list of the candidates for direct recruitment in order of their proficiency as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate the Commission shall arrange them in order of merit on the basis of their general suitability for the Service. Subject to the provisions of rule 21 and to the allocation of posts to communities and classes, the Board shall select the candidates who stand highest in order of merit, provided that they are satisfied that the candidates are duly qualified in other respects.

20. **Waiting list of candidates :-** (1) The names of persons selected for vacancies to be filled (1) by direct recruitment, (2) by promotion, or (3) under rule 18 (2) (hereafter collectively called listed candidates), shall be entered according to the year of their selection in a list maintained by the Board.

(2) Candidates selected in the same year shall be entered in the list in the following order :

(i) candidates promoted under rule 5 (ii) :

(ii) candidates selected under rule 5 (iii) :

(iii) candidates directly recruited under rule 5 (i).

(3) Candidates in each group under sub-rule (2) shall rank inter accordingly to the following principles :

(a) as between persons promoted from the same service, according to their seniority in that service;

(b) as between persons promoted from different services according to their substantive pay immediately before promotion and, if on equal pay, according to their length of service :

(c) as between persons directly recruited, in the order in which their names appear on the final list drawn up by the Commission in order of merit.

21. Physical fitness and riding certificate :- No person, other than candidates selected under rule (5) (ii), shall be appointed to the service unless-

(i) he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of the Service. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to furnish a medical certificate of health in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10.

(ii) he produces a certificate of his ability to ride signed by a District officer.

22. Appointments to permanent vacancies :- The Board shall, on the occurrence of substantive vacancies in the service make appointment thereto, in order of seniority of candidates whose names are entered in the list maintained under rule 20.

Note :- A directly recruited candidate may lose his seniority if he is not available to join the service when a vacancy is offered to him.

Short Notes

Selection made in pursuance to the guidelines can not be held to arbitrary. (1989)
(1) SLJ Kerala 324)

23. Seniority :- Seniority in the Service shall be determined by the date of the order of substantive appointments, provided that if two or more candidates are appointed on the same date, their seniority shall be determined according to their respective positions in the list.

24. Probation :- (1) Every listed candidate on appointment in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) Continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre of the Service or on a higher post may be taken into account in computing the period of probation.

25. Departmental examinations and training :- (1) Every listed candidate whether appointed in a substantive vacancy or not shall be required to pass such tests in departmental subject and the languages of that Province and to undergo such training as the Governor may from time to time prescribe.

(2) Every listed candidate shall appear at each successive examination at which he is required by sub-rule (1) to appear until he has passed, unless he is prevented by illness or is specially exempted by the Board up to the limit of three years in the proviso to rule 26. The sanction of the Governor shall be necessary.

exemption of a candidate from appearance at an examination beyond this period. A medical certificate shall be required in case of illness.

Note :- The rules for departmental examination have been published in a separate pamphlet which is obtainable from the Director, Printing and Stationary. U. P., Allahabad.

26. If it appears at any time during or at the end of the period of probation that a person appointed or probation has not made sufficient use of his opportunities or has failed to pass the departmental examination completely or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive appointment, if he holds one, or in other cases he should be removed from service : Provided that the Board may extend the period of probation to three years. An extension beyond this period shall require the sanction of the Governor. Every extension whether granted by the Board or the Governor shall specify the exact date up to which it is granted.

Notes :- (1) An extension may be granted beyond three years only for special reasons. The fact that a candidate has been seconded for special duty within or outside the Province shall be valid ground for extension.

(2) A candidate removed from service during the period of probation shall not be entitled to any compensation.

27. Confirmation :- (1) A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation, if.

(i) he has passed the departmental examination for Naib-Tahsildars completely.

(ii) the Commissioner reports that he is fit for confirmation and that his integrity is unquestionable, and.

(iii) the appointing authority is satisfied about his fitness for confirmation.

(2) An intimation of all confirmations of Naib Tahsildars shall be given to the Commissioners of the Divisions concerned.

28. Officiating and Temporary Appointments :- (1) Temporary vacancies not likely to last for more than six weeks may be filled by the District Officer by appointment of a listed candidate if available in the district, but if no such candidate is available, the most suitable official available may be appointed.

(2) Vacancies lasting for more than six weeks but not more than three months shall be filled by the District Officer by the appointment of a listed candidate, if one is available, in the district. If no such candidate is available, a report shall be made to the Commissioner who shall if possible, appoint a listed candidate from some other district of the division. If no listed candidate is available in the division, the Commissioner shall appoint, or authorise the District Officer to appoint the most suitable official available.

(3) All vacancies lasting for more than three months shall, on the report of the Commissioner, be filled by the Board.

Short Notes

Services of temporary Government servant can be terminated at any time without assigning any reasons.

1989 (1) SLR P&H 432

1986 (1) SLR P&H 378

1979 (1) SLR 351 (SC)

1986 (1) SLR Gujrat 501

1986 (1) SLR J&K 1986(*) SLR SC 424

Adhoc appointment can not last long for years together (1989 (1) SLJ P&H 155.)

29. All reversion and changes among Naib-Tahsildars shall be Notified by the District Officer as soon as they occur, to the Commissioner and the Board in the prescribed form.

30. **Prohibition against taking other employment :-** A listed candidate selected by direct recruitment shall not take up any other employment without first obtaining the permission of the Board. If he does so, his name shall be struck off from list.

Part VIII - Pay

31. (1) Subject to the provisions of the United Provinces Revised Rates of Pay Rules, 1931, the rates of monthly pay admissible to persons appointed to the posts of Naib-Tahsildars, whether in a substantive or in an officiating capacity or as a temporary measure, shall be as follows :

(i) For persons appointed or selected for appointment :

Before July 4, 1931.

On or after July 4, 1931 but before April, 1944

	Rs.	Rs.
I. Grade	150-00	120-00
II. Grade	130-00	100-00
III. Grade	115-00	85-00
IV. Grade	100-00	75-00

(ii) With effect from April 1, 1944, monthly pay shall be drawn in the time-scale of Rs. 75-5-100-5-150 (Efficiency bar at Rs. 100/-) provided that persons who were in the service on that date shall have the option to draw the graded rates of pay under clause (1) above in accordance with the provisions of Fundamental Rule 23, read with the Audit Instruction No. 3 regarding that rule.

(ii) With effect from August 1, 1972 monthly pay shall be drawn in the time scale of pay of Rs. 300-8-340-EB-10-440-E.B.-12-500 and also with effect from October 1, 1975, the pay shall be drawn in the time-scale of pay of Rs. 300-8-324-9-360 EB-10-440-EB. 12-500. provided that persons who were in the service on those dates shall have the right to opt for the old scale of day in accordance with the procedure laid down for the purpose by the government.

²(2) Persons appointed to the following posts of Naib-Tahsildar shall draw a special pay mentioned against each :

(i) Nazul Naib Tahsildar, Agra. Special pay Rs. 15 per mensem.

(ii) Nazul Naib-Tahsildar, Agra. Special pay Rs. 30 per mensem.

(3) Criterion for crossing the efficiency bars.- (1) No Naib-Tahsildar shall be allowed to cross the first efficiency bar unless his record of service shows that he has worked steadily with distinct ability and unless his integrity is certified.

(2) No Naib-Tahsildar shall be allowed to cross the second efficiency bar unless he is considered fully capable of holding an independent charge of tahsil by reason of his ability and unless his integrity is certified.

1. Substituted by Notification No. 7/3/(1) F/74-139-dated April 24, 1978.

2. Substituted by Notification No. 7/3/(1) F Rs. 74-139/dated April 24, 1978.

Short Notes

The above pay scales have been revised by the U. P. Pay Commission w.e.f. 1-1-1986. (See Chapter XXXVIII)

32. Pay during Probation :- A person on probation, if he is not already in the service of the State, shall draw during the period of probation the minimum of the scale of pay which may be admissible to him, and shall draw increments as they accrue, provided that if the period of probation is extended for failure to give satisfaction, the extended period shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

33. Grade promotions :- (i) Grade promotions of those Naib-Tahsildars who do not elect the time-scale of pay shall be made by the Board by seniority subject to efficiency after considering their character rolls and the reports of the District Officers and the Commissioners on their work. No Naib-Tahsildar shall be promoted from one grade to another unless his integrity is certified.

(ii) An intimation of all grade promotions of Naib-Tahsildars, who still retain the graded rates of pay mentioned in sub-clause (1) of clause (1) of rule 31 shall be given to the Commissioners of the divisions concerned.

Note :- Grade promotions in officiating vacancies shall be regulated subject to the provisions of paragraph I read with paragraph VI of the orders of the Governor regarding the first proviso to Fundamental Rule 30 (1) in the Financial Handbook. Volume II, Part II.

34. Canvassing :- No recommendation for recruitment, either written or oral other than that required under these rules shall be taken into consideration. Any attempt on the part of the candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature by other means shall make him liable to disqualification.

35. Transfers :- (1) Naib-Tahsildars may be transferred from one tahsil to another by their District Officers, from one district to another by the Commissioners of their division and from one division to another by the Board.

(2) The Commissioner may in his discretion post a Naib-Tahsildar to a particular tahsil in any district of his division. Similarly, the Board may in their discretion post a Naib-Tahsildar to a particular district or tahsil in the Province. The Naib-Tahsildar so posted shall not be transferred from that tahsil or district without the previous approval of the Commissioner or the Board as the case may be.

(3) Notwithstanding anything to the contrary in these rules or in the Subordinate Revenue Executive Service (Peshkars) Rules, 1946, the Board may on administrative grounds transfer the Naib-Tahsildars to the Kashipur and Tarai and Bhabar Tahsils of Naini Tal District or to any tahsil of district of the Utrakhand Division to work as Peshkars.

Explanation :- Where a Commissioner is incharge of more than one division the entire area within his jurisdiction shall for the purposes of this rule be treated as constituting one division.

36. Punishment and appeals :- Subject to the modification noted below, the provisions of the rule regulating punishments and appeals promulgated in the "Punishment and Appeal Rules for the Subordinate Services" shall apply to persons appointed to the Service :

(1) The Division Officer may censure a Naib-Tahsildar.

(2) The District Officer may suspend a Naib-Tahsildar pending enquiry into any instance of official misconduct or pending the receipt of orders upon any report made as to such misconduct.

(3) Any order for the punishment of a Naib-Tahsildar excepting dismissal or removal may be passed by the Commissioner, who shall send a copy thereof to the Board.

(4) Any order for punishment of a Naib-Tahsildar who was not appointed by the Governor may be passed by the Board.

(5) The Board may pass any order of punishment except removal or dismissal on a Naib-Tahsildar appointed by the Governor.

(6) If the Board consider that an order of punishment of removal or dismissal is required in the case of Naib-Tahsildar appointed by the Governor, the Board shall submit the complete proceedings including formal charges, the explanation of the officer and the evidence for and against him together with their own findings and recommendation to Government for orders.

37. Regulation of pay, leave, allowances, pension, etc. :- Except as provided in these rules, the pay, allowance, leave, pension and other conditions of service of a person appointed to the Service shall be regulated by the rules made under section 241 (2) (b) of the Government of India Act, 1935, and pending the issue of such rules by the rules continued in force by section 276 of the said Act and by and in accordance with the provisions of paragraph 15 (2) of the Government of India (Commencement and Transitory Provisions) Order, 1936.

38. Notwithstanding anything contained in these rules :- (1) Officers who were serving in any area which has merged in the State of Uttar Pradesh, after August 15, 1947, or may merge therein hereinafter, or (2) displaced persons who, after migration from Pakistan areas to this State, have been selected in accordance with the provision contained in para 6 of the Appointment Department O. M. No. O-416/II-48, dated February 6, 1948 may be appointed in consultation with the Commission, to posts in the cadre, and the person or persons so appointed will be deemed to have been appointed to the Service in accordance with these rules.

39. Notwithstanding anything contained elsewhere in these rules :-

(1) all the permanent and temporary posts of 'Collection Naib-Tahsildar' existing as on November 14, 1962, shall, with effect from November 15, 1962, be deemed to have been redesignated as 'Naib Tahsildar' and added to the permanent and temporary cadres respectively of the Service;

(2) all persons who were serving as Collection Naib-Tahsildars in the State on November 14, 1962, in a substantive capacity, shall be deemed to have been appointed as 'members of the Service', as defined in clause (g) of rule 3;

(3) persons who were serving as Collection Naib-Tahsildars in the State on November 14, 1962 in an officiating capacity or in temporary posts, shall be deemed to have been appointed as 'Naib-Tahsildars' in officiating or temporary vacancies, as the case may be, in accordance with the rules and shall be eligible for appointment as members of the service, in consultation with the Commission; and

1. Substituted by Notification No. 1831 (1) I F 205 T/62 dated August 24, 1963.

(4) the Governor may direct that the said rules or any individual rule thereof shall not apply or shall apply with such modification as he may specify, to the persons mentioned in sub-rules (2) and (3) in respect of their recruitment on appointment to the Service and other conditions of service relating thereto.

ORDER

In exercise of the power conferred by clause (b) of section 275 of the Government of India Act, 1935, the Governor of the United Provinces is pleased to order that women shall not be eligible for appointment to the post of Naib-Tahsildars.

Appendix A

(See Rule 10)

The following examination have been recognized by the Governor, for the purpose of rule 10 :

- (1) Intermediate Examination of the Benaras Hindu University.
- (2) Intermediate Examination of the Aligarh Muslim University.
- (3) Cambridge Higher School Certificate Examination.
- (4) Senior Diploma Examination of the Mayo College, Ajmer.

Appendix B

(See Rule 14)

Scale of fee to be charged from candidates for direct recruitment.

(1) **Application fee** :- Rs. 5 payable in two instalments. Rs. 1 with the requisition for the application form and Rs. 4 with the application when it is filed.

(2) **Examination fee** :- Rs. 25 for candidate other than Scheduled Caste candidates; Rs. 15 for Scheduled Caste candidates;

These fees must be deposited in a Government treasury or in a branch of the Imperial Bank of India or in a State treasury authorised to transact business on behalf of the Provincial Government under the head "XXXVI-Miscellaneous Departments-Examination fees-Fees realized by the Provincial Public Service Commission, United Provinces" and only the treasury receipts should be furnished to the Commission.

Appendix C

(See Rule 15)

Syllabus and Rules for the Competitive Examination

¹(1) The competitive examination shall include the following subjects and each subject will carry the number of marks shown against it;

Section A - To be taken by all candidates;

Subject :	...	100
1. General Hindi and Essay	...	100
2. General Knowledge (including simple Science)	...	100
3. Elementary Mathematics	...	100

Section B - Each candidate must take two of the following subjects :

1. Vide Subs. Notification No. 7/3 (1)-F/74-139, dated 24-4-1978.

4. General Indian History	...	100
5. General Geography	...	100
6. Physics	...	100
7. Chemistry	...	100
8. Economics	...	100
9. Sociology	...	100
10. Book-keeping and Accountancy	...	100
11. Botany	...	100
12. Zoology	...	100
13. Lower Mathematics	...	100
14. Law	...	100
15. Agriculture	...	100
16. Politics	...	100
17. Psychology	...	100
18. Statistics	...	100
19. Chemical Engineering	...	100
20. Sanskrit Literature	...	100
21. Hindi Literature	...	100
22. Urdu Literature	...	100
23. English Literature	...	100
24. National Defence and Security	...	100
Section C		
25. Personality Test (Viva Voce)	...	100

Note :- The paper in the case of each of the subject mentioned in Sections A and B above shall be of 3 hours' duration.

(2) The standard and scope of the examination in each subject shall be as follows:

Section A :- (Compulsory Subjects.)

1. **General Hindi and Essay :-** This paper will be of High School standard.

2. **General Knowledge (including Simple Science) :-** Including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience as may be expected of an educated person without any special study. The questions will ordinarily be set as to admit of brief answers and besides covering popular science, will embrace the knowledge of the social, political and economic events of the day.

3. **Elementary Mathematics :-** This paper will be of High School standard.

Section B - (Optional Subjects)

4. **General Indian History :-** The minimum scope of knowledge will be that which a B. A. pass student should have attained who has acquired familiarity with the main aspects and the leading events of the different periods of the Indian History and more particularly those relating to the period of Akbar's reign down to the present day.

B. A. **General Geography :-** The minimum scope of knowledge will be that which a Geography of the World should have attained. The paper will include questions on require the drawing of a map. the questions on physiography. One of the question will

6. Physics :- The scope of the paper will be that which a B. Sc. pass student should have attained.

7. Chemistry :- The scope of the paper will be that which a B. Sc. pass student should have attained.

8. Economics :- The scope of the paper will be that which a B. A. pass student should have attained.

9. Sociology :- Principles of Sociology (Social System), the Indian Social System. Principles of Sociology (Social Control and Social Change), Applied Sociology.

10. Book Keeping and Accountancy :- The scope of the paper will be that which a commerce Graduate should have attained.

11. Botany :- The paper will be of B. Sc. standard. It will include questions on Morphology, Physiology and life histories of Angiosperms. General Plant Physiology, Evolution, Variation and Heredity, Economic Botany.

12. Zoology :- The paper will be of B. Sc. standard. It will include questions on chordata, Elementary Facts and Embryology, Physiology, Geological and Geographical Distribution.

13. Lower Mathematics :- The paper will be of B. Sc. standard and will cover Algebra, Trigonometry, Analytical Geometry of two dimensions, Differential Calculus, Integral Calculus, Differential Equations, Statics, Dynamics, Hydrostatics and Astronomy.

14. Law :- Constitutional Law (both Indian and British) Jurisprudence, Torts, Indian law of Contract, Indian Evidence Act and Indian Penal Code.

15. Agriculture :- The paper will be of B. Sc. (pass) in Agriculture standard. It will include questions on Agricultural Economics and Farm Managements, Agricultural Engineering Farm Crops and Agricultural Chemistry and Biological Science.

16. Politics :- The scope of the paper will be that which a B. A. pass student should have attained.

17. Psychology :- The paper will be of Degree standard.

18. Statistics :- The paper will be of Degree standard.

19. Chemical Engineering :- The paper will be of Degree standard.

20. Sanskrit Literature :- Candidates will be expected to show a general knowledge of the History of Sanskrit Literature with special reference to the principal classical authors and of the prakrit used in plays passage may also be given for translation from Sanskrit into English and vice versa. Answers required to be written in Sanskrit must be written in Devanagari script.

21. Hindi Literature :- Candidates will be expected to know the standard works in Hindi though question on books of lesser importance may also be used. They will also be expected to possess a knowledge of the history of literature and social knowledge of general social history as will enable them to understand the literature. Answers to questions should be written in Hindi in Devanagari script.

22. Urdu Literature :- Candidates will be expected to know the best known books in Urdu though questions on works of lesser importance may also be set. They will also be expected to possess a knowledge of the history of the literature and social

knowledge of general social history as will enable them to questions should be written in Urdu.

23. English Literature :- Candidates will be expected to show a general knowledge of history of English Literature from the time of Spenser to 1930 with special reference to the work of the following authors;

Shakespeare, Milton, Johnson, Dickens, Wordsworth, Keats, Carlyle, Tennyson, Hardy and Bernard Shaw.

24. National Defence and Security :- This paper will deal with Defence and Security problems of the great powers in general and India in detail-(1) Essentials of National Defence :

- (a) Geographical factor Location, Frontiers Terrain,
- (b) Economic Factor-Resources Industrial and Scientific Development Transport and Communication,
- (c) Internal political conditions,
- (d) Defence Mechanism of the Modern State.
- (2) Modern Trends-
 - (a) Defence and Military Alliances,
 - (b) Neutrality and Non-alignment,
 - (c) Disarmament and World Peace Organisation.
- (3) Defence and Security of India-
 - (a) Historical background and problems,
 - (b) Defence problem of Free India-
 - (i) India's Foreign Policy in the context of Inter-national power politics and her relations with the neighbours.
 - (ii) India's Strategic Location and Frontier,
 - (iii) Economic Strength of India,
 - (iv) India's Defence Organization.

Section C

(Personality Test/Viva Voce)

25. The examination will be in matters of general interest not in matters of academic interest Marks will be awarded to each candidate for intelligence personality address, character, physique and general suitability for service. Any suitable question designed to throw light on these matters may be asked.

Note :- Only those candidates will be called for personality test, who have obtained such minimum marks in the written examination as thereof any may fix keeping in view the general standard of the candidate.

✓

उ० प्र० कलेक्शन अमीनों को सेवा नियमावली, 1974

U. P. Collection Amins' Service Rules, 1974

उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग-6, द्वारा शासनादेश संख्या 119/1-66 (यू० ओ० 545/72) राजस्व-6 दिनांक 9 अगस्त, 1974-संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर समस्त वर्तमान नियमों तथा आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल कलेक्शन अमीनों की सेवा में पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

भाग-1 - सामान्य

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :- (1) यह नियमावली उ० प्र० कलेक्शन अमीनों की सेवा नियमावली, 1974 कहलायेगी (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. प्रास्थिति :- उ० प्र० कलेक्शन अमीनों की सेवा तृतीय श्रेणी की अधीनस्थ सेवा है।

3. परिभाषायें :- जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

1[(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य नियम 19-क में इस रूप में इंगित प्राधिकारी से है।]

2[(ख) "परिषद" का तात्पर्य राजस्व परिषद उ० प्र० से है;

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत के संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) "कलेक्टर" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है तथा इसके अन्तर्गत उप-आयुक्त भी होंगे;

(ङ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उ० प्र० सरकार से है,

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उ० प्र० के राज्यपाल से है;

3[(ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।]

4[(झ) "सीज़नल अमीन" का तात्पर्य ऐसे अमीन से है जो रबी या खरीफ या दोनों ही फसलों के लिए नियुक्त किया जाय;]

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उ० प्र० कलेक्शन अमीनों की सेवा से है;

(ट) "परगना अधिकारी" का तात्पर्य किसी परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर से है;

5[(ठ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

1. अ० सू० सं० 135/3-80 (53)-राजस्व-6 द्वारा दि० 8-5-84 द्वारा बढ़ाया गया।

2. अ० सू० सं० 135/3-80 (53) द्वारा उप नियम (क) से (च) को बदल कर उप नियम (ख) से (छ) के रूप में किया गया।

3. अधिसूचना सं० 135/3-80 (53) राजस्व 6 द्वारा दि० 8-5-84 द्वारा बढ़ाया गया।

4. अधिसूचना सं० 135/3-80 (53) राजस्व 6 द्वारा दि० 8-5-84 द्वारा बदला गया।

5. अधिसूचना सं० 135/3-80 (53) राजस्व 6 द्वारा दि० 8-5-84 द्वारा बदला गया।

(ड) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि है।]

भाग 2 - संवर्ग

4. सेवा में पदों की संख्या :- (1) सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा में पदों की स्थाई संख्या, जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन उनमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है।

(1) कलेक्शन अमीन (सामान्य श्रेणी) - 5,341

(2) कलेक्शन अमीन (चयन श्रेणी) - 593

प्रतिबन्ध यह है कि-

(क) कलेक्टर किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थायित रख सकते हैं और ऐसा किये जाने पर कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; और

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं; जो आवश्यक हो।

भाग 3 - भर्ती

1[5. भर्ती का स्रोत :- (1) सेवा की सामान्य श्रेणी के पदों पर भर्ती इस नियमावली के भाग 5 में व्यवस्थित रीति से प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम पर की जायगी;

प्रतिबन्ध यह है कि उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, पन्द्रह प्रतिशत रिक्तियाँ ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त कलेक्शन चपरासियों में से पदोन्नति द्वारा भरी जायगी :-

(क) जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की कम से कम हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और

(ख) जिन्होंने राजस्व विभाग के कलेक्शन संगठन में कम से कम छः फसलों की अवधि के लिये कार्य किया हो :

प्रतिबन्ध यह और कि पैंतीस प्रतिशत रिक्तियाँ ऐसे सीजनल कलेक्शन अमीनों में से चयन द्वारा भरी जायेंगी-

(क) जिन्होंने कम से कम चार फसलों तक सन्तोषजनक रूप से कार्य किया हो;

(ख) जिनकी आयु उस वर्ष की पहली जुलाई को, जिस वर्ष चयन किया जाय, 45 वर्ष से अधिक न हो;

प्रतिबन्ध यह भी कि यदि अपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियाँ सीधी भर्ती के माध्यम के सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी।

स्पष्टीकरण :- सन्तोषजनक कार्य का तात्पर्य होगा शुरू से अन्त तक अच्छे आचरण को सम्मिलित करते हुये अन्तिम चार फसलों के दौरान विहित स्तर के अनुसार कम से कम सत्तर प्रतिशत वसूली।]

(2) सेवा की चयन श्रेणी के पदों पर नियुक्ति इस नियमावली के भाग 6 में व्यवस्थित रीति से सामान्य श्रेणी के स्थायी कलेक्शन अमीनों की पदोन्नति करके की जायगी।

2[6. आरक्षण :- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

1. अधिसूचना सं० 2755/1-7-92-2-1-87 (97) रा-7

दि० 23-अक्टूबर 1992 द्वारा बदला गया जो कि

उ० प्र० गजट 20-मार्च 1993 को प्रकाशित हुआ।

2. अ० सू० सं० 2755/1-7-92-1-87 (97) राजस्व 7 दि०

23-10-1992 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

भाग 4 - अर्हतायें

¹[7. राष्ट्रीयता :- राज्य सरकार के अधीन किसी पद या सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जिसका 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने का इरादा हो।

(ग) वह मूलतः भारतीय निवासी का वंशज हो और पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीका के केलस उगोण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (जिसके पहले टागानीज और जंजीदार नाम था) के देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के इरादे से आया हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ख) या (ग) अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिनके नाम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक की सीजनल कलेक्शन अमीन के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अनुमोदित सूची में सम्मिलित किये गये थे और जिन्होंने उक्त दिनांक तक सीजनल कलेक्शन अमीन के रूप में कम से कम चार फसलों में कार्य कर लिया था, शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० की हाई स्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा होगी।

²[8. आयु :- सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।]

³[9. शैक्षिक अर्हताएँ :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व भर्ती किये गये थे, शैक्षिक अर्हता वही समझी जायगी जो सेवा में उनकी प्रथम नियमित नियुक्ति के समय विहित थी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो उत्तर प्रदेश कलेक्शन अमीनों की सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1980 के प्रारम्भ होने के पूर्व सीजनल कलेक्शन अमीन के पदों पर नियुक्त किये गये थे और जिन्होंने उक्त दिनांक तक पहले ही कम से कम चार फसलों के लिए संतोषजन कार्य कर लिया हो, उनकी शैक्षिक अर्हता वही होगी जो-जो सीजनल अमीन के रूप में उनकी प्रथम नियुक्ति के समय विहित थी।]

⁴[9-क. अधिमानी अर्हता :- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा जिसने -

1. अ० 135/27/73 (480) राजस्व 6 दि० 20 अप्रैल 1977 द्वारा बदला गया।

2. अधिसूचना संख्या 135/3-80 (53)-राजस्व-6, दिनांक 8 मई, 1984 द्वारा बदला गया।

3. अधिसूचना संख्या 135/27/73 (480)-राजस्व 6, दिनांक 18 मार्च, 1980 द्वारा बदला गया।

4. सं० 135/3-80 (53) राजस्व-6 दिनांक 8-5-84 द्वारा बदला गया।

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।]

10. वैवाहिक स्थिति :- कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा कोई महिला अभ्यर्थी जिसने एक पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र न होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपाल को यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है तो वे किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से मुक्त कर सकते हैं।

¹[**11. चरित्र :-** सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान न कर लेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. शारीरिक स्वास्थ्यता :- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना न हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैन्डबुक, खण्ड-2, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग 5 - भर्ती

2[13. सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र :- कलेक्टर, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। कलेक्टर तब स्थानीय सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमन्त्रित करेगा।

14. परीक्षा :- (1) कलेक्टर, आवेदन पत्रों की परिनरीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में, जो सामान्यतः अप्रैल व मई माह में होगी, बैठने की अपेक्षा की जायेगी। कोई भी अभ्यर्थी तब तक परीक्षा में प्रविष्ट नहीं किया जायगा जब तक कि उसके पास कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

(2) परीक्षा में प्रविष्ट प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह परीक्षा-शुल्क के लिए 2 रुपये दे।

15. प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम तथा नियम वही होंगे जो समय-समय पर राज्यपाल द्वारा विहित किये जायें।

1. अधिसूचना सं० 135/3-80 (53) रा० 6 दि० 8 मई 1984 2. अ० सं० 2755/1-7-92-2-1-87 (97) रा० 7-दि० अक्टूबर द्वारा नियम 11 से 17 तक बदला गया था परन्तु नियम 13 1992 द्वारा प्रतिस्थापित।
अधिसूचना सं० 27555/1-7-92-1-87 (97) रा-7 दि० 23-10-92 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

टिप्पणी :- इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय विहित विषय तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में दिये गये हैं।

16. साक्षात्कार :- कलेक्टर साक्षात्कार के लिए उतने अभ्यर्थियों को बुलायेगा जो उसके द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त किये हों। साक्षात्कार में प्राप्त अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर स्वविवेक से, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने का कार्य अपर जिला मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है।

17. चयन सूची :- कलेक्टर, अभ्यर्थियों की एक सूची योग्यता क्रम में, जैसा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों से विदित हो, तैयार करेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों को अंक योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त हों तो लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की ऊपर रखा जायेगा।

¹[17. (क) सीजनल कलेक्शन अमीनों के चयन की प्रक्रिया :- कलेक्टर सीजनल कलेक्शन अमीनों की जो नियम 5 के उप नियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन चयन के लिये पात्र हों एक सूची तैयार करेगा और उनमें से सन्तोषजनक कार्य के अधीन जिले में सीजनल कलेक्शन अमीन के पद पर उनकी सेवा अवधि के आधार पर अपेक्षित संख्या में चयन करेगा।

18. पदोन्नति की प्रक्रिया :- कलेक्टर ऐसे स्थायी कलेक्शन चपरासियों को जो नियम 5 के उप-नियम (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन पदोन्नति के लिये पात्र हों, एक सूची तैयार करेगा और उनमें से ज्येष्ठता के आधार पर, किन्तु अनुपयुक्त व्यक्ति को अस्वीकार करते हुए अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

भाग 6 - चयन श्रेणी में नियुक्ति के लिये चयन की प्रक्रिया

19. चयन श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयन :- सेवा की चयन श्रेणी के पदों में रिक्तियाँ होने पर कलेक्टर जिले में सेवा की सामान्य श्रेणी के स्थाई कलेक्शन अमीनों में से ज्येष्ठता के आधार पर, किन्तु अनुपयुक्त व्यक्ति को अस्वीकार करते हुये, चयन करेगा। तदनुसार चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार की जायेगी।

²[19-क. नियुक्ति प्राधिकारी :- संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, परगना अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि तत्समय प्रवृत्त नियमावली के अनुसार कलेक्टर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में वह संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी होगा।

³[अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि समस्त मामलों में जहाँ परगना अधिकारी या किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नियुक्ति की गयी हो, कलेक्टर अपने विवेक के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।]

भाग 7 - नियुक्ति, परीक्षा तथा स्थायीकरण

⁴[20. नियुक्ति :- (1) सेवा की सामान्य श्रेणी में नियुक्तियाँ, कलेक्टर द्वारा यथास्थिति, नियम 17 के अधीन सीधे चुने गये अभ्यर्थियों की सूची, नियम 17-क के अधीन सीजनल कलेक्शन अमीनों से चुने गये अभ्यर्थियों की सूची और नियम 18 के अधीन पदोन्नत अभ्यर्थियों की सूची से उसी क्रम में जिसमें

1. अ० सं० 2755/1-7-92-2-1-87 (97) रा० 7
दि० 23-10-92 द्वारा बढ़ाया गया।

2. अधिसूचना संख्या 135/27/73 (480)-राजस्व-6.
दिनांक 17 मई, 1980 द्वारा 19-क बढ़ाया गया।

3. अ० सं० 2755/1-7-92-2-1-87 (97) रा० 7
दि० 23-10-92 द्वारा बढ़ाया गया।

4. अ० सं० 2755/10-7-92-2-1-87 (97) रा० 7
दि० 23-10-92 द्वारा बढ़ाया गया।

उनके नाम सूची में आये हों, से की जायगी। नियुक्तियों करते समय यह सुनिश्चित किया जायगा कि सीजनल कलेक्शन अमीनों से चुने गये और स्थायी कलेक्शन चपरासियों से पदोन्नत किये गये उपर्युक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुये, नियुक्तियों उसी क्रम में की जायगी जैसी परिशिष्ट-ग में उपबन्धित है।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस सम्बन्ध में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायगा। यदि नियुक्तियों सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो नाम उपनियम (1) में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

21. ज्येष्ठता :- सेवा में ज्येष्ठता मौलिक पद पर नियुक्ति किये जाने के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि दो या इससे अधिक अभ्यर्थी एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी जिस क्रम में उनकी नियुक्ति नियम 19 के अधीन की गई हो।

22. परिवीक्षा :- (1) सेवा की सामान्य श्रेणी में, मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक अभ्यर्थी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है। इस प्रकार बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के आदेश में वह ठीक दिनांक निर्दिष्ट होगा जब तक के लिए उक्त अवधि बढ़ाई जाय। बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि सामान्यतया 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा-अवधि जैसी भी दशा हो, के दौरान या उसके अन्त में किसी समय यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या अन्य प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, या यदि उसका किसी भी मौलिक पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं जिसके लिए वह किसी प्रतिकार का हकदार न होगा।

(3) सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर स्थानापन्न अथवा अस्थायी रूप से की गई अनवरत सेवा की परिवीक्षा अवधि की गणना करने में सम्मिलित किया जा सकता है।

23. स्थायीकरण :- परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा-अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि, जैसी भी दशा में हो, के अन्त में अपने पद पर स्थाई कर दिया जायेगा, यदि कलेक्टर का उससे कार्य और आवरण के आधार पर यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए उपयुक्त है और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाय।

भाग 8 - वेतन

24. वेतनमान :- सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति को, चाहे मौलिक रूप में हो अथवा स्थानापन्न या अस्थायी रूप में अनुमन्य वेतनमान जब तक कि राज्यपाल द्वारा उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें निम्नलिखित होगा।

	1 अगस्त, 1972 के पूर्व	1 अगस्त, 1972 से
(1) सामान्य श्रेणी	100-4-120 द० रो०-4-140 द० रो०-4-160 रुपये	200-5-250-द० रो०-6-280 द० रो०-8-320 रुपये
(2) चयन श्रेणी	120-6-150-द० रो०-6-180- द० रो०-8-220 रुपये।	230-6-290-द० रो०-8-330- द० रो०-10-380 रुपये।

25. परीक्षा-अवधि में वेतन :- फण्डामेंटल रूल में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परीक्षाधीन व्यक्ति को, परीक्षा-अवधि के दौरान वेतन वृद्धि इस शर्त पर दी जायेगी कि उसका कार्य तथा आचरण सन्तोषजनक प्रतिवेदित किया जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सन्तोषजनक कार्य न करने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक न की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

26. दक्षता-रोक पार करने के लिए मानदण्ड :- (1) किसी भी व्यक्ति को प्रथम दक्षता-रोक पार करने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य तथा आचरण अच्छा न पाया जाय तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) किसी भी व्यक्ति को द्वितीय दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका आचरण सन्तोषजनक न हो और उसका संग्रहण एवं लेखा-कार्य अच्छे स्तर का न हो तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग 9 - अन्य उपबन्ध

27. पक्ष समर्थन :- भर्ती के लिए इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी सिफारिश पर चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा और किसी अभ्यर्थी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्थता के लिए अन्य उपायों द्वारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास उसे अनर्ह कर देगा।

28. प्रतिभूति :- सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति से उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम 222-ग के अनुसार प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।

29. स्थानान्तरण :- (1) कलेक्शन अमोन उसी तहसील में एक सर्किल से दूसरे सर्किल में परगनाधिकारी द्वारा तथा एक तहसील से दूसरी तहसील में कलेक्टर द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है।

(2) साधारणतया जिले के बाहर स्थानांतरण नहीं किया जायेगा।

किन्तु ऐसा स्थानांतरण विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। किसी डिवीजन में एक जिले से दूसरे जिले में ऐसा स्थानांतरण जिसके अन्तर्गत पारस्परिक स्थानांतरण भी है, डिवीजन के आयुक्त द्वारा किया जा सकता है।

30. अवशिष्ट विषय :- ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विशिष्ट रूप से इस नियमावली अथवा तदधीन दिये गये या जारी किये गये आदेशों के अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों तथा आदेशों द्वारा नियुक्त होंगे जो उ० प्र० के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया प्रयोज्य होते हों।

31. सेवा की शर्तों में शिथिलता :- यदि सरकार को यह समाधान हो जाय कि सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से, किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कष्ट होता है तो वह नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिसे वह उस मामलों को न्याय और साम्यपूर्ण ढंग से निपटाने के लिये आवश्यक समझे, अभियुक्त कर सकती है या शिथिल कर सकती है।

परिशिष्ट "क"

(नियम 6 देखिये)

परिशिष्ट "ख"

(नियम 15 देखिये)

परीक्षा के लिए पाठ्य-विवरण

(1) अंकगणित

1. चार प्रारम्भिक नियम
2. दशमिक भिन्नांक
3. क्षेत्रफल
4. साधारण तथा चक्रवृद्धि व्याज
5. प्रतिशत
6. औसत
7. लाभ तथा हानि
8. लघुतम समापत्य, महत्तम समापवर्तक
9. व्यवहार गणित
10. ऐकिक नियम

(2) भूगोल

1. जिलों की भौगोलिक स्थिति, अवस्थिति इत्यादि
2. जलवायु
3. फसलें
4. भारी एवं लघु उद्योग
5. महत्वपूर्ण गाँव, कस्बे, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा धाना
6. आवागमन के साधन
7. काश्तकारों की दशा
8. सिंचाई के साधन
9. कृषीय आपदाएँ
10. नदियाँ, तालाब, पर्वत

(3) सामान्य ज्ञान

निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना -

1. तहसील, परगना, धाना के नाम
2. उ० प्र० के मन्त्री, परिषद् के मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों के नाम।
3. जिला परिषद् तथा पालिका बोर्ड या नगर-महापालिका के अध्यक्ष का नाम।
4. भौमिक अधिकार के कृषि सुधार प्रणाली सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषय।
5. जिलों के रेलवे या बस स्टेशनों के नाम।
6. पुलिस के सिपाहियों, पुलिस उपनिरीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों के कृत्य।
7. महत्वपूर्ण स्कूल कालेज व खेलकूद।
8. सहकारी, पशुपालन, कृषि आयोजन तथा शिक्षा और चिकित्सा एवं राजस्व विभाग के कृत्य।

(4) हिन्दी निबन्ध

वर्णनात्मक या कथनात्मक प्रकार के सरल निबन्ध

1[परिशिष्ट "ग"]

[नियम 20 (1) देखिये]

कलेक्शन अमीन के पद पर नियुक्ति का क्रम

सीजनल कलेक्शन अमीन से चुने जाने वाले और स्थायी कलेक्शन चपरासियों से पदोन्नत किये जाने वाले उपर्युक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, नियुक्ति निम्नलिखित क्रम में की जायगी :-

पहली रिक्ति	सीधे भर्ती किये गये
दूसरी रिक्ति	सीजनल कलेक्शन अमीन
तीसरी रिक्ति	सीधे भर्ती किये गये
चौथी रिक्ति	सीजनल कलेक्शन अमीन
पाँचवीं रिक्ति	सीधे भर्ती किये गये
छठी रिक्ति	पदोन्नत कलेक्शन चपरासी
सातवीं रिक्ति	सीधे भर्ती किये गये
आठवीं रिक्ति	सीजनल कलेक्शन अमीन
नवीं रिक्ति	सीधे भर्ती किये गये
दसवीं रिक्ति	सीजनल कलेक्शन अमीन
ग्यारहवीं रिक्ति	सीधे भर्ती किये गये
बारहवीं रिक्ति	पदोन्नत कलेक्शन चपरासी
तेरहवीं रिक्ति	सीधे भर्ती किये गये
चौदहवीं रिक्ति	सीजनल कलेक्शन अमीन
पन्द्रहवीं रिक्ति	सीधे भर्ती किये गये
सोलहवीं रिक्ति	सीजनल कलेक्शन अमीन
सत्रहवीं रिक्ति	सीधे भर्ती किये गये
अट्ठारहवीं रिक्ति	सीजनल कलेक्शन अमीन
उन्नीसवीं रिक्ति	सीधे भर्ती किये गये
बीसवीं रिक्ति	पदोन्नत कलेक्शन चपरासी

यदि रिक्तियों की संख्या बीस से अधिक हो तो उपर्युक्त क्रम को दोहराया जायेगा।

CHAPTER XXI
The Uttar Pradesh Revenue Consolidation (Higher)
Service Rules, 1992¹

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2132/1-8-92-54/2/83-Revenue-8, dated July 3, 1992 :

No. 2132/1-8-92-54/2/83-Revenue-8 July 3, 1992 :- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Revenue Consolidation (Higher) Service.

Part I - General

1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Revenue Consolidation (Higher) Service Rule, 1992."

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the service :- The Uttar Pradesh Revenue Consolidation (Higher) service a State Service comprising group 'A' and 'B' posts.

3. Definitions :- In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context,-

- (a) "appointing authority" means the Consolidation Commissioner in respect of the post of Assistant Settlement Officer Consolidation and the Governor in respect of other posts;
- (b) "citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution;
- (c) "Constitution" means the Constitution of India;
- (d) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;
- (e) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
- (f) "member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;
- (g) "Service" means the Uttar Pradesh Revenue Consolidation (Higher) Service;
- (h) "substantive appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being, by executive instructions issued by the Government;
- (i) "year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

¹ Vide Notification No. 2132/1-8-92-54/2/83-Revenue of dated July 3, 1993 published in U. P. Gazette dated 11-9-1993.

Part II - Cadre

4. Cadre of service :- (1) The strength of the Service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service and of each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Appendix;

Provided that :

(1) The appointing authority may leave unfilled or hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(2) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper,

Part III - Recruitment

5. Source of recruitment :- Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :

- | | |
|--|---|
| (1) Assistant Settlement Officer Consolidation | By promotion from amongst Consolidation officers who are substantively appointed and who are continuing as such as on the first day of the year of recruitment. |
| (2) Settlement Officer Consolidation | ¹ [By promotion from amongst substantively appointed Consolidation Officers, Rectangular Officers, Deputy Assistant Director Consolidation and Assistant Settlement Officers Consolidation, who has completed three years service as such on the first day of the year of recruitment. |
| (3) Assistant Director Consolidation | By promotion from amongst Settlement Officers Consolidation who are substantively appointed and who are continuing as such on the first day of the year of recruitment. |
| (4) Deputy Director Consolidation | By promotion from amongst substantively appointed Assistant Directors Consolidation who have completed two years of service as such on the first day of the year of recruitment : |

1. Substituted by notification No. 54/(1) 994-609 Revenue 8 Feb. 23, 1996.

Provided that if suitable candidates are not available, the field of eligibility may be extended to include substantively appointed Settlement Officers Consolidation who are confirmed on immediately lower post and have also completed two years of service on the post of Settlement Officer Consolidation on the first day of the year of recruitment.

(5) Joint Director Consolidation

By promotion from amongst substantively appointed Deputy Directors Consolidation who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.

(6) Additional Director Consolidation (Technical)

By promotion from amongst substantively appointed Joint Directors Consolidation who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.

Provided that, if suitable candidates are not available, the condition of two years service may be relaxed by the appointing authority.

6. Reservation :- Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the order of the Government in force at the time of the recruitment.

Part IV - Procedure for recruitment

7. Determination of vacancies :- The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies, if any, to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

8. Procedure for recruitment by promotion :- ¹[Recruitment by promotion to the post of Assistant Settlement Officer Consolidation, Settlement Officer Consolidation, Assistant Director Consolidation, Deputy Director Consolidation, Joint Director Consolidation, and Additional Director Consolidation (Technical) shall be made on the basis of the criterion specified in the Uttar Pradesh Government Servants (Criterion for recruitment by promotion) Rules, 1994 as amended from time to time through the Selection Committee constituted in accordance with the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for post outside the purview of the Public Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility list or lists of candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by selection (On posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended

1. Sub by Notification 54 (1) 94-609 Revenue-8 Dated 23.2.96

from time to time and place the same before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare separate lists of selected candidates for each category of posts arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.]

Part V - Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

9. Appointment :- (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under sub-rule (8) of rule 8.

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted.

10. Probation :- (1) A person substantively appointed to a post in the Service shall be placed on probation for a period of the year.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is graced.

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has to made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post.

(4) A probationer who is reverted under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

11. Confirmation :- The order issued by the appointing authority under sub-rule (3) rule 5 of the Uttar Pradesh State Government Servants' Confirmation Rules, 1991, declaring that the probationer has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

12. Seniority :- The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules. 1991, as amended from time to time.

Part VI - Pay etc.

13. Scale of pay :- (1) The scales of pay admissable to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

U. P. Revenue Consolidation (Higher) Service Rules, 1992

155

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given below:

Name of Post		Scale of Pay
1.	Assistant Settlement Officer, Consolidation	Rs. 2,000-60-2,300- E. B.-75-3,200-100-3,500
2.	Settlement Officer Consolidation	Rs. 2,200-75-2,800-E.B.-100-4,000.
3.	Assistant Director, Consolidation.	Rs. 2,200-75-2,800-E.B.-100-4,000 + special pay; as sanctioned by Govern- ment from time to time, in addition to pay in the scale.
4.	Deputy Director, Consolidation	Rs. 3,000-100-3,500-125-4,500
5.	Joint Director Consolidation	Rs. 3,700-125-4,700-150-5,000.
6.	Additional Director, Consolidation (Technical).	Rs. 4,500-150-5,700.

14. Pay during Probation :- (1) The pay during probation of person already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules;

Provided that if, the period of probation is extended on accounts of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

15. Criteria for crossing efficiency bar :- No person shall be allowed to cross the efficiency bar unless he has worked diligently and to the best of his ability, his work and conduct are found to be satisfactory, and his integrity is certified.

Part VII - Other provisions

16. Canvassing :- No recommendations, either written or oral, other than that required under the rules applicable to the post of service, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

17. Regulation of other matters :- In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules regulations and orders applicable generally re Government servants serving in connection with the affairs of the State.

18. Relaxation in the conditions of service :- When the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

19. Savings :- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix**[See Rule 4 (2)]**

The sanctioned strength of the service and each category of posts at the commencement of the Rules :

Serial No.	Name of post	Number of posts		
		Permanent	Temporary	Total
1	2	3		
1.	Assistant Settlement Officer Consolidation.	30	..	30
2.	Settlement Officer, Consolidation.	21	7	28
3.	Assistant Director, Consolidation	11	..	11
4.	Deputy Director, Consolidation.	13	..	13
5.	Joint Director Consolidation.	..	2	2
6.	Additional Director, Consolidation (Technical).	..	1	1

CHAPTER XVI

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (सुपरवाइजर कानूनगो)

सेवा नियमावली, 1977

U. P. Adhinishtha Rajsaw Karyapalak (Supervisor Kanungo)

Sewa Niyamawali, 1977

सं० 51-7 (1)/68-ए-राजस्व-9 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल अधीनस्थ कार्यपालक (सुपरवाइजर कानूनगो) सेवा में भर्ती को, और उनमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

अध्याय एक - सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (सुपरवाइजर कानूनगो) सेवा नियमावली, 1977 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तर काशी और पिथौरागढ़ के जिलों, जिला नैनीताल की पर्वतीय पट्टी और जिला देहरादूर के जानसार बाबर परगना को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में नियुक्त सुपरन्यूमरेरी कानूनगो और सुपरवाइजर कानूनगो पर लागू होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति :- अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (सुपरवाइजर कानूनगो) सेवा अराजपत्रित वर्ग 'ग' सेवा है।

परिभाषाएँ :- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

(क) "आयोग" का तात्पर्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है।

(ख) "आयुक्त" का तात्पर्य डिविजन के आयुक्त से है और इसमें अपर आयुक्त भी सम्मिलित है।

(ग) "कलेक्टर" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है और इसमें जिले का अपर कलेक्टर, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है।

(घ) "परिषद्" का तात्पर्य राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, से है।

(ङ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक है समझा जाय।

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

(ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों में, आदेशों के उपबन्धों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से है।

(झ) "स्कूल" का तात्पर्य सर्वे ऐण्ड लैण्ड रिकार्ड्स ट्रेनिंग संस्थान, हरदोई, उत्तर प्रदेश से है।

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (सुपरवाइजर कानूनगो) सेवा से है।

अध्याय दो - संवर्ग

4. सेवा की सदस्य संख्या :- (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की स्थायी सदस्य संख्या, जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने का आदेश न दिया जाय- (1) सुपरवाइजर कानूनगो 758, जिसमें छुट्टी के लिये पन्द्रह आरक्षित पद भी सम्मिलित हैं, और (2) सुपरन्यूमेरी कानूनगो 100 होगी, परन्तु।

(1) राज्यपाल समय-समय पर संवर्ग में ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जिन्हें वह आवश्यक समझे,

(2) राज्यपाल संवर्ग में किसी पद को आस्थगित रख सकते हैं या परिषद् किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकती है और ऐसा किये जाने पर कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

अध्याय तीन - भर्ती

5. भर्ती का स्रोत :- सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार की जायगी-

(क) सीधी भर्ती द्वारा, जैसा इन नियमावली के अध्याय पाँच में व्यवस्थित है,

(ख) स्थायी लेखपालों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) स्थायी भूमि अर्जन अमीनों की पदोन्नति द्वारा, और

(घ) सर्वेक्षण अमीनों का चयन करके।

6. हरदोई ट्रेनिंग संस्थान में प्रवेश :- सेवा में भर्ती के प्रयोजनार्थ, अभ्यर्थियों के लिये सर्वेण्ड लैण्ड रिकार्ड्स ट्रेनिंग, संस्थान, हरदोई में प्रशिक्षण लेना और प्रशिक्षण का विहित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

7. भर्ती का अनुपात :- (1) संस्थान में, प्रशिक्षण के प्रत्येक पाठ्यक्रम में नियम 5 में उल्लिखित स्रोतों से रिक्तियों का वितरण, यथाशक्य निम्नलिखित अनुपात में होगा-

(क) रिक्तियों का 33-1/3 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी,

(ख) 60 प्रतिशत रिक्तियां उन स्थायी नियमित लेखपालों में से, जिन्होंने उस वर्ष की, जिसमें चयन किया जाय, पहली जुलाई को लेखपाल के रूप में कम से कम दस वर्ष की लगातार सेवा की हो, अभ्यर्थियों का चयन करके भरी जायेगी, और

(ग) शेष रिक्तियां सर्वेक्षण अमीनों और स्थायी भूमि अर्जन में से चयन द्वारा भरी जायेंगी।

(2) सर्वेक्षण अमीनों और स्थायी भूमि अर्जन अमीनों के बीच प्रतिशत का अनुपात प्रत्येक चयन के समय सर्वेक्षण अमीनों और स्थायी भूमि अर्जन अमीनों का सापेक्ष संख्या को दृष्टि में रखते हुए परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जायगा।

8. रिक्तियों की संख्या का अवधारण :- प्रत्येक कलेन्डर वर्ष के प्रारम्भ होने पर परिषद् वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की संख्या सुनिश्चित करेगी और संस्थान में प्रशिक्षण के उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नियम 7 में उल्लिखित प्रत्येक स्रोत से चयन किये जाने के लिये अपेक्षित संख्या विनिश्चित करेगी।

अध्याय चार - अर्हतायें

9. स्वस्थता :- (1) किसी व्यक्ति को संस्थान में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने सरकारी कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

परन्तु स्थायी लेखपालों और स्थायी भूमि अर्जन अमीनों के मामले में चिकित्सीय परीक्षा आवश्यक न होगी।

(2) किसी ऐसे अभ्यर्थी से जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में न हो, स्कूल में उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के पूर्व यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैंडबुक, खण्ड-2, भाग-3 के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी से स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

10. राष्ट्रीयता :- सीधी भर्ती के माध्यम से उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी का-

(क) भारत का नागरिक

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और किसी पूर्वी अफ्रीकी देश कैन्या, उगाण्डा, जंजीबार से प्रव्रजन किया हो, होना आवश्यक है,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसा अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के पश्चात् सेवा में केवल तब ही रखा जा सकता है यदि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामलों में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न उसे देने से इंकार किया गया हो; किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अस्थायी रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि वह बाद में आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में जारी किया जाय।

11. आयु :- सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि उसने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा के दिनांक को अनुवर्ती 1 जनवरी को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु 27 वर्ष से अधिक की आयु न प्राप्त की हो।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य ऐसी श्रेणियों के जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचित करे, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्च आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय-

12. शैक्षिक अर्हता :- सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

13. चरित्र :- सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का चरित्र अवश्य ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह इस विषय में अपना समाधान कर ले।

टिप्पणी :- संघ, सरकार, किसी राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी निकाय या निगम या उपक्रम द्वारा प्रदत्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिए दोष-सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

14. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण :- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के सदस्यों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त आरक्षण के आदेशों के अनुसार होगा।

टिप्पणी :- इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

अध्याय पाँच - सीधी भर्ती के माध्यम से चयन की प्रक्रिया

15. सीधी भर्ती के लिए चयन की प्रक्रिया :- (1) परिषद् प्रति वर्ष संस्थान में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने के कम से कम आठ मास पूर्व संस्थान में प्रशिक्षण के लिए सीधी भर्ती द्वारा प्रविष्टि किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आयोग को सूचित करेगा।

(2) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञा का आवेदन-पत्र, विज्ञापन के माध्यम से आयोग द्वारा मांगा जायगा और उसे विहित प्रपत्र में, जिसे मूल्य देकर आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे समय के भीतर दिया जायगा जो विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित नियम और पाठ्यक्रम :- विवरण ऐसा होगा जैसा आयोग राज्यपाल के अनुमोदन से समय-समय पर विहित करें।

टिप्पणी :- इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त नियम और पाठ्य विवरण परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

(4) आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और ऐसे अभ्यर्थियों से, जो पात्र समझे जायें, उस दिनांक को जिसे आयोग विनिर्दिष्ट करे, परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

(5) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में मिले अंक प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात आयोग अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए सम्यक् प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लिखित परीक्षा में उनके द्वारा युक्ति-युक्त स्तर प्राप्त करने के अधीन रहते हुए, उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा जितने अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण स्कूल में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा में अपनी उपयुक्तता प्रदर्शित की हो। व्यक्तित्व परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए अंक को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायगा।

(6) तत्पश्चात आयोग अंकों के योग द्वारा अवधारित योग्यता क्रम में चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा।

अध्याय छः - स्कूल में प्रवेश के लिए स्थायी लेखपालों का चयन।

16. चयन का मापदण्ड संस्थान में प्रवेश के लिए सभी स्तर पर लेखपालों के लिए चयन का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता होगी।

17. चयन की प्रक्रिया :- स्थायी लेखपालों में से संस्थान में प्रवेश के लिए चयन किए जाने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायगी :-

(क) परिषद् प्रति वर्ष आयुक्त को पहली मार्च तक प्रत्येक डिवीजन से नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सूचित करेगा,

(ख) अभ्यर्थियों का नाम-निर्देशन, प्रथमतः कलेक्टर द्वारा किया जायगा, जो अपने द्वारा किए गए नाम निर्देशन को वर्ष की पहली जून तक परिशिष्ट 'ब' में दिए गए प्रपत्र में आयुक्त को भेजेगा,

(ग) आयुक्त, डिवीजन में जिलों के कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट समस्त लेखपालों के मामलों पर विचार करेगा। यह कलेक्टरों द्वारा संस्तुत नामों में से, अपने डिवीजन से उतने अभ्यर्थियों को नाम-निर्दिष्ट करेगा, जितने नाम की उपर्युक्त उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन परिषद्

द्वारा अपेक्षा की जाय और उनके नाम ज्येष्ठता-क्रम में रखेगा। वह नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची उनकी चरित्र पंजियों सहित वर्ष की पहली जुलाई तक परिषद को भेजेगा।

(2) कलेक्टर और आयुक्त अपने नाम निर्देशन क्रमशः आयुक्त और परिषद को भेजते समय समस्त ऐसे लेखपालों को यदि कोई हो, जिनका अतिक्रमण कर दिया गया हो, ऐसे अतिक्रमण का कारण देते हुए एक सूची भी भेजेगा।

(3) संस्थान में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन अन्तिम रूप से परिषद द्वारा किया जायगा। यदि परिषद यह आवश्यक समझे कि आयुक्त से प्राप्त सूची के किसी या समस्त अभ्यर्थियों को चयन के पूर्व, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए तो वह इस प्रयोजन के लिए अभ्यर्थियों को बुला सकती है।

18. प्रशिक्षण के दौरान लेखपाल कर्तव्यस्थ माने जायेंगे :- लेखपाल अभ्यर्थी, जब वह प्रशिक्षण पर हो, कर्तव्यस्थ माने जायेंगे और लेखपाल के रूप में अनुमन्य अपना वेतन और भत्ता पायेंगे।

अध्याय सात - संस्थान में प्रवेश के लिए सर्वेक्षण अमीनों और स्थायी

भूमि अर्जन अमीनों का चयन।

19. संस्थान में प्रवेश के लिए पात्रता :- कोई सर्वेक्षण अमीन और कोई स्थायी भूमि अर्जन अमीन संस्थान में प्रवेश के लिए पात्र होगा, यदि

- (क) उसने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो,
- (ख) उससे उस वर्ष की पहली जुलाई को सर्वेक्षण अमीन या भूमि अर्जन अमीन के रूप में या किसी उच्च पद पर कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा की हो।

20. चयन का मानदण्ड :- सर्वेक्षण अमीन और स्थायी भूमि अर्जन अमीन का प्रत्येक मामले में, चयन पात्र अभ्यर्थियों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर किया जायगा।

21. चयन की प्रक्रिया :- संस्थान में प्रवेश के लिए सर्वेक्षण अमीनों और स्थायी भूमि अर्जन अमीनों के चयन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा :

- (क) परिषद प्रति वर्ष पहली मार्च तक सर्वेक्षण अमीनों और स्थायी भूमि अर्जन अमीनों में से मनोनीत किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बन्दोबस्त आयुक्त/जिलाधिकारी को सूचित करेगा;
- (ख) ऐसे अभ्यर्थियों की जिसका अतिक्रमण कर दिया गया हो, यदि कोई हो, ऐसे अतिक्रमण के कारण देते हुए, सूची भी बन्दोबस्त आयुक्त/जिलाधिकारियों द्वारा पृथक रूप से तैयार की जायगी;
- (ग) अभ्यर्थियों की उपर्युक्त सूची, उनकी पद-क्रम सूची और चरित्र पंजियों के साथ उस वर्ष, जिसमें चयन किया जाय, पहली जुलाई तक परिषद को भेज दी जायगी;
- (घ) परिषद स्व-विवेकानुसार, रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में पात्र अभ्यर्थियों के ज्येष्ठताक्रम में या समस्त पात्र अभ्यर्थियों के नाम और अभिलेख मंगा सकती है।
- (ङ) परिषद उन ज्येष्ठतम सर्वेक्षण अमीनों और स्थायी भूमि अर्जन अमीनों की जो नियम 14 के साथ पठित नियम 5 (ग) और 5 (घ) के अधीन सुपरवाइजर कानूनगो के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र हो पृथक-पृथक दो सूची तैयार करेगा। इन सूचियों में यथाशक्य, सर्वेक्षण अमीनों और स्थायी भूमि अर्जन अमीनों में से भरी जाने के लिए अपेक्षित रिक्तियों की संख्या के पाँच गुने के बराबर नाम होंगे।
- (च) परिषद उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन बन्दोबस्त आयुक्त/जिलाधिकारी द्वारा भेजी गयी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की, और उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित अभ्यर्थियों की, जिन्हें चयन के लिए उपर्युक्त नहीं समझा गया, चरित्र पंजियों और अन्य सुसंगत अभिलेखों पर, यदि कोई हो

और ऐसे अन्य नामों और अभिलेखों पर भी, जिन्हें परिषद उपर्युक्त खण्ड (घ) के अधीन मंगाये, विचार करेगी और तत्पश्चात् अन्तिम चयन करेगी। यदि परिषद आवश्यक समझे तो वह बन्दोबस्त आयुक्त/जिलाधिकारी से प्राप्त सूची के किसी या सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुला सकती है। सर्वेक्षण अमीनों और स्थायी भूमि अर्जन अमीनों में से चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची परिषद द्वारा तैयार की जायगी।

(छ) यदि उपर्युक्त खण्ड (ग) के अधीन बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा भेजी गयी सूची में उपर्युक्त अभ्यर्थियों के नाम अपेक्षित संख्या में नहीं है, तो परिषद उस कमी को पूरा करने के लिए नियमित लेखपालों का चयन कर सकती है।

22. प्रशिक्षण के दौरान सर्वेक्षण अमीनों और स्थायी भूमि अर्जन अमीनों को भुगतान :- सर्वेक्षण अमीनों में से चयन किये गये अभ्यर्थी संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान कर्तव्यस्थ नहीं माने जायेंगे और उन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत वृत्ति मिलेगी। स्थायी भूमि अर्जन अमीन, जब वे प्रशिक्षण पर हों कर्तव्यस्थ माने जायेंगे, यदि वे संस्थान में प्रवेश करने के दिनांक से ठीक पूर्व इस रूप में कार्य कर रहे हों, और स्थायी भूमि अर्जन अमीन के रूप में उन्हें अनुमन्य अपने वेतन और भत्ते अपने मूल विभाग से मिलेंगे।

अध्याय आठ - संस्थान में प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम अनुशासन और डिप्लोमा का स्तर।

23. चयन किये गये अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण :- संस्थान में प्रवेश के लिए चयन किये गये अभ्यर्थी अपेक्षित दिनांक पर, जो सामान्यतः पहली नवम्बर होगा, संस्थान में प्रवेश करेंगे और एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। संस्थान के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सर्वेक्षण (जिसमें धीओडोलाइट और प्रिज्म कम्पाज द्वारा सर्वेक्षण भी सम्मिलित है) क्षेत्रमिति-भू-अभिलेख, राजस्व विधि और प्रक्रिया, जोत चकबन्दी अधिनियम प्रायोगिक कृषि और ग्रामीण अर्थशास्त्र, जिसके अन्तर्गत नियोजन और विकास भी हैं, सम्मिलित होंगे, फिर भी प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम विवरण में परिषद द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

24. बन्ध पत्र का निष्पादन :- संस्थान में प्रवेश के लिए चयन किया गया प्रत्येक अभ्यर्थी अपने प्रवेश के पूर्व संस्थान के प्राचार्य की उपस्थिति में सरकार द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में, विहित मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर 500 रुपये का एक बन्धपत्र निष्पादित करेगा, जिसमें अपना प्रशिक्षण सफलता-पूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात् कम से कम दो वर्ष के लिये सुपरन्यूमरेरी कानूनगो/सुपरवाईजर कानूनगो के रूप में सेवा करने का वचन देगा। सुपरन्यूमरेरी/कानूनगो/ सुपरवाईजर कानूनगो के रूप में सेवा न करने या सेवा करने से इन्कार करने या बन्ध-पत्र के किसी निबंधन या शर्त का उल्लंघन करने पर वह बन्ध-पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करने के लिये राज्य सरकार को अनुबद्ध धनराशि देगा। इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि प्राप्ति शीर्षक "9-ख-भू-राजस्व-प्रकीर्ण मालिकाना राजस्व अन्य प्राप्तियों" में जमा की जायगी।

25. अनुशासन :- (1) अभ्यर्थियों से पूरे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान अच्छा चरित्र बनाये रखने की अपेक्षा की जायेगी और वे संस्थान के प्राचार्य के नियन्त्रण और अनुशासन में रहेंगे।

(2) परिषद संस्थान के प्राचार्य की सिफारिश पर नियम 15 के अधीन सीधे चयन किये गये किसी प्रशिक्षार्थी को संस्थान की नामावली से हटा सकता है और किसी ऐसे परीक्षार्थी को, जो नियम 17 या 19 के अधीन चयन किया गया था, उस पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है, जिस पद से उसका चयन किया गया था।

परन्तु किसी व्यक्ति को बिना ऐसी जाँच के जिसमें उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गयी हो और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, इस प्रकार हटाया या प्रत्यावर्तित नहीं किया जायगा।

26. अर्हकारी परीक्षा :- (1) प्रशिक्षण पत्र की समाप्ति पर एक अर्हकारी परीक्षा होगी, जिसका प्रबन्ध परिषद द्वारा किया जायगा। सामान्यतया किसी अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि वह सत्र के दौरान जब संस्थान खुला रहा हो, कम से कम 80 प्रतिशत दिनों तक कक्षा में उपस्थित न रहा हो। फिर भी अपवादिक मामलों में परिषद इस शर्त को शिथिल कर सकती है।

(2) (क) ऐसे अभ्यर्थी जो दो से अधिक विषयों में अर्हकारी परीक्षा में असफल रहता है परिषद द्वारा संस्थान में चार मास अग्रेतर संक्षिप्त प्रशिक्षण प्राप्त करने का अनुमति दी जा सकती है। अग्रेतर प्रशिक्षण केवल उस विषय या उन विषयों में दिया जायगा, जिसमें वह पिछली परीक्षा में असफल हुआ था।

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट अग्रेतर प्रशिक्षण की समाप्ति पर संस्थान में परिषद द्वारा अभ्यर्थियों की एक अनुपूरक परीक्षा ली जायगी।

(ग) उप नियम (1) में उल्लिखित अर्हकारी परीक्षा में दो से अधिक विषयों में असफल होने वाले परीक्षार्थी को परिषद के स्वविवेकानुसार अगले सत्र में संस्थान में पुनः प्रवेश किया जा सकता है और उस स्थिति में उसे पूरी अवधि के लिए समस्त विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और समस्त विषयों में परीक्षा देनी होगी।

परन्तु यदि वह अनुवर्ती वर्ष में पुनः असफल हो जाता है तो उसे न तो पुनः संस्थान में प्रवेश दिया जायगा और न ही उसे इस उप नियम के खण्ड (क) या खण्ड (ग) में उल्लिखित सुविधा दी जायगी।

सभी सफल अभ्यर्थियों को संस्थान का डिप्लोमा दिया जायगा, किन्तु सीधी भर्ती द्वारा प्रवेश किये गये अभ्यर्थियों को डिप्लोमा तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उन्होंने अभिलेख क्रिया के अधीन किसी ज़िस्ते में या, जहां परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रबन्ध किया गया हो, तीन मास तक सर्वेक्षण और अभिलेख तैयार करने का अग्रेतर व्यावहारिक प्रशिक्षण न प्राप्त कर लिया हो और जब तक कि उन्होंने ऐसा प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर सम्बद्ध अभिलेख अधिकारी से प्रवीणता का प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया हो।

टिप्पणी :- किसी व्यक्ति को जिसे संस्थान के अपने डिप्लोमा की दूसरी प्रति अपेक्षित हो, कलेक्टर के माध्यम से परिषद को आवेदन करना चाहिए जो अपना समाधान करने के पश्चात कि आवेदक वही व्यक्ति है, जिसे मूल डिप्लोमा जारी किया गया था, 1 रुपये की फीस जिसे शीर्षक "9-ख-भू-राजस्व प्रकीर्ण मालिकाना राजस्व पटवारी प्रकीर्ण प्राप्ति" के अधीन जमा किया जायगा, वसूल करेगा और इस आशय के एक पृष्ठांकन सहित आवेदन पत्र को अग्रसारित करेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर डिप्लोमा की दूसरी प्रति, बिना कोई अग्रेतर प्रभार लिए, आवेदक को देने के लिए कलेक्टर को भेजी जायगी। डिप्लोमा की दूसरी प्रति पर लाल स्याही से "दूसरी प्रति" अंकित किया जायगा।

4- (क) परिषद, प्रत्येक वर्ष अर्हकारी परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य के लिये एक अधिकारी को नाम-निर्दिष्ट करेगा। अधीक्षक अपनी वारी में प्रवीक्षक नियुक्त करेगा, जो परीक्षा के दौरान किसी परीक्षार्थी द्वारा किये गये दुराचरण के, जिसमें अनुचित साधनों का प्रयोग करना या उसके लिए प्रयास करना भी सम्मिलित है, मामलों की सूचना देगे। अधीक्षक, स्वविवेकानुसार या तो परीक्षार्थी को आगे परीक्षा देने से वर्जित कर देगा या किसी विशेष प्रश्न-पत्र में प्राप्त अंकों में से अंक को काट दिये जाने का आदेश देगा। इस सम्बन्ध में अधीक्षक का आदेश अन्तिम होगा।

(ख) दुराचरण के जिसमें अनुचित साधनों का प्रयोग भी सम्मिलित है, आधार पर परीक्षार्थी को आगे परीक्षा देने से वर्जित करने या प्राप्त अंकों में से अंक को काट लेने का आदेश दिये जाने के पूर्व अधीक्षक उसे प्रस्तावित कार्यवाही किये जाने के विरुद्ध कारण बताने का पूरा अवसर देगा।

अध्याय नौ - डिप्लोमाधारी और सुपरन्यूमरेरी कानूनगो

27. डिप्लोमाधारी :- परिषद ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया है और संस्थान का डिप्लोमा प्राप्त करने के हकदार हैं, एक सूची रखेगी। सूची में नाम, अभ्यर्थी द्वारा संस्थान की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष और उस परीक्षा में उसे प्राप्त स्थान के अनुसार क्रमबद्ध किये जायेंगे।

परन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने समान स्थान प्राप्त किया हो तो उनके नाम आयु के अनुसार क्रमबद्ध किये जायेंगे। अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायगा।

28. सुपरन्यूमरेरी कानूनगो के रूप में नियुक्ति :- (1) केवल वे ही अभ्यर्थी जिनके नाम डिप्लोमाधारियों की सूची में हो सुपरन्यूमरेरी कानूनगो के रूप में नियुक्त किये जाने के पात्र होंगे। जब सुपरन्यूमरेरी कानूनगो के पद में कोई रिक्ति हो तब कलेक्टर इस तथ्य की सूचना परिषद को देगा। परिषद डिप्लोमाधारियों की सूची में आये हुए अभ्यर्थी के नाम की सूचना कलेक्टर को देगा।

2- किसी सुपरन्यूमरेरी कानूनगो को, जब उसके लिए सुपरवाईजर कानूनगो के रूप में कार्य करने की व्यवस्था न हो, सदर कानूनगो या सुपरवाईजर कानूनगो के कार्यालय से, जहां भी कार्य हित में आवश्यक हो, सम्बद्ध कर दिया जायगा।

अध्याय दस - सुपरवाईजर कानूनगो के रूप में नियुक्ति, परीवीक्षा और स्थायीकरण

29. नियुक्ति प्राधिकारी :- सुपरन्यूमरेरी कानूनगो और सुपरवाईजर कानूनगो के पद के सम्बन्ध में कलेक्टर नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

30. सुपरवाईजर कानूनगो के रूप में नियुक्ति :- (1) परिषद समस्त सुपरन्यूमरेरी कानूनगो की एक सूची रखेगी। उनके नाम उसी क्रम में क्रमबद्ध किये जायेंगे, जिनमें वे नियम 27 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों।

(2) जब किसी जिले में सुपरवाईजर कानूनगो के पद में कोई रिक्ति हो तो कलेक्टर इसकी सूचना परिषद को देगा। परिषद ऐसी नियुक्ति के लिए उप-नियम [1] के अधीन रखी गई सूची में से अभ्यर्थी के नाम की संसूचना कलेक्टर को देगी। कलेक्टर तदनुसार नियुक्ति करेगा।

31. स्थानापन्न और अस्थायी नियुक्ति :- (1) तीन मास से अनधिक अवधि की किसी अस्थायी या स्थानापन्न रिक्ति में कलेक्टर जिले में उपलब्ध सुपरन्यूमरेरी कानूनगो/सुपरवाईजर कानूनगो के पद पर नियुक्त कर सकता है।

(2) यदि जिले में सुपरन्यूमरेरी कानूनगो उपलब्ध न हो और अस्थायी रिक्ति तीन मास से अधिक अवधि की हो तो उस अभ्यर्थी को, जिसका नाम नियम 30 के अधीन परिषद से प्राप्त हो, नियुक्त किया जायगा।

32. परीवीक्षा :- (1) सुपरवाईजर कानूनगो के पद पर किसी मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रखा जायगा।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे परीवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है। इस प्रकार परीवीक्षा अवधि बढ़ाये जाने के किसी आदेश में वह दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जब तक के लिए परीवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय और यह भी विनिर्दिष्ट किया जायगा कि बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन के समय मान में वेतन वृद्धि के प्रयोजनार्थ की जायगी या नहीं।

(2) सुपरवाईजर कानूनगो के पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई अनवरत सेवा की परीवीक्षा अवधि की सगणना करने में विचार किया जा सकता है।

(3) यदि परीवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परीवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय यह प्रतीत हो कि परीवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या अन्यथा सन्तोषजनक रूप से

कर्तव्य पालन में असफल रहा है तो उसे यदि वह नियमित लेखपाल या स्थायी भूमि अर्जन अमीन में से सुपरवाईजर कानूनगो नियुक्त किया गया है, उस पद पर जिस पर वह संस्था में अपने प्रवेश के पूर्व था, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि वह सीधी भर्ती द्वारा या सर्वेक्षण अमीन में से नियुक्त किया गया हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं, जिसके लिए वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

33. स्थायीकरण :- उस व्यक्ति से जिसे नियम 32 (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी जायें, भिन्न परिवाक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति परीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परीक्षा अवधि के अन्त में सुपरवाईजर कानूनगो के पद पर स्थायी कर दिया जायगा, यदि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक रहा हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

34. ज्येष्ठता :- नियम 44 में व्यवस्था की गई है उसके सिवाय किसी वर्ष में सुपरवाईजर कानूनगो के पद नियुक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता नियम 27 के अधीन रखी गई डिप्लोमाधारियों की सूची में उनकी पद स्थिति के अनुसार आधारित की जायगी।

परन्तु कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो देगा यदि वह किसी वैध कारण के, जब उससे किसी रिक्ति में कार्य करने का प्रस्ताव किया जाय, कार्य-भार ग्रहण नहीं करता।

टिप्पणी :- कारण की वैधता के सम्बन्ध में परिषद का विनिश्चय अन्तिम होगा। परन्तु यह और कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व स्थायी किये गये सुपरवाईजर कानूनगो की ज्येष्ठता वही बनी रहेगी जैसी कि वह अस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर थी।

अध्याय ग्यारह - वेतन

35. वेतनमान :- (1) (क) सुपरवाईजर कानूनगो के रूप में नियुक्त डिप्लोमाधारियों की वही नियत वेतन अनुमन्य होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाय।

(ख) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य नियत वेतन की धनराशि 200,00 रुपये प्रतिमाह है।

(2) (क) सुपरवाईजर कानूनगो पद पर मौलिक स्थानापन्न या अस्थाई रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाय।

(ख) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वेतनमान निम्नलिखित है-

पुराना वेतनमान 30, सितम्बर, 1975 तक

नया वेतनमान

1 अक्टूबर 1975 से

230-6-290-द० रो०-8-330-

250-7-285-

द० रो० 10-380

द० रो०-9-375-द० रो० 10-425

संक्षिप्त टिप्पणी :- समता सीमित की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान संशोधित कर दिये गये हैं। राज्य सरकार ने दिनांक 1-1-1986 से इसको लागू कर दिया है।

(देखिये अध्याय XXXVIII)

36. परीक्षा-अवधि का वेतन :- (1) सुपरवाईजर के पद पर परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षा अवधि में, उस वेतनमान का न्यूनतम मिलेगा, जो उसे अनुमन्य हो, जब तक कि वह तत्समय प्रवृत्त वित्तीय नियमों के अनुसार उच्च वेतन पाने का हकदार न हो और वेतन-वृद्धि जब वे प्रोद्भूत हों मिलेगी, परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न करने के कारण परीक्षा अवधि की गणना तब तक वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) उस व्यक्ति का वेतनमान जो सेवा में भर्ती के पूर्व पहले से ही सरकारी सेवा में मौलिक पद पर हों नियम 41 में निर्दिष्ट सुसंगत नियमों के अनुसार नियत किया जायगा।

37. दक्षता-रोक पार करने के लिए मानदण्ड :- (1) किसी सुपरवाइजर कानूनगो को वेतन के समय-मान में प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसके सेवा अभिलेख से यह न प्रदर्शित हो कि उसने धीरतया और अपनी यथोक्तता और पूरी सत्यनिष्ठा से कार्य किया है।

(2) किसी सुपरवाइजर कानूनगो को द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति जब तक नहीं दी जायगी जब तक कि यह न पाया जाय कि उसे नियमों का पर्याप्त ज्ञान है और उसमें प्रशासनिक व्यवहार, कुशलता और योग्यता है और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

अध्याय बारह - छुट्टी, स्थानांतरण, पेन्सन और सेवा की अन्य शर्तें

38. पक्ष समर्थन :- इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफरिशों से भिन्न सिफरिशों पर चाहें वे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। अभ्यर्थी की ओर से संस्थान में उद्देश्य पाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्थता के लिए समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयत्न उसे अनर्ह कर देगा।

39. छुट्टी :- (1) कलेक्टर सुपरवाइजर कानूनगो और सुपरन्यूमेरी कानूनगो को छुट्टी देने के लिए प्राधिकृत हैं।

(2) जब किसी जिला या जिले के किसी भाग में अभिलेख या बन्दोबस्त या चकबन्दी क्रिया चल रही हो तब जिले के यथास्थिति अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी या जिला उप चकबन्दी निदेशक को अपने अधीनस्थ सुपरन्यूमेरी कानूनगो और सुपरवाइजर कानूनगो के सम्बन्ध में वही शक्तियां होंगी जो उप नियम (1) के अधीन कलेक्टर को प्राप्त हैं।

40. स्थानान्तरण :- किसी जिले के भीतर सुपरन्यूमेरी कानूनगो और सुपरवाइजर कानूनगो का स्थानान्तरण उस जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायगा। डिवीजन के भीतर एक जिले से दूसरे जिले को स्थानान्तरण उस डिवीजन के आयुक्त द्वारा ऐसी रीति से किया जायगा, जिससे कि परिषद के अनुमोदन के बिना किसी जिले की अस्थायी या स्थायी पदों की संख्या में परिवर्तन न हो।

परन्तु जब किसी जिला या जिले के किसी भाग में अभिलेख या बन्दोबस्त या चकबन्दी क्रिया चल रही हो तब, यथास्थिति, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के नियंत्रण में नियोजित सुपरन्यूमेरी कानूनगो या सुपरवाइजर कानूनगो का स्थानान्तरण कलेक्टर ऐसे अधिकारी से परामर्श किये बिना जिले के भीतर नहीं करेगा।

41. अवशिष्ट विषय :- ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो इस नियमावली या इसके अधीन दिए गए या जारी किये गए आदेशों या विशेष आदेश के अधीन विशिष्ट रूप से न आते हों सेवा में नियुक्त व्यक्ति उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे जो राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हैं।

42. सेवा की शर्तों में शिथिलता :- (1) जहां राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है तो, वह इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिसे वह उस मामले के न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती हैं।

परन्तु यदि नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया था तो उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श करना होगा।

(2) यदि इस नियमावली को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, आयोग से परामर्श करने के पश्चात आदेश द्वारा इस नियमावली के उपबन्ध को उस सीमा तक शिथिल कर सकती है जहां तक वह कठिनाई दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो :

परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

43. संवर्ग का विस्तार :- सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक सामान्य संवर्ग होगा और उनका स्थानान्तरण उन समस्त क्षेत्रों, में, जहां नियम 1 (3) के अधीन यह नियमावली लागू होती हो, किया जा सकता है।

44. तराई भावर और स्टोन महाल क्षेत्रों के सुपरवाइजर कानूनगो का राज्य संवर्ग में विलयन :-
(1) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, और सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर भर्ती को और उस पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले समस्त वर्तमान नियमों का अतिक्रमण करके एतद्वारा व्यवस्था की जाती है कि -

(एक) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक पर जिला नैनीताल में तराई भावर क्षेत्र में, सुपरवाइजर कानूनगो के वर्तमान स्थायी पदों का उस दिनांक से सुपरवाइजर कानूनगो के राज्य संवर्ग में विलय होना समझा जायगा, और

(दो) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जाने वाले किसी आदेश में विनिर्दिष्ट भावी दिनांक पर जिला मिर्जापुर में, स्टोन महाल क्षेत्र में, सुपरवाइजर कानूनगो के वर्तमान स्थायी पदों का विलय ऐसे विनिर्दिष्ट दिनांक से सुपरवाइजर कानूनगो के राज्य संवर्ग में कर दिया जायगा।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता और सेवा के अन्य सदस्यों की ज्येष्ठता सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर मौलिक नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायगी।

आज्ञा से,
अतहर हुसैन
आयुक्त एवं सचिव

परिशिष्ट 'क'

[नियम 15 (3) के नीचे की टिप्पणी देखीए]

परीक्षा का पाठ्यक्रम

- | | |
|---|-----|
| 1- (एक) सामान्य ज्ञान-यह प्रश्न-पत्र इस प्रकार तैयार किया जायगा जिससे कि अभ्यर्थी के दिन प्रति दिन के व्यवहार में आने वाले विज्ञान, भूगोल, इतिहास और वर्तमान घटनाओं के ज्ञान की परीक्षा हो जाय। | अंक |
| (दो) सरल क्षेत्रमिति जिसमें निम्नलिखित प्रश्न होंगे। | 100 |
| (क) भुजा (साइड), लम्ब (परपेन्डीक्यूलर) और त्रिभुजाकार, आयत, चतुर्भुज, समाबहुभुज और ऋजुरेखीय आकृति (रेक्टीलीनियल फिगर्स)। | 100 |
| (ख) सिंगुलर फिगर्स, उनकी लम्बाई। | |

(ग) वृत्त की परिधि (सर्किल सरकम्फरेंस), व्यास और क्षेत्रफल

(घ) फील्ड बुक।

(तीन) अंकगणित और ज्यामिति	...	100
(चार) ग्रामीण अर्थशास्त्र, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा	...	100

उत्पादन के लिए अनिवार्य वस्तुएँ-उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलों, भूमि में कम उपज और उसके कारणों, जोतों के विखण्डन का सर्वेक्षण, महत्वपूर्ण कुटीर उद्योगों की विधियाँ या कृषि उपकरण। मिट्टी और खाद, सिंचाई, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलें, पशुधन और पशु उत्पाद, कृषि सम्बन्धी तकनीक और ग्रामीण उद्योग, रहन-सहन का स्तर ग्रामीण उत्पाद का विपणन उनकी कमियाँ और उसमें सुधार। ग्रामीण मण्डी-हाट, बाजार और मेला, उनकी उपयोगिता और संगठन, औद्योगिक और श्रमिक मजदूरों की मजदूरी-रूढ़ियाँ और परम्पराएँ और आर्थिक दशा पर उनका प्रभाव।

उत्तर प्रदेश में भौमिक अधिकार, ग्रामीण समस्याएँ, स्वच्छता, शिक्षा, मनोरंजन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान और उसके सिद्धान्त पशु-समस्या-सुधार के तरीके, विवाद, ऋण-ग्रस्तता-कारण और उसके उपाय। ग्राम और जिला प्रशासन-उत्तर प्रदेश की पंचायतें-पंचायत अधिनियम। सहकारी ऋण समितियाँ-प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियाँ उनका संगठन और कार्य प्रणाली। बहु-प्रयोजन समितियाँ।

कृषि ऋण समितियों से भिन्न कृषि समितियाँ। सहकारी विक्रय और सहकारी समितियाँ, सहकारी बैंक।

(पांच) हिन्दी	भाग एक - निबन्ध	60
	भाग दो - पांडुलिपि	40
(लिखित पांडुलिपि के अंशों को शीघ्रता से साफ लिपि में लिखना)		100
(छः) व्यक्तित्व परीक्षा		100

टिप्पणी :- सभी विषयों के प्रश्न-पत्र का स्तर (सरल क्षेत्रमिति और ग्रामीण अर्थशास्त्र को छोड़कर) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट की परीक्षा के स्तर का होगा।

2. पद संख्या (एक) से (चार) तक में उल्लिखित प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए तीन घंटे का समय दिया जायेगा किन्तु भाग एक हिन्दी (निबन्ध) का उत्तर देने के लिए दो घंटे का समय दिया जायेगा और भाग दो पांडुलिपि के लिए केवल आधे घंटे का समय दिया जायेगा।

3. प्रश्न-पत्र (दो) और (तीन) का उत्तर देने के लिए कम्पास और रूल का प्रयोग करने की अनुज्ञा होगी।

परिशिष्ट - 'ख'

[नियम 17 [1] [ख]]

सर्वे एण्ड लैण्ड रिकार्ड्स ट्रेनिंग स्कूल में प्रवेश के लिए कलेक्टर द्वारा नियमित लेखपालों के नाम निर्देश का प्रपत्र।

1. जिला का नाम.....
2. नाम निर्दिष्ट लेखपाल का नाम.....
3. लेखपाल के रूप में नियुक्ति का दिनांक.....

4. जन्म का दिनांक और लेखपाल नियुक्ति किये जाने के समय आयु.....
5. नाम निर्देशन के समय लेखपाल के रूप में वेतन.....
6. शैक्षिक अर्हतायें.....
7. अवधि जब तक के लिए (31 अगस्त को)
 - (एक) लेखपाल के रूप में.....
 - (दो) स्थानापन्न सुपरवाइजर कानूनगो के रूप में.....
 - (तीन) अभिलेख क्रिया या जोत चकबन्दी या भूमि अर्जन क्रिया अमीन के रूप में.....
कार्य किया।
 - (चार) किसी अन्य पद पर.....
8. पूर्ववर्ती नाम-निर्देशन यदि कोई हो, वर्ष.....
9. कलेक्टर की सिफारिश.....
10. अभियुक्ति.....

CHAPTER XV

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (पेशकार)

सेवा नियमावली, 1983

U. P. Adhinishtha Rajsan Karyapalak (Peshkar)

Sewa Niyamawali, 1983

संख्या-84-1 (2)/65-राजस्व -698

लखनऊ, 19 मार्च, 1983

अधिसूचना

सा० प० नि०-46

सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (पेशकार) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

भाग एक - सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (पेशकार) सेवा नियमावली, 1983 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्राप्ति :- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (पेशकार) सेवा अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएँ :

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से है।

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो सविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(ग) "आयोग" का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है।

संक्षिप्त टिप्पणी

लोक सेवा आयोग एक स्वतन्त्र बाडी है। इसका कार्य परीक्षा लेकर अभ्यर्थियों का चयन करना है। सभी सिविल पदों पर जो इसके अधीन आते हैं परीक्षा लेकर ज्येष्ठता के अनुसार शासन को नियुक्ति हेतु सूची भेजना इसका मुख्य कार्य है। नियुक्ति करने का अधिकार राज्य सरकार का है। शासन को यह अधिकार है कि लोक सेवा आयोग की संस्तुति स्वीकार करे या अस्वीकार की दशा में राज्य सरकार को इसका कारण बताना होता है एवं ऐसे मामले विधान मंडल से स्वीकृत कराये जाते हैं।

(ए० आई० आर० 1987 एस० सी० 169)

1989 (1) एस० एल० जे० एस० सी० 364

ए० आई० आर०, 1984 एस० सी० 1850

ए० आई० आर० 1987 उच्चतम न्यायालय 169

ए० आर०

- (घ) "आयुक्त" का तात्पर्य किसी मंडल के आयुक्त से है।
 (ङ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है।
 (च) "जिला अधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में किसी जिले के जिला अधिकारी से है।
 (छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।
 (ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।
 (झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।
 (ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (पेशकार) सेवा से है।
 (ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसूचित चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो।
 (ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. सेवा की सदस्य :- (1) संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर आधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य-संख्या निम्न प्रकार होगी :

पद का नाम	पदों की संख्या
पेशकार	स्थायी 36
(जिसके अन्तर्गत चयन श्रेणी के 4 पद भी हैं)	
	अस्थायी 2
	योग..... 38

परन्तु :-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझें।

भाग तीन - भर्ती

5. भर्ती का श्रोत :- सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी -

(एक) कुल रिक्तियों की एक-तिहाई रिक्तियां, जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, चमोली, टिहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी जिला नैनीताल की पर्वतीय पट्टियों और जिला देहरादून के परगना जौनसार

बाबर में नियुक्त ऐसे सुपरवाइजर कानूनगो में से जिन्होंने चयन के वर्ष की पहली जनवरी को मूल पद पर मौलिक और/या स्थानापन्न रूप में कुल मिलाकर कम से कम सात वर्ष की सेवा की हो, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी, और :

(दो) शेष दो-तिहाई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा।

6. आरक्षण :- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये राष्ट्रीयता आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

संक्षिप्त टिप्पणी

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी परीक्षा में सफल नहीं होता है। तो आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन करने में कोई अनियमिता नहीं है।

1989 (1) एस० एल० आर० पंजाब एण्ड हरियाणा 269

भाग चार - अर्हतायें

7. राष्ट्रीयता :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांयानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो, और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षिक अर्हतायें :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।

9. अधिमानी अर्हतायें :- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा जिसेन-

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10. आयु :- सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जूर की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को,

यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11. चरित्र :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी अन्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा।

12. वैवाहिक प्रास्थिति :- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थता और घुड़ सवारी का प्रमाण-पत्र :- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिसने उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेशियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी,

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती किये गये अभ्यर्थियों को, नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व, घोड़े की सवारी करने की अपनी योग्यता के बारे में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भाग पाँच - भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारण :- नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया :- (1) सेवा में सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा के लिये आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में मांगे जायेंगे जो आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) किसी अभ्यर्थी को तब तक परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।

(3) आयोग, लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणी बद्ध किये जाने के पश्चात्, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक्

प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक के हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों में कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतने अभ्यर्थियों को जितने वह उचित समझे, नियुक्ति के लिये संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायगा। सूची में नालों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं होगी) आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी 1 :- प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण और नियम वही होंगे जो नायब तहसीलदार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। इस समय प्रवृत्त पाठ्य विवरण परिशिष्ट "क" में दिया गया है।

टिप्पणी 2 :- आयोग स्वविवेक से इस सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा को किसी अन्य सेवा या सेवाओं से मिला सकता है।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :- पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार योग्यता के आधार पर की जायगी।

17. संयुक्त चयन सूची :- यदि सेवा में नियुक्ति पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार किये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

दृष्टान्त :- यदि नियुक्ति सीधी भर्ती (सी० भ०) और पदोन्नति (प०) दोनों प्रकार से 2:1 के अनुपात में की जानी हो और किसी विशिष्ट वर्ष में 18 रिक्तियां हैं तो ऐसी स्थिति में 12 रिक्तियां सीधी भर्ती वालों को और 6 रिक्तियां पदोन्नति किये गये व्यक्तियों को दी जायेंगी। चयन किये जाने के पश्चात् संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायगी :-

- | | |
|-----------|------------|
| 1- प० | 10- प० |
| 2- सी० भ० | 11- सी० भ० |
| 3- सी० भ० | 12- सी० भ० |
| 4- प० | 13- प० |
| 5- सी० भ० | 14- सी० भ० |
| 6- सी० भ० | 15- सी० भ० |
| 7- प० | 16- प० |
| 8- सी० भ० | 17- सी० भ० |
| 9- सी० भ० | 18- सी० भ० |

भाग छ: - नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति :- (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूची में हों।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची न तैयार कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एकाधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा। जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायगा, यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रूप में भी उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5 (क) के उपबन्धों के अधीन होगी।

19. विभागीय परीक्षा और प्रशिक्षण :- सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति से, परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण लेने की, जैसा राज्यपाल द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय अपेक्षा की जायगी।

20. परीक्षा :- (1) सेवा में किसी पद पर किसी स्थाई रिक्ति में, या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक कि अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परीक्षा-अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम [3] के अधीन जिस परीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21. स्थायीकरण :- किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि-

(क) उसने पेशकार के लिए विभागीय परीक्षा, यदि विहित हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

22. ज्येष्ठता :- (1) एतदपश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, सेवा में व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हों, अवधारित की जायगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

परन्तु वह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एकाधिक आदेश जारी किए जायें तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उप नियम (3) के अधीन जारी किए गए नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो आयोग द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्य-भार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण कि युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया।

भाग सात - वेतन आदि

23. वेतनमान :- (1) सेवा में पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान 515-15-590-18-626-द० रो० 18-680-20-780-द० रो० 20-860 रुपया है। सेवा में 680-20-780-द० रो० 20-920 रुपये की एक चयन श्रेणी भी अनुमन्य है जो मौलिक रूप में की गई 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् अनुमन्य होगी। चयन श्रेणी के पद पर नियुक्ति वित्त विभाग (वेतन आयोग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या वे० आ०-1842/दस-48 (एम)-1981, दिनांक 25 नवम्बर, 1981 में विहित मापदण्ड के अनुसार की जायगी।

संक्षिप्त टिप्पणी

समता सीमित की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान संशोधित कर दिये गए हैं। राज्य सरकार ने इन वेतन मानों को दिनांक 1 जनवरी 1986 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। (दिखिये अध्याय XXXVIII)

24. परिवीक्षा अवधि में वेतन :- (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा-अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्य कलाप के सम्बंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25. किसी व्यक्ति को-

(एक) प्रथम दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने विशिष्ट योग्यता और पूरी ईमानदारी से अपना कार्य न किया हो और उसका कार्य-और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय,

(दो) साधारण श्रेणी में द्वितीय दक्षता-रोक पार करने और चयन श्रेणी में दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसे उप तहसील (पेशकारी) का स्वतन्त्र प्रभार लेने के पूर्णतया योग्य न समझा जाय और उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ - अन्य उपबन्ध

26. पक्ष समर्थन :- पद या सेवा के सम्बंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

27. स्थानान्तरण :- पेशकार का स्थानान्तरण एक तहसील से दूसरी तहसील में उसके जिला अधिकारी द्वारा एक जिले से दूसरे में मण्डल आयुक्त द्वारा और एक मण्डल से दूसरे मण्डल में राजस्व परिषद् द्वारा किया जा सकता है।

28. अन्य नियमों का विनियमन :- ऐसे विषयों के सम्बंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त राज्य के कार्यकलाप के सम्बंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

29. सेवा की शर्तों में शिथिलता :- जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां, वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है, परन्तु उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श लिया जायगा।

30. व्यावृत्ति :- इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस सम्बंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशिष्ट श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

(नियम 15 देखिए)

प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्य-विवरण और नियम

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे और प्रत्येक विषय के लिए उसके सामने दिये गए अंक होंगे-

अनुभाग-क - सभी अभ्यर्थियों को इस अनुभाग के विषय लेने होंगे-

विषय	अंक
1- सामान्य हिन्दी और निबन्ध	100
2- सामान्य ज्ञान (जिसके अन्तर्गत साधारण विज्ञान भी है)	100
3- प्रारम्भिक गणित	100

अनुभाग-ख - प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित विषयों में से दो विषय लेना होगा :

4- सामान्य भारतीय इतिहास	100
5- सामान्य भूगोल	100
6- भौतिक विज्ञान	100
7- रसायन विज्ञान	100
8- अर्थ-शास्त्र	100
9- समाज-शास्त्र	100
10- बही-खाता और लेखा-शास्त्र	100
11- वनस्पति विज्ञान	100
12- प्राणि विज्ञान	100
13- अवर गणित	100
14- विधि	100
15- कृषि	100
16- राजनीति शास्त्र	100
17- मनोविज्ञान	100
18- सांख्यिकी	100
19- रसायनिक अभियांत्रिकी	100
20- संस्कृत साहित्य	100
21- हिन्दी साहित्य	100
22- उर्दू साहित्य	100
23- अंग्रेजी साहित्य	100
24- राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा	100
अनुभाग -	
25- व्यक्तित्व परीक्षा (मौखिक)	100

टिप्पणी :- ऊपर अनुभाग "क" और "ख" में उल्लिखित प्रत्येक विषय की स्थिति में प्रश्न-पत्र तीन घण्टे का होगा।

(2) प्रत्येक विषय में परीक्षा का स्तर और क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :-

अनुभाग-क - (अनिवार्य विषय)

1. सामान्य हिन्दी और निबन्ध

प्रश्न-पत्र हाई स्कूल स्तर का होगा।

2- सामान्य ज्ञान (जिसके अन्तर्गत साधारण विज्ञान भी है)

इसमें साम्प्रतिक घटनाओं के और प्रतिदिन के सम्पर्क और अनुभव के ऐसे विषयों का ज्ञान सम्मिलित है जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से बिना किसी विशेष अध्ययन के आशा की जाती है। प्रश्न साधारणतया ऐसे होंगे जिनके संक्षिप्त उत्तर दिये जा सकें और लोक प्रचलित विज्ञान के अतिरिक्त वर्तमान सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक घटनाओं के ज्ञान से सम्बन्धित होंगे।

3- प्रारम्भिक गणित

यह प्रश्न-पत्र हाई स्कूल स्तर का होगा।

अनुभाग ख (वैकल्पिक विषय)

4- सामान्य भारतीय इतिहास-

ज्ञान का न्यूनतम विषय क्षेत्र ऐसा होगा जिसके स्तर की योग्यता किसी बी० ए० उत्तीर्ण छात्र की होनी चाहिए जिसे भारतीय इतिहास के भिन्न-भिन्न काल के और विशेष रूप से अकबर के शासन काल से लेकर वर्तमान समय के मुख्य पहलुओं और प्रमुख घटनाओं की अच्छी जानकारी हो।

5- सामान्य भूगोल

ज्ञान का न्यूनतम विषय क्षेत्र ऐसा होगा जिसके स्तर की योग्यता किसी बी० ए० उत्तीर्ण छात्र की होनी चाहिए। प्रश्न-पत्र में विश्व भूगोल के प्रश्न और भू-आकृति विज्ञान के प्रश्न होंगे। इनमें से एक प्रश्न में नक्शा बनाने की अपेक्षा की जायेगी।

6- भौतिक विज्ञान

प्रश्न-पत्र का विषय क्षेत्र ऐसा होगा जिसके स्तर की योग्यता किसी बी० एस-सी० उत्तीर्ण छात्र की होनी चाहिए।

7- रसायन विज्ञान

प्रश्न-पत्र का विषय क्षेत्र ऐसा होगा जिसके स्तर की योग्यता एक बी० एस-सी० उत्तीर्ण छात्र की होनी चाहिए।

8- अर्थशास्त्र

प्रश्न-पत्र का विषय क्षेत्र ऐसा होगा जिसके स्तर की योग्यता एक बी० ए० उत्तीर्ण छात्र की होनी चाहिए :

9- समाज शास्त्र

समाज शास्त्र (सामाजिक पद्धति) के सिद्धान्त, भारतीय सामाजिक पद्धति, समाज-शास्त्र (सामाजिक नियन्त्रण और सामाजिक परिवर्तन) के सिद्धान्त, व्यवहारिक समाज शास्त्र।

10- बही-खाता लेखा-शास्त्र

प्रश्न-पत्र का विषय क्षेत्र ऐसा होगा जिसके स्तर की योग्यता किसी वाणिज्य स्नातक की होनी चाहिए।

11- वनस्पति विज्ञान

प्रश्न-पत्र बी० एस-सी० स्तर का होगा। इसमें आकृति विज्ञान क्रिया विज्ञान और आवृतबीज (एजियोस्पर्मस) का जीवन वृत्त, सामान्य पादप, क्रिया विज्ञान, क्रम विकास, विभिन्नता और अनुवर्षिकता, आर्थिक वनस्पति विज्ञान के प्रश्न होंगे।

12- प्राणि विज्ञान

प्रश्न-पत्र बी० एस-सी० स्तर का होगा। इसके अन्तर्गत नान कार्डेट, प्रारम्भिक तथ्य, और भ्रूण विज्ञान, क्रिया विज्ञान भू-वैज्ञानिक और भौगोलिक वितरण के प्रश्न होंगे।

13- अवर गणित

प्रश्न-पत्र बी० एस-सी० का स्तर होगा और इसके अन्तर्गत बीज गणित, त्रिकोणमिति, दो आयाम की वैश्लेषिक ज्यामिति, अवकलन गणित, समाकलन गणित, अवकल समीकरण, स्थैतिकी, गति विज्ञान, द्रव-स्थिति-विज्ञान और भूगोल विज्ञान होंगे।

14- विधि

संविधान विधि (भारतीय और ब्रिटिश दोनों), न्याय शास्त्र, अपकृत्य (टार्ट), भारतीय संविदा विधि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता।

15- कृषि

प्रश्न-पत्र कृषि में बी० एस-सी० (उत्तीर्ण) स्तर का होगा। इसमें कृषि, अर्थशास्त्र और फार्म प्रबन्ध, कृषि अभियांत्रिकी, फार्म फसल और कृषि रसायन और जैव विज्ञान होंगे।

16- राजनीति शास्त्र

प्रश्न-पत्र का विषय क्षेत्र ऐसा होगा जिसके स्तर की योग्यता किसी बी० ए० उत्तीर्ण छात्र की होनी चाहिए।

17- मनोविज्ञान

प्रश्न-पत्र स्नातक स्तर का होगा।

18- सांख्यिकी

प्रश्न-पत्र स्नातक स्तर का होगा।

19- रसायनिक अभियांत्रिकी

प्रश्न-पत्र स्नातक स्तर का होगा।

20- संस्कृत साहित्य

अभ्यर्थियों से प्रमुख अभिजात लेखकों के विशेष सन्दर्भ में अभिजात संस्कृत साहित्य के इतिहास और नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत के सामान्य ज्ञान की आशा की जायगी। संस्कृत से अंग्रेजी और अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए गद्यांश भी दिये जा सकते हैं। जिन उत्तरों की संस्कृत में लिखने की अपेक्षा की जायगी उन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जायगा।

21- हिन्दी साहित्य

अभ्यर्थियों से हिन्दी की मानक रचनाओं के ज्ञान की आशा की जायगी यद्यपि अपेक्षाकृत कम महत्व की पुस्तकों पर भी प्रश्न दिये जा सकते हैं। उनसे साहित्य के इतिहास का ज्ञान और सामान्य सामाजिक इतिहास ऐसे ज्ञान की भी आशा की जायगी जिससे वे साहित्य को समझ सकें। प्रश्नों के उत्तर देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में लिखे जाने चाहिए।

22- उर्दू साहित्य

अभ्यर्थियों से उर्दू की सुप्रसिद्ध पुस्तकों के ज्ञान की आशा की जायगी यद्यपि अपेक्षाकृत महत्व की रचनाओं पर भी प्रश्न दिये जा सकते हैं। उससे साहित्य के इतिहास का ज्ञान और सामान्य सामाजिक इतिहास के ऐसे ज्ञान की भी आशा की जायगी जिससे वे साहित्य को समझ सकें। प्रश्नों के उत्तर उर्दू में लिखे जाने चाहिए।

23- अंग्रेजी साहित्य

अभ्यर्थियों से स्पेन्सर के समय से 1930 तक अंग्रेजी साहित्य के इतिहास के सामान्य ज्ञान की आशा की जायगी जिसमें निम्नलिखित लेखकों की रचना का विशेष सन्दर्भ होगा :

शेक्सपियर, मिल्टन, जानसन, डिकेन्स, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कार्लाइल, टेनीसन, हार्डी और वर्नाडिशा।

24- राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा

इस प्रश्न-पत्र में समान्यतया बड़ी शक्तियों की और विस्तृत रूप में भारत की रक्षा और सुरक्षा समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्न होंगे :

(1) राष्ट्रीय रक्षा की आवश्यक बातें -

- (क) भौतिक तत्व-स्थल विवरण, सीमावर्ती भू-भाग,
- (ख) आर्थिक तत्व, संसाधन औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास परिवहन और संचार व्यवस्था,
- (ग) आन्तरिक राजनैतिक स्थिति,
- (घ) आधुनिक राज्य की रक्षा-यन्त्र विन्यास,

(2) आधुनिक प्रवृत्तियाँ -

- (क) रक्षा और सैनिक सन्धियाँ,
- (ख) तटस्थता और गुट निरपेक्षता,
- (ग) निरस्त्रीकरण और विश्व शान्ति संगठन।

(3) भारत की रक्षा और सुरक्षा-

- (क) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और समस्याएँ,
- (ख) स्वतन्त्र भारत की रक्षा समस्या-
- (एक) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के सन्दर्भ में भारत की विदेश नीति और पड़ोसी राष्ट्रों से उसके सम्बन्ध,
- (दो) भारत के सामयिक महत्व के स्थल और सीमावर्ती क्षेत्र
- (तीन) भारत की आर्थिक शक्ति,
- (चार) भारत का रक्षा संगठन।

अनुभाग-ग - (व्यक्तित्व परीक्षा-मौखिक)

25. परीक्षा सामान्य रुचि के विषयों में होगी और शैक्षिक रुचि के विषयों में नहीं होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व, सम्बोधन, चरित्र, शारीरिक गठन और सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता के लिए अंक दिये जायेंगे। कोई भी ऐसा उपर्युक्त प्रश्न पूछा जा सकता है जो इन विषयों पर प्रकाश डालता हो।

CHAPTER XX

The Uttar Pradesh Consolidation Department Ministerial and Drawing Staff Service Rules, 1980¹

1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Consolidation Department Ministerial and Drawing Staff Service Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the service :- The Uttar Pradesh Consolidation Department Ministerial and Drawing Staff Service comprises Group 'C' posts.

3. Definitions :- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

- (a) "Act" means the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 (U. P. Act No. V of 1954), as amended from time to time;
- (b) "appointing authority" in respect of the posts at the headquarters means, the senior-most Joint Director (Headquarters) and in respect of the posts of the subordinate offices means,-
 - (1) the Joint Directors Consolidation, posted in a region, in respect of the posts of their offices.
 - (2) the Deputy Directors Consolidation, in respect of the posts of their offices, and
 - (3) the Settlement Officers, Consolidation, in respect of the posts of their offices and the offices of Consolidation Officers and Assistant Consolidation Officers under them;
- (c) "Citizen" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
- (d) "Constitution" means the Constitution of India,
- (e) "Consolidation Officer" means the Officer defined in Section 3 (3) of the Act;
- (f) "Department" means the Consolidation Department of the Uttar Pradesh Government;
- (g) "Deputy Director" includes District Deputy Director of Consolidation;
- (h) "Director" means the Director of Consolidation, Uttar Pradesh;
- (i) "Drawing Staff" in relation to the service means the Draftsmen and Tracers;
- (j) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;
- (k) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
- (l) "Headquarters" means the office of the Director of Consolidation in Lucknow;
- (m) "Member of the service" means a person appointed in a substantive capacity under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the service;
- (n) "Settlement Officer" means Settlement Officer, as defined in Sections 3 (9) of the Act;
- (o) "Service" means the Uttar Pradesh Consolidation Department Ministerial and Drawing Staff Service; and

¹ Substituted by Notification No. 54/3-75-475-Ra 8, dated 24/9/1980, Published in U. P. Gazette, Part I-Ka dated 17/1/1981.

- (p) "Year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part II - Cadre

4. Cadre of service :- (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in Appendix I :

Provided that -

(1) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation.

(2) the Governor may create such additional, permanent or temporary posts from time to time, as he may consider proper.

Note :- For the posts of Stenographers, there shall be a combined cadre for the Headquarter and other subordinate offices and for any other post in the Service, there shall be two separate cadres, one for the Headquarters and the other for other subordinate offices.

Part III - Recruitment

5. Source of recruitment :- (1) Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :

(A) Headquarters :

(1) Lower Division Assistant.

(2) Lower Division Clerk.

(3) Routine Clerk (Scale of pay Rs. 200-320).

(4) Junior Accounts Clerk.

(5) Ahalmad.

(6) Typist.

(7) Stenographer (Scale of pay Rs. 250-425).

(8) Stenographer (Scale of pay Rs. 300-500).

By direct recruitment in accordance with the provisions of the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975.

By direct Recruitment.

By promotion amongst the permanent Stenographers in the scale of pay Rs. 250-425 at the Headquarters and Subordinate Offices.

Note :- For the purpose of promotion, a combined seniority list shall be prepared by arranging the names of eligible persons in order of their seniority as determined in accordance with the principles laid down in Rule 21. So, however, that the *inter se* seniority is not disturbed.

(9) Superintendent

By promotion from amongst the permanent Assistant Superintendents and Permanent Chief Accountants.

(10) Assistant Superintendent and Chief Accountant

By promotion from amongst the permanent Upper Division Assistants and Record Keepers.

U. P. Consolidation Deptt. Ministerial and Drawing Staff Service Rules, 1980 143

- | | |
|--|---|
| (11) Upper Division Assistant and Record Keepers | By promotion from amongst the permanent Readers, Assistant Record Keepers, Routine Clerks (Scale of pay Rs. 230-380), Accountant, Senior Accounts Clerk, Nazir and Librarian. |
| (12) Assistant Record Keeper, Routine Clerk (scale of pay Rs. 230-380) Nazir, Senior Accounts Clerk, Librarian, Accountant and Reader. | By promotion from amongst the permanent Lower Division Assistant, Lower Division Clerks, Typist, Junior Accounts Clerk, Routine Clerks and Ahalmads : |

Provided that if sufficient number of suitable eligible persons are not available for promotion, the vacancies remaining unfilled after selection from Headquarters establishment may be filled from amongst the permanent Readers, Ahalmads, Court Clerks, Record Keepers, Typists and Tabulators of establishment of subordinate offices.

(B) Subordinate Offices :

- | | |
|---|---|
| (1) Reader | By direct recruitment in accordance with the provisions of the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975. |
| (2) Ahalmad | |
| (3) Record Keeper | |
| (4) Court Clerk | |
| (5) Typist | |
| (6) Tabulator | |
| (7) Head Assistant | By promotion from amongst the permanent Correspondence Clerks. |
| (8) Stenographer (Scale of pay Rs. 250-125). | By direct recruitment. |
| (9) Correspondence Clerk, Account Clerk and Senior Clerk. | By promotion from amongst the permanent Readers, Ahalmads, Court Clerks, Record Keepers, Typists and Tabulators. |
| (10) Tracer | By direct recruitment. |
| (11) Draftsman (Unqualified) | By promotion from amongst the permanent Tracers. |
| (12) Draftsman (Qualified) | By promotion from amongst the permanent Tracers provided that if no suitable candidates are available for promotion the vacancies may be filled up by direct recruitment. |

Note :- For the purposes of recruitment by promotion, combined seniority list of the eligible candidates shall be prepared by arranging the names of the eligible persons in order of their seniority as determined in accordance with the provision of Rule 21, so however, that the *inter se* seniority of the persons in different categories shall not be disturbed.

6. **Reservation :-** Reservations for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Part IV - Qualifications

7. Nationality :- A candidate for direct recruitment to a post in the service must be-

- (a) a citizen of India; or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, U. P. :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note :- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic qualifications :- (1) A candidate for direct recruitment to the posts to which recruitment is to be made in accordance with the Sub-ordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975, must possess the qualification as prescribed in the said rules.

(2) A candidate for direct recruitment to the post of Stenographer must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto. He must also possess a minimum speed of 80 words per minute and 30 words per minute in Hindi Shorthand and typing, respectively.

(3) A candidate for direct recruitment to the post of Tracer must have passed atleast the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto with drawing as one of the subjects.

(4) A candidate for direct recruitment to the posts of Draftsman (qualified) must possess a diploma in Draftsmanship from an institution recognised by the Government.

9. Preferential qualifications :- A candidate who has-

- (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
- (ii) obtained a 'B' Certificate of the National Cadet Corps,

shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10. (1) A candidate for direct recruitment to the posts, to which recruitment is to be made in accordance with the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975, must be within the age-limits laid down in the said rules.

U. P. Consolidation Deptt. Ministerial and Drawing Staff Service Rules, 1980 145

(2) A candidate for direct recruitment to the post of Tracer must have attained the age of 18 years and a candidate for direct recruitment to the post of Stenographer and Draftsman (qualified) must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 28 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January 1 to June 30, and on July 1, if the posts are advertised during the period July 1 to December 31 :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

11. Character :- The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note :- Persons dismissed by the Union Government or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital status :- A male candidate who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical fitness :- No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 and contained in Chapter III of the Financial Hand book, Volume II, Part III :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part V - Procedure for Recruitment

14. Determination of vacancies :- The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule 6. He shall intimate the vacancies to be filled by direct recruitment to the employment exchange in accordance with the rules and orders for the time being in force.

15. Procedure for direct recruitment to the posts of Lower Division Assistant, Lower Division Clerk, Routine Clerk (Rs. 200-320), Junior Accounts Clerk, Ahalmad, Typist at the Headquarters and Reader, Ahalmad, Record Keeper, Court Clerk, Typist and Tabulator in the Subordinate Offices :- Recruitment to the posts shall be made in accordance with the procedure laid down in the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975 as amended from time to time.

Note :- A copy of the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975 is attached as (Appendix II Not printed)

16. Procedure for direct recruitment to the posts of Stenographer and Tracer:- (1) For the purpose of recruitment, to the posts of Stenographers and Tracers, there shall be constituted Selection Committees as follows :

(a) *Stenographers :*

1. District Magistrate/District Deputy Director, Consolidation.
2. Regional Deputy Director, Consolidation, nominated by Consolidation Commissioner.
3. Settlement Officer Consolidation, nominated by Consolidation Commissioner.

(b) *Tracer :*

1. Regional Deputy Director, nominated by District Magistrate/Deputy Director Consolidation.
2. Settlement Officer, Consolidation, nominated by District Magistrate/District Deputy Director, Consolidation.
3. Sub-Divisional Magistrate, nominated by District Magistrate District Deputy Director of Consolidation.

(2) The Selection Committee shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in a competitive examination and in an interview.

(3) After the marks obtained by the candidates in the written test have been tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with Rule 6, call for interview such number of candidates as, on the result of the written examination have come up to the standard fixed by the Committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written test.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of merit, as disclosed by aggregate of marks obtained by them in the written test and interview. If two or more candidates obtain equal marks, the candidates obtaining higher marks in the written test shall be placed higher. The number of the names in the list shall be larger but not larger by more than 25 per cent of the vacancies. The list shall be forwarded to the appointing authority.

17. Procedure for recruitment by promotion :- (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit through a Selection Committee, comprising-

- (a) Senior-most Joint Director, Consolidation at the headquarters.
- (b) One of the Deputy Directors at the headquarters nominated by the Consolidation Commissioner.
- (c) District Deputy Director of Consolidation nominated by the Consolidation Commissioner.

Note :- In nominating the Officer, the Appointing Authority/Consolidation Commissioner shall keep in view the orders of the Government contained in G. O. No. 15/25/75-Rashtriya Ekikaran, dated May 10, 1976 or such other orders as may be in force at the time of recruitment.

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidate arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with the character rolls and such other record, pertaining to them as may be considered proper.

U. P. Consolidation Deptt. Ministerial and Drawing Staff Service Rules, 1980 147

3. The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in sub-rule (2) and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

4. The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to Appointing Authority.

Part VI - Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

18. Appointment :- (1) On the occurrence of substantive vacancies, the appointing authority shall make appointment by taking candidates in the order in which they stand in the list, prepared under Rule 15, 16 or 17 as the case may be.

(2) The appointing authority may make appointments in temporary and officiating vacancies also from the lists referred to in sub-rule (1). If the list of candidates is exhausted or no candidate is available for appointment from the list of selected candidates the concerned appointing authority may make appointments in such vacancies from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such an appointment will not last for a period exceeding six months.

19. Probation :- (1) A person on appointment to a post in the service in or against substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended for more than one year and in no case beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

20. Confirmation :- A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-

(a) his work and conduct are found to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

21. Seniority :- Seniority in any category of posts in the Service shall be determined from the date of order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, from the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that-

(1) The *inter se* seniority of persons directly appointed to the Service shall be same as determined at the time of selection, and

(2) the *inter se* seniority of persons appointed to the Service by promotion shall be the same as it was in the substantive post held by them at the time of promotion.

Note :- (1) A candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reason when a vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of the reason will be final.

(2) Where the appointment order specifies an earlier date with effect from which a person is appointed substantively that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment. In other cases, it will mean the date of issue of the order.

Part VII - Pay, etc.

22. Scale of pay :- (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given in Appendix I.

23. Pay during probation :- (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government service shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed and second increment after two years services when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

24. Criteria for crossing efficiency bar :- (1) No Superintendent shall be allowed to cross the efficiency bar unless he has worked diligently and to the best of his ability, his work and conduct are found to be satisfactory, his control and supervision over the staff is found to be adequate and his integrity is certified.

(2) A person not covered by sub-rule (1) shall not be allowed to cross-

(1) the first efficiency bar unless his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified,

(2) the second efficiency bar unless his work and conduct are found to be satisfactory, he is found to have worked with distinct ability and initiative and unless his integrity is certified.

25. Canvassing :- No recommendations either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post in the service will be taken into consideration, any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

26. Regulation of other matters :- In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special order, persons appointed to the service shall be

U. P. Consolidation Deptt. Ministerial and Drawing Staff Service Rules, 1980 149

governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

27. Relaxation from the conditions of service :- Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes under hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

28. Saving :- Nothing in these rules will affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

Appendix 1

A- Headquarters Establishment

Serial No.	Name of post	Scale of pay	Number of posts		
			Permanent	Temporary	Total
1	2	3	4	5	6
		Rs.			
1.	Superintendent	450-25-575-E.B.-25-700	1	..	1
2.	Assistant Superintendent	800-8-340-E.B.-10-440-E.B.-12-500	2	1	3
3.	Chief Accountant	..	1	..	1
4.	Stenographer	..	5	46	51
5.	Record Keeper	280-8-320-E.B.-9-410-E.B.-10-450	1	..	1
6.	Upper Division Assistant	..	8	7	15
7.	Stenographer	250-7-285-E.B.-9-375-E.B.-10-425	1	5	6
8.	Reader	230-6-290-E.B.-8-330-E.B.-10-380	..	34	34
9.	Routiner Clerk	..	2	1	3
10.	Accountant	..	1	..	1
11.	Senior Accounts Clerk	..	4	3	7
12.	Assistant Record Keeper	..	1	..	1
13.	Nazir	..	..	1	1
14.	Librarian	..	..	1	1
15.	Lower Division Assistant	200-5-250-E.B.-6-280-E.B.-8-320	4	6	10
16.	Lower Division Clerk	..	..	1	1

150 Revenue Service Rules in U. P.

17. Typist	4	3	7
18. Junior Accounts Clerk	2	..	2
19. Routine Clerk	2	..	2
20. Ahalmad	..	10	10

B- District Establishment

Serial No.	Name of post	Scale of pay	Number of posts		
			Perma- nent	Tempo- rary	Total
1	2	3 Rs.	4	5	6
1.	Head Assistant	280-8-320-E.B.-9-410- E. B.-10-450	41	42	83
2.	Draftsman- (1) Qualified (2) Unqualified	200-5-250-E.B.-6-280- E.B.-8-320	113	100	213
3.	Stenographer	250-7-285-E.B.-9-375- E.B.-10-425	22	61	83
4.	Correspondence Clerk	230-6-290-E.B.-8-330- E.B.-10-380	25	17	42
5.	Accounts Clerk	..	53	31	84
6.	Senior Clerk	..	21	..	21
7.	Reader	200-5-250-E.B.-6-280- E.B.-8-320	33	195	228
8.	Ahalmad	..	33	195	228
9.	Court Clerk	..	175	522	697
10.	Record Keeper	..	11	31	42
11.	Typist	..	..	33	33
12.	Sarnikar	200-5-250-E.B.-6-280- E.B.-8-320	..	64	64
13.	Anurekhak	185-3-215-E.B.-4-235- E.B.-265	206	194	397

Note :- The orders in force at the time of commencement of these rules are contained in G. O. No. 37/169, Appointment (B), dated January 1, 1970. (Annexure 'A').

Appendix II

Not Printed
